भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

का

निष्कर्ष बजट

2008-2009

निष्पादन सारांश

इस्पात मंत्रालय के निष्पादन बजट का उद्देश्य मंत्रालय की विशिष्ट भूमिका और उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तैयार किए गए कार्यक्रमों, परियोजनाओं और गतिविधियों तथा इस्पात मंत्रालय तथा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के निष्कर्ष पर प्रकाश डालना है। इस दस्तावेज में वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए नियत लक्ष्यों और वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए अनुमानों का विवरण भी दिया गया है।

अध्याय- I *में इस्पात मंत्रालय के संगठनात्मक ढांचे और उद्देश्यों, मुख्य कार्यक्रमों के वर्गीकरण और इनसे सम्बद्ध कार्यान्वयन एजेंसियों की विस्तृत जानकारी दी गई है।*

अध्याय- II*में मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में परिव्यय तथा निष्कर्षों/लक्ष्यों का विवरण तालिकाओं के रूप में दिया गया है। चूंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की योजनाएं/परियोजनाएं बहुत अधिक हैं तथा प्रकृति में भिन्न-भिन्न हैं और अधिकांशत: उनके दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों से संबंधित हैं, अत: 50 करोड़ रूपए और इससे अधिक अनुमानित/मंजूर लागत वाली केवल प्रमुख योजनाओं को ही इस विवरण में शामिल किया गया है। वर्ष 2008-09 के लिए ऐसी 53 प्रमुख योजनाओं, जिनमें 52 योजनागत योजनाएं तथा 1 गैर-योजनागत योजना शामिल है, को निष्कर्ष बजट में शामिल किया गया है। इन 52 योजनागत योजनाओं को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (30 योजनाएं), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (11 योजनाएं), कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (5 योजनाएं) और एनएमडीसी लि. (4 योजनाएं) और मॉयल इंडिया लि. (1 योजना) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और इन योजनाओं पर होने वाले पूरे व्यय की पूर्ति संबंधित उपक्रमों के आंतरिक तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आई एंड ईबीआर) से की जाएगी। अनुसंधान एवं विकास हेतु 1 योजना को इस्पात मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। एक मात्र प्रमुख गैर-योजनागत योजना हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु कंपनी द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए ऋणों हेतु ब्याज इमदाद उपलब्ध करवाने के लिए है। इन 53 प्रमुख योजनाओं के संबंध में अनुमानित/मंजूर लागत, वर्ष 2008-09 के लिए परिव्यय, प्रक्रियाओं/ टाइमलाइन्स,*

जोखिम घटकों, अनुमानित वास्तविक उत्पादन तथा अनुमानित निष्कर्ष इस विवरण में दिए गए हैं।

<u>अध्याय- III</u> *में इस्पात मंत्रालय द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों और नीतिपरक पहलों का विवरण दिया गया है। इस अध्याय में सरकार द्वारा भारतीय लोहा और इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए उदारीकरण के बाद किए गए महत्वपूर्ण नीतिपरक उपायों का ब्यौरा दिया गया है। इस संबंध में इस्पात मंत्रालय द्वारा की गई एक महत्वूपर्ण नीतिपरक पहल राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2005 की घोषणा है। राष्ट्रीय इस्पात नीति का दीर्घकालिक लक्ष्य घरेलू इस्पात उद्योग को विविधीकृत इस्पात मांग को पूरा करने वाला विश्वस्तरीय मानकों का आधुनिक तथा क्षमतावान इस्पात उद्योग बनाना है। इस नीति में न केवल लागत, गुणवत्ता तथा उत्पाद मिश्र की दृष्टि से अपितु दक्षता तथा उत्पादकता के वैश्विक मानकों की दृष्टि से भी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय इस्पात नीति में वर्ष 2019-2020 तक 110 मिलियन टन वार्षिक इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस्पात उद्योग के निष्पादन की समीक्षा करने, प्रमुख क्षेत्रगत नीतिपरक मुद्दों तथा सरोकारों पर विचार करने, 11वीं योजना के दौरान मांग तथा आपूर्ति संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने तथा कार्यान्वयन के लिए नीतिपरक सिफारिशें करने के लिए मई, 2006 में योजना आयोग द्वारा लोहा और इस्पात उद्योग से संबंधित एक कार्य दल का गठन किया गया था। कार्य दल ने मांग तथा आपूर्ति संबंधी प्रबंधन, प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण तथा प्रदूषण नियंत्रण, मूल्य स्थिरता तथा सुरक्षा उपायों जैसे प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में सिफारिशें करते हुए अपनी रिपोर्ट दिसंबर, 2006 में योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है। इस अध्याय में उन सिफारिशों तथा उन प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है जिनके संबंध में भारत को लोहा और इस्पात क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए सहायक उपाय किए जाने/नीतियां बनाएं जाने की जरूरत है।*

<u>अध्याय- IV</u> *में इस्पात मंत्रालय के निष्कर्ष बजट, 2007-08 में दर्शाए गए अनुमानित निष्कर्षों/लक्ष्यों के संबंध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की 50 करोड़ रूपए अथवा इससे अधिक की अनुमानित/मंजूर लागत वाली प्रमुख योजनाओं तथा परियोजनाओं के निष्पादन की समीक्षा की गई*

है। निष्कर्ष बजट 2007-08 में शामिल 32 प्रमुख योजनाओं-31 योजनागत योजनाओं तथा एक गैर-योजनागत योजना के संबंध में 2007-08 की तीसरी तिमाही (31 दिसंबर, 2007 तक) तक का निष्पादन अनुमोदित परिव्यय तथा अनुमानित निष्कर्षों की तुलना में किए गए वास्तविक व्यय और योजनाओं की वास्तविक उपलब्धियों को देखते हुए दर्शाया गया है। 31 प्रमुख योजनागत योजनाएं सेल, आरआईएनएल, एनएमडीसी और केआईओसीएल से संबंधित हैं तथा एक मात्र गैर-योजनागत योजना एचएससीएल की है। सेल की 17 योजनाओं में से 7 योजनाएं पूरी कर ली गईं हैं। चूंकि अधिकांश प्रमुख योजनाएं इस समय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, अत: वास्तविक उपलब्धियों का अपेक्षाकृत अधिक सार्थक और वास्तविक मूल्यांकन इन योजनाओं के पूर्ण होने के बाद ही संभव होगा।

अध्याय-V *में इस्पात मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/संगठनों के वित्तीय परिव्यय तथा वित्तीय आवश्यकताओं का ब्यौरा दिया गया है। बजट अनुमान 2007-08 में 150.50 करोड़ रूपए तथा संशोधित अनुमान 2007-08 में 154.05 करोड़ रूपए के बजटीय प्रावधान की तुलना में बजट अनुमान 2008-09 में इस्पात मंत्रालय के लिए मांग संख्या-91 के तहत 119.52 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बजट अनुमान 2007-08 में मंत्रालय के 6203.70 करोड़ रूपए के वार्षिक योजना परिव्यय (आई एंड ईबीआर: 6137.70 करोड़ रूपए तथा योजना बजटीय सहायता: 66.00 करोड़ रूपए) को बढ़ाकर बजट अनुमान 2008-09 में 9543.00 करोड़ रूपए (आई एंड ईबीआर: 9509.00 करोड़ रूपए तथा योजना बजटीय सहायता: 34.00 करोड़ रूपए) कर दिया गया है। योजना परिव्यय में काफी बढ़ोतरी मुख्यत: आरआईएनएल के वाईजैग इस्पात संयंत्र के क्षमता विस्तार हेतु 3000 करोड़ रूपए के परिव्यय के कारण की गई है। चालू वर्ष सहित हाल ही के वर्षों में बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में व्यय के समग्र रुख के संबंध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों तथा उनके पास व्यय नहीं किए गए शेष की स्थिति भी इस अध्याय में दर्शाई गई है। इस्पात मंत्रालय की अनुदान मांगों में शामिल प्रावधानों को संबद्ध करते हुए इस अध्याय में वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए इस्पात मंत्रालय की अनुदान मांग की अनुपूरक जानकारी भी दी गई है।*

अध्याय - VI *में इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पिछले 3 वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 (दिसंबर, 2007 तक) के वास्तविक तथा वित्तीय निष्पादन और 2008-09 (बजट अनुमान) के लिए अनुमानों से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई गई है।*

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रमुख योजनाओं/परियोजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था अधिकांशत: उनके आंतरिक तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आई एंड ईबीआर) से की जा रही है और संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आंतरिक तकनीकी समिति द्वारा इनका वास्तविक और वित्तीय तौर पर नियमित रूप से प्रबोधन किया जा रहा है। निदेशक मंडल द्वारा इन योजनाओं/परियोजनाओं की आवधिक रूप से समीक्षा के अलावा मंत्रालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर इनकी प्रगति की समीक्षा की जाती है। प्रबोधन तथा मूल्यांकन तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए है कि योजनाओं/परियोजनाओं के पूरा होने पर उनकी वास्तविक उपलब्धियां निष्कर्ष बजट 2008-09 में अनुमानित निष्कर्षों से मेल खाती हों।

****

अध्याय-I

प्रस्तावना

1. उद्देश्य

इस्पात मंत्रालय के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

(क) लोहा और इस्पात तथा फैरो-मिश्र के उत्पादन, वितरण, मूल्य, आयात और निर्यात से संबंधित नीतियां बनाना;

(ख) लोहा और इस्पात उत्पादन सुविधाओं की आयोजना, विकास और इनकी स्थापना को सुसाध्य बनाना

(ग) सरकारी क्षेत्र में लौह अयस्क खानों तथा लोहा और इस्पात उद्योग के उपयोग में आने वाली अन्य लौह अयस्क खानों का विकास; और

(घ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और इसकी सहायक कंपनियां तथा लोहा और इस्पात क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों/सरकार द्वारा प्रबंधित कंपनियों के निष्पादन का प्रबोधन करना।

2. कार्यक्रम

2.1 इस्पात मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रम/उप-कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:-

(i) खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग - लोहा और इस्पात उद्योग

(क) उत्पादन, आयात और निर्यात;
(ख) टैरिफ तथा मूल्य निर्धारण;
(ग) अनुसंधान तथा प्रशिक्षण;
(घ) निर्माण कार्य; और
(ड.) तकनीकी तथा परामर्शी सेवाएं

(ii) खान और खनिज:

(क) लौह अयस्क;
(ख) मैंगनीज अयस्क; और

(ग) क्रोमाइट अयस्क

2.2 इस्पात मंत्रालय - इस्पात उद्योग के विकास के लिए सहायक

इस्पात मंत्रालय से इस्पात क्षेत्र के सुव्यवस्थित एवं एकीकृत उत्थान के लिए अहम भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है। महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण, 11वीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के स्तर को प्राप्त करने के लिए इस्पात क्षेत्र का सतत् उत्थान पूर्वापेक्षित है। तथापि, यह मानना होगा कि इस्पात जैसे उद्योग के साथ अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के अग्रगामी एवं पश्चगामी सम्बन्ध हैं अत: इसकी अपनी स्वयं की विकास पद्धति अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। कच्चे माल और ऊर्जा लागत की बढ़ती हुई कीमतें इस्पात क्षेत्र की कई कम्पनियों के तुलन-पत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। इस क्षेत्र में निजी निवेश के सतत् स्तर को भी बनाए रखने की आवश्यकता है। यह अच्छी बात है कि इस्पात क्षेत्र जिस माहौल में प्रचालन करता है उसमें इस्पात मंत्रालय द्वारा एक प्रोत्साहक की भूमिका निभाने की जरूरत है। इस्पात मंत्रालय से एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है ताकि भारतीय इस्पात क्षेत्र के विकास में आने वाली अड़चनों को यह दूर कर सके तथा यह अनेक प्रकार से इस उद्योग की सहायता कर सके जैसे कि कच्चे माल की उपलब्धता, अवसंरचना विकास, अपेक्षित पूंजी उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थाओं से सतत् आधार पर बातचीत करना और उपयुक्त नीतिपरक कार्रवाई करने में सरकार के अन्य संबंधित मंत्रालयों और विभागों की सहायता करना और उन्हें परामर्श देना ।

3. संगठन

इस्पात मंत्रालय के प्रभारी एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री हैं। इनकी सहायता के लिए एक सचिव, भारत सरकार, एक अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, भारत सरकार, एक मुख्य लेखा नियंत्रक, तीन संयुक्त सचिव, एक आर्थिक सलाहकार, पांच निदेशक, चार उप सचिव (28.2.2007 की स्थिति के अनुसार) तथा अन्य अधिकारी एवं सहायक कर्मचारी । लोहा और इस्पात उद्योग से संबंधित मामलों को तकनीकी दृष्टि से देखने के लिए एक तकनीकी स्कंध है जिसके प्रभारी औद्योगिक सलाहकार हैं, जो भारत सरकार के वरिष्ठ निदेशक स्तर के हैं। इनकी सहायता के लिए एक अपर औद्योगिक सलाहकार, एक संयुक्त औद्योगिक सलाहकार एवं अन्य सहायक कर्मचारी हैं।

इस्पात मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय नामत: विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात का कार्यालय था, जो कोलकत्ता में स्थित था। व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर विकास आयुक्त लोहा और इस्पात का कार्यालय तथा इसके चार क्षेत्रीय कार्यालयों को दिनांक 25.3.2003 से बंद करने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया था। इस कार्यालय को बंद करने के परिणामस्वरूप विकास आयुक्त लोहा ओर इस्पात के 226 कर्मचारियों में से 223 कर्मचारी अधिशेष घोषित कर दिए गए और पुनर्तैनाती हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिशेष सैल

की नामावली में ले लिए गए। शेष तीन कम्रचारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अभी अधिशेष घोषित किए जाने हैं। आंकड़े संग्रहण का कार्य जो संयुक्त संयंत्र समिति (जे पी सी) को सौंपा गया है, को छोड़कर विकास आयुक्त लोहा और इस्पात के शेष कार्य मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं।

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कोई सांविधिक अथवा स्वायत्त निकाय नहीं है।

4. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी प्रबंधन की कंपनी

4.1 इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रम और सरकारी प्रबंधनाधीन कंपनी कार्य कर रहे हैं:-

1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), नई दिल्ली
2. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल), बंगलौर
3. एन एम डी सी लिमिटेड, हैदराबाद
4. हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल), कोलकाता
5. मेकान लिमिटेड, रांची
6. मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल), नागपुर
7. स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (सिल), हैदराबाद
8. भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड (बी आर एल), बोकारो
9. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल), विशाखापट्टनम
10. एम एस टी सी लिमिटेड, कोलकाता
11. फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल), भिलाई (एम एस टी सी लि. की सहायक कंपनी)

(1) स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के समग्र नियंत्रणाधीन निम्नलिखित इकाइयां हैं:-

1. बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो;
2. भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई;
3. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर;
4. राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला;
5. मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर;
5. सेलम इस्पात संयंत्र, सेलम;
6. इस्को स्टील प्लांट, बर्नपुर (पूर्व में सेल की एक सहायक कंपनी इस्को का 16.2.2006 को सेल में विलय हो गया और इसे इस्को स्टील प्लांट नाम दिया गया है)
7. विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात संयंत्र, भद्रावती

9. केन्द्रीय विपणन संगठन, कोलकाता;
10. लोहा और इस्पात अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, रांची;
11. कच्चा माल प्रभाग, कोलकाता;
12. इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, रांची; और
13. निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मैल्ट लिमिटेड (एमईएल) भी सेल की एक सहायक कंपनी है जिसमें सेल की 99.12 प्रतिशत शेयर पूंजी है। एमईएल का संयंत्र चंद्रपुर (महाराष्ट्र) में स्थित है और यह कंपनी फैरो मिश्र का उत्पादन करती है।

2. **कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (के आई ओ सी एल)** कर्नाटक राज्य में लौह अयस्क भण्डारों का विकास करने तथा उनसे उत्पादित लौह अयस्क सांद्रणों की बिक्री के लिए अप्रैल, 1976 में बनाई गई थी। यह पूर्णत: सरकारी कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय बंगलौर में है।

3. **एन एम डी सी लिमिटेड** लौह अयस्क के खनन और हीरे, चूना-पत्थर, डेालोमाइट, बेंटोनाइट आदि जैसे खनिजों के गवेषण/विकास कार्य में लगा हुआ है। इसका पंजीकृत कार्यालय हैदराबाद में है। इसके साथ-साथ भारत सरकार की ओर से मैसर्स मांडवी पैलेट्स लिमिटेड नामक कंपनी में भी इसकी भागीदारी है। यह कंपनी मैसर्स चोगुले एंड कंपनी के सहयोग से स्थापित संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है जो पैलेटों के निर्माण के लिए स्थापित की गयी है। जम्मू स्थित जे एंड के मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन नामक कंपनी एन एम डी सी लिमिटेड की सहायक कंपनी है।

4. **हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)** जिसका पंजीकृत कार्यालय कोलकत्ता में है, ने बोकारो, विजाग और सेलम जैसे इस्पात संयंत्रों की स्थापना और भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर (इस्को) आदि इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण से सम्बद्ध बड़े-बड़े निर्माण कार्य किए हैं। अब कंपनी ने उच्च श्रेणी की योजना समन्वय और अत्याधुनिक तकनीकों के साथ अवसंरचना क्षेत्रों में भी अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं। इस्पात संयंत्रों में निर्माण संबंधी कार्यकलापों में कमी के चलते कंपनी ने अपने कार्यकलापों का विद्युत, कोयला, तेल एवं गैस जैसे अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया है। इसके अलावा, कंपनी ने सड़क/राजमार्गों, पुलों, बांधों, भूमिगत संचार और परिवहन प्रणाली और उच्च स्तर की आयोजना वाले औद्योगिक तथा बस्ती परिसरों, समन्वय और आधुनिक तकनीकों आदि जैसे अवसंरचना क्षेत्रों में अपने कार्यकलापों का विविधीकरण किया है।

5. **मेकॉन लिमिटेड,** देश में पहला परामर्शी और इंजीनियरी संगठन है जिसे आई एस ओ: 9001 मान्यता प्राप्त है। यह कंपनी लोहा एवं इस्पात, रसायन, रिफाइनरीज तथा पैट्रो रसायनों, विद्युत, सड़क एवं राजमार्गों, रेलवे, जल प्रबंधन, पत्तन एवं बंदरगाह, गैस एवं तेल,

पाइपलाइनों, अलौह खनन, सामान्य इंजीनियरिंग, पर्यावरण इंजीनियरिंग तथा संबद्ध/विविधीकृत क्षेत्रों में व्यापक विदेशी अनुभव सहित अग्रणी बहुविधिक डिजाइन, इंजीनियरिंग, परामर्शी और कांट्रैक्टिंग संगठन है।

6. **भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड (बी आर एल) की** चार रिफ्रैक्ट्री इकाइयां हैं। इनमें से एक भण्डारीदह में, एक रामगढ़ में और एक इकाई भिलाई में है। यह कंपनी ब्रिक्स और मासेज का उत्पादन करती है और इनकी आपूर्ति मुख्यत: सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को करती है।

7. **मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल),** जिसका निगमित कार्यलय नागपुर में है, उच्च ग्रेड के मैंगनीज अयस्क का उत्पादक करने वाली सबसे बडी कंपनी है। इस्पात बनाने में प्रयुक्त होने वाले फैरो-मिश्र का उत्पादन करने के लिए मैंगनीज कच्चे माल के रूप में काम में लाया जाता है तथा डाईऑक्साइड अयस्क शुष्क बैटरियों के उत्पादन हेतु कच्चा माल है। भारत सरकार तथा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारें कंपनी की शेयरधारक हैं। भारत सरकार की शेयरधारिता 81.57% है। मॉयल ने 90 के दशक के दौरान कारोबार की मात्रा और लाभप्रदता में सुधार करने के लिए मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन में अपने कार्यकलापों का विविधीकरण किया है।

8. **स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (सिल),** प्रदर्शन स्पंज लौह संयंत्र के सफल प्रचालन के पश्चात् अस्तित्व में आया। यह भारत सरकार और आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार की भागीदारी तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की सहायता से ठोस अपचयन प्रक्रिया (सॉलिड रिडक्टेंट प्रोसेस) के आधार पर स्पंज लोहे का उत्पादन करने के लिए स्थापित किया गया है। सिल का पंजीकृत कार्यालय हैदराबाद में है।

9. **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)** का पंजीकृत कार्यालय विशाखापट्टणम में है। यह भारत में स्थापित प्रथम तटीय आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र है। 30 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के द्रव इस्पात के साथ इसे अगस्त, 1992 में चालू किया गया था।

10. **एम एस टी सी लिमिटेड** भारत सरकार का एक व्यावसायिक उपक्रम है। पहले यह लघु इस्पात संयंत्रों को वितरण के लिए इस्पात गलन स्क्रैप का आयात करने वाली माध्यम एजेंसी के रूप में नामित थी । इसका मुख्यालय कोलकात्ता में है। इस कंपनी का माध्यम एजेंसी का स्वरूप फरवरी, 1992 से समाप्त हो गया। अब यह अन्य निजी व्यावसायिक कंपनियों की तरह पूर्णत: स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में काम कर रही है। अब यह कंपनी ट्रेडिंग कार्यकलाप, ई-कॉमर्स, लौह तथा अलौह स्क्रैप का निपटान और सेल, आर आई एन एल आदि के एकीकृत इस्पात संयंत्रों में उत्पन्न होने वाले लौह स्क्रैप और अन्य गौण सामग्री और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है, में उत्पन्न होने वाले स्क्रैप और अधिशेष भंडार आदि का निपटान कार्य कर रही है।

11. **फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)** पहले एम एस टी सी और मै. हर्सको कारपोरेशन इंक, अमेरिका की एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी थी । अब एम एस टी सी द्वारा एम

एस हर्सको के धारित 40% साम्या शेयरों का अधिग्रहण करने के बाद यह एम एस टी सी की शत प्रतिशत सहायक कंपनी बन गई है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य सेल, आरआईएनएल और एनआईएनएल के सभी एकीकृत इस्पात संयंत्रों में स्लैग से स्क्रैप प्राप्त करना और आईआईएल तथा जेएसपीएल जैसे निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में प्रचालन करना भी है। कंपनी अग्रणी संगठनों में से एक है जो देश के धातुकर्मीय उद्योगों को विशेषज्ञतायुक्त सेवाएं उपलब्ध करवाती है।

4.2 सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त उपक्रमों के अतिरिक्त इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकारी प्रबंधन की एक कंपनी अर्थात बर्ड ग्रुप की कंपनियां, कोलकाता है। 25 अक्तूबर, 1980 से भारत सरकार द्वारा 21 कम्पनियों के शेयर जो पहले बर्ड एंड कम्पनी लिमिटेड के पास थे, का अधिग्रहण करने पर इस्पात उद्योग से संबंधित बर्ड ग्रुप की निम्नलिखित 7 कम्पनियां इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गई:-

1. उड़ीसा मिनरल डेवलमेंट कंपनी लिमिटेड (ओ एम डी सी);
2. बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बी एस एल सी);
3. करनपुरा डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (के डी सी एल);
4. स्कॉट एंड सैक्सबी लिमिटेड (एस एस एल), (के डी सी एल की सहायक कंपनी);
5. कुमारध्रुबी फायरक्ले एंड सिलिका वर्क्स लिमिटेड (के एफ एस डब्ल्यू);
6. बोरिया कोल कंपनी लिमिटेड; और
7. बुराकुर कोल कंपनी लिमिटेड

उपर्युक्त 7 कंपनियों में से तीन कंपनियां नामत: ओएमडीसी, बीएसएलसी और केडीसीएल खनन कंपनियां हैं। एसएसएल गहरे नलकूपों की खुदाई और खनिज गवेषण से संबंधित कार्यकलाप कर रही है। ईआईएल एक निवेश कंपनी है और बड्र ग्रुप के तहत प्रचालन कर रही कंपनियों के साम्या शेयरों में इसकी मुख्य हिस्सेदारी है। बोरिया तथा बुराकुर कोयला कंपनियों का प्रचालन कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद बंद हो गया है। केवल चार कंपनियां नामत: ओ एम डी सी, बी एस एल सी, के डी सी एल और एस एस एल ही अब प्रचालनरत हैं।

इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान (50 करोड़ रुपए की अनुमानित/स्वीकृत लागत से) कायान्वित मुख्य स्कीमों/कार्यक्रमों का ब्यौरा अध्याय-।। में दिया गया है।

इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकारी प्रबंधन की कंपनी की सूची, उनके पंजीकृत कार्यालयों के स्थान सहित नीचे दी गई है।

I. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003

2. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (के आई ओ सी एल), ।।-ब्लाक, कोरमंगला, बंगलौर-560034

3. एनएमडीसी लिमिटेड, खनिज भवन, 10-3-311/ए, कैसल हिल्स, मसाब टैंक, हैदराबाद-500028

4. हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल), 5/1 कैमिशेरिएट रोड, हैस्टिंग्स, कोलकाता-700022

5. मेकान लिमिटेड, मेकान बिल्डिंग, पो.ओ.,हीनू, रांची-834002

6. मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मायल), मॉयल भवन, 1ए, कोटाल रोड़, नागपुर-440013

7. स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (सिल), एन एम डी सी कॉम्पलैक्स, खनिज भवन, 10-3-311/ए कैसल हिल्स, हैदराबाद-500028

8. भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड (बी आर एल), इंदिरागांधी मार्ग, सेक्टर IV, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो, (झारखण्ड)-827004

9. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, (आर आई एन एल), परियोजना कार्यालय ए ब्लाक, विशाखापट्टणम-530031

10. एम एस टी सी लिमिटेड, 225 एफ, आचार्य जगदीश बोस रोड, कोलकाता-700020

11. फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल), एफ एस एन एल भवन, इक्विपमेंट चौक, सेट्रल एवेन्यू, पोस्ट बॉक्स नं. 37, भिलाई (छत्तीसगढ़)-490001

II. सरकार के प्रबंधन में कंपनी

(1) बर्ड ग्रुप की कंपनियाँ, एफ डी 350, साल्ट लेक, सेक्टर-।।।, कोलकाता-700106

****

अध्याय-II

वर्ष 2007-08 के लिए प्रमुख योजनाओं का निष्कर्ष बजट

उनके अवधारणात्मक, रूपांकन और कार्यान्वयन को निष्कर्षोन्मुखी बनाकर विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 2005-06 में निष्कर्ष बजट की अवधारणा शुरू की गई थी। यह इस अवधारणा पर आधारित है कि परिव्यय अनिवार्यरूप से निष्कर्ष नहीं होता। निष्कर्ष बजट का अभिप्राय न केवल मध्यवर्ती वास्तविक उत्पादन जिसे अधिक तात्कालिक ढंग से मापा जा सकता है, का ट्रैक करना है, बल्कि सरकार के हस्तक्षेप के अन्तिम उद्देश्य का निष्कर्ष है। इसके लिए सुदृढ़ परियोजना/कार्यक्रम बनाने, मूल्यांकन क्षमताओं के साथ-साथ प्रभावी बेंच-सुपुर्दगी प्रणालियों की आवश्यकता होती है। सम्पूर्ण कार्रवाई को मानिटर करने योग्य बनाकर सुपुर्दगी की यूनिट लागत की बेंच-मार्किंग सहित निष्कर्ष विकास को मापने योग्य परिभाषित करना है। धन जिसे वांछित निष्कर्ष सहित प्रस्तावित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, के समय पर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली की आवश्यकता है तथा उपयुक्त रिर्पोटिंग के जरिए उचित लेखांकन, लेखा परीक्षा एवं मूल्यांकन तंत्र की आवश्यकता है। इसलिए निष्कर्ष बजट सभी प्रमुख कार्यक्रमों के विकास निष्कर्ष को मापने के लिए तंत्र तैयार करने का एक प्रयास है।

10वीं योजना (2002-07) तक इस्पात मंत्रालय को प्रत्यक्ष रूप से किसी योजना का कार्यान्वयन नहीं करना था। 11वीं योजना (2007-12) में "लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना" नामक एक नई योजना को 118.00 करोड़ रुपए के प्रावधान सहित घरेलू लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए शामिल किया गया है। फिलहाल यह योजना तैयार किए जाने के चरण में है। इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने-अपने प्रचालनों के क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम बनाते हैं और कार्यान्वित करते हैं। योजना के स्वरूप पर निर्भर करते हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की योजनागत योजनाएं उनकी वार्षिक योजना अथवा पंचवर्षीय योजनाओं अथवा दोनों की घटक होती हैं। प्रत्येक उपक्रम की अपनी-अपनी कई योजनाएं हैं। अधिकांश योजनाएं कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों और प्रचालनों से संबंधित हैं। इसलिए यह महसूस किया गया है कि इस्पात मंत्रालय के निष्कर्ष बजट में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सभी योजनाओं को शामिल करना न तो व्यवहारिक होगा और न ही निष्कर्ष बजट के उद्देश्य के अनुरूप। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इस्पात मंत्रालय के निष्कर्ष बजट में केवल 50 करोड़ रूपए से अधिक लागत की मंजूर/अनुमानित लागत की प्रमुख योजना और गैर-योजनागत योजनाओं को ही शामिल किया जाए। तदनुसार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रमुख योजनाओं (50 करोड़ रूपए अथवा उससे अधिक मंजूर लागत) को इस्पात मंत्रालय के निष्कर्ष बजट में दर्शाया गया है जैसा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। तथापि, इस्पात मंत्रालय के वित्तीय बजट, 2008-09 और निष्कर्ष बजट, 2008-09 के बीच पूर्णत: अनुरूपता बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की 50 करोड़ रूपए से कम लागत की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए बजटीय आबंटन भी तालिका में दिए गए हैं।

परिव्यय तथा निष्कर्ष का विवरण/लक्ष्य (2008-09)

(50.00 करोड़ रूपए से अधिक की अनुमानित/मंजूर लागत की योजनाएं)

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय 2008-09 (बजट अनुमान)			परिमाणयोग्य सुपुर्दगीयोग्य/अनुमानित निष्कर्ष	प्रोसेसेज/ टाईम लाईन्स	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				गैर-योजना बजट	योजना बजट	आई एंड ईबीआर			
1	2	3	4	5(i)	5(ii)	5(iii)	6	7	8
क.	50.00 करोड़ रूपए से अधिक की अनुमानित/मंजूर लागत की योजनाएं								
1.	**स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)**								
	भिलाई इस्पात संयंत्र								
(ii)	कोक ओवन बैटरी-5 का पुनर्निर्माण	उत्पादन में सुधार करना तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नवीनतम प्रदूषण मानकों को प्राप्त करना	219.04	--	--	**50.00**	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नवीनतम प्रदूषण मानकों के तहत पुनर्निर्माण	जुलाई,08	-मैसर्स सीयूआई/जिप्रोकोक्स /केबीके द्वारा डिजाइन किए गए सिविल और विस्तृत इंजी. में देरी हुई । - सीयूआई व परिसंघ के भागीदारों के बीच समन्वय की कमी ने आपूर्ति एवं उत्थापन को प्रभावित किया है।
(ii)	2x1250 टीपीडी O_2 संयंत्र के लिए विद्युत आपूर्ति सुविधाओं की स्थापना	बीएसपी की भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनटीपीसी व सेल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनएसपीसीएल के जरिए विद्युत संयंत्र-3 से 220 केवी पर विद्युत को हटाया जाना।	62.00	--	--	**30.00**	500 मेगावाट में से 280 मेगावाट बीएसपी के लिए आबंटित की है।	सितं, 08	--
(iii)	मेन स्टैप डाऊन स्टेशन की स्थापना (एमएसडीएस-V)	बीएसपी की भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनटीपीसी व सेल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनएसपीसीएल के जरिए विद्युत संयंत्र-3 से 220 केवी पर विद्युत को हटाया जाना।	143.02	--	--	**92.00**	500 मेगावाट में से 280 मेगावाट बीएसपी के लिए आबंटित की है।	नवं, 08	--

(iv)	नए स्लैब कास्टर, आरएच डिगैसर और लैडल फर्नेस की स्थापन	उच्च गुणवत्ता वाली प्लेटों का उत्पादन करने के लिए क्षमता वृद्धि करने और विशेष रूप से भारतीय रेलवे के अनुकूल बनाने के लिए मूल्यवर्धित/विशेष गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन करना।	520.76	--	--	**123.00**	अतिरिक्त कास्टिंग-0.165 एमटीपीए. एपीआई X65/X70 ग्रेड-3,00,000टी	जुलाई,08	- एलएफ के लिए हॉट ट्रायल 7.2.08 से चल रही है। आरएच डिगैसर के लिए हॉट ट्रायल और चालू करने को कार्य मार्च, 08 में किया जाएगा। - स्लैब कास्टर के मामले में मैसर्स डेनियल एंड सी. इटरी ने आपूर्ति व उत्थापन के संबंध में विलंब किया। - साईट पर कार्य से ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए अपर्याप्त संसाधन संगटन भी प्रभावित हुए हैं।

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय 2008-09 (बजट अनुमान)			परिमाणयोग्य सुपुर्दगीयोग्य/अनुमानित निष्कर्ष	प्रोसेसेज/ टाईम लाईन्स	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				गैर-योजना बजट	योजना बजट	आई एंड ईबीआर			
1	2	3	4	5(i)	5(ii)	5(iii)	6	7	8
(v)	एसएमएस में तप्त धातु डिसल्फ्यूराईजेशन	विशेष रूप से तटीय, परिवहन और अवसंरचना क्षेत्रों में अनुप्रयोग हेतु उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए कम सल्फर वाले इस्पात के उत्पादन को सुविदाप्रद बनाना।	86.23	--	--	**19.23**	तप्त धातु में सल्फर के स्तर में 0.1% से 0.01% की कमी	मार्च, 08	- फ्यूम एक्सट्रेक्शन (एफई) सिस्टम के अनुसार दिसं, 07 में शुरूआत हुआ। - एफई सिस्टम के लिए एकीकृत हॉट ट्रायल जनवरी, 08 में शुरू। यूनिट स्थापित की जा रही है।
(vi)	प्लेट मिल ड्राईव्ज का थिरिस्टोराईजेशन	स्टेट-ऑफ-आर्ट डिजिटल कंट्रोल के साथ मॉर्डन थिरिस्टर कन्वर्टरों द्वारा पुराने व गलत एमजी सैटों को बदलना।	53.52	--	--	**25.00**	मिल उपलब्धता में सुधार एवं विद्युत खपत में कमी	फर, 09	--
(vii)	ऑक्सीजन संयंत्र-।। में 700टीपीडी एएसयू	ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व आर्गन की मांग में हुई बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन संयंत्र-।। में नया एएसयू स्थापित किया जा रहा है।	244.30	--	--	**60.00**	ऑक्सीजन का प्रतिदिन 700 टन	जुलाई, 09	--
(viii)	एंड फोर्जिंग प्लांट	हैवी होलेज/हाई स्पीड ट्रक के निर्माण और प्रस्तावित फ्रैट कोरिडोर के लिए भारतीय रेलवे जरूरत के लिए एंड प्रोफाईल थिक वैब रेल्स को प्रोफाइल ऑफ रेल्स में परिवर्तित करने हेतु।	53.52	--	--	**30.00**	हैवी होलेज/हाई स्पीड ट्रक के लिए हैवी ड्यूटी स्विच बनाने हेतु रेलों का उत्पादन।	नवं, 08	--

2.	**दुर्गापुर इस्पात संयंत्र**								
(i)	बीएफ-3 व 4 में कोल डस्ट इंजेक्शन	प्रौद्योगिकीय जरूरत के मुताबिक कोक दर में कमी तथा फर्नेस उत्पादकता में सुधार	74.22	--	--	**16.97**	1:1 अनुपात के आधार पर कोक का पुल्वेराईज्ड कोल में प्रतिस्थापना। 120 किग्रा/ टीएचएम की दर से ब्लास्ट फर्नेस में कोल इंजेक्शन दर ।	अप्रैल, 08	- मैसर्स श्रीराम ईपीसी द्वारा उपस्कर उत्थापन में विलंब। - सीडीआई इकाई मार्च, 08 में तैयार हो जाएगी, अप्रैल, 08 में यह चालू हो जाएगी ताकि बीएफ उत्पादन प्रभावित न हो।

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय 2008-09 (बजट अनुमान)			परिमाणयोग्य सुपुर्दगीयोग्य/अनुमानित निष्कर्ष	प्रोसेसेज/ टाईम लाईन्स	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				गैर-योजना बजट	योजना बजट	आई एंड ईबीआर			
1	2	3	4	5(i)	5(ii)	5(iii)	6	7	8
3.	**राउरकेला इस्पात संयंत्र**								
(i)	कोक ओवन बैटरी-1 का पुनर्निर्माण	उत्पादन में सुधार करना तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नवीनतम प्रदूषण मानदंडों को प्राप्त करना ।	248.94	--	--	**103.00**	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नवीनतम प्रदूषण मानदंडों के अनुसार पुनर्निनिर्माण	अग, 09	--
(ii)	एसएमएस-।। में हॉट मैटल डिसल्फ्यूराईजेशन यूनिट	विशेष रूप से ऑफ-शोर, परिवहन तथा अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में अनुप्रयोग हेतु उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए कम सल्फर वाले इस्पात के उत्पादन की सुविधा प्रदान करना ।	52.39	--	--	**25.00**	तप्त धातु में सल्फर के स्तर में 0.1% से 0.01% की कमी	मई, 08	--
(iii)	पाईप कोटिंग प्लांट की स्थापना	मुख्य रूप से हाईड्रोकार्बन क्षेत्र में कोटिड पाईपों की आपूर्ति	68.27	--	--	**45.00**	8छ से 42छ की बाह्य परिधि की रेंज वाले पाइपों सहित 60,000 टीपीए क्षमता	अग., 08	--
(iv)	बीएफ-4 में कोल डस्ट इंजेक्शन सिस्टम	कोक दर में कमी तथा फर्नेश उत्पादकता में सुधार के लिए तकनीकी आवश्यकता	70.71	--	--	**50.00**	1:1 अनुपात के आधार पर कोक का पुल्वेराईज्ड कोल में प्रतिस्थापना। 120 किग्रा/ टीएचएम की दर से ब्लास्ट फर्नेस में कोल इंजेक्शन दर ।	अक्तू, 08	--

(v)	सीपीपी-। में टर्बो ब्लोवर सं. 5 की अपरेटिंग	बीएफ-4 की उच्च दाब की आवश्यकता के लिए और अन्य टर्बो ब्लोवरों के शट डाऊन/अनुपलब्धता के मामले में अन्य धमन भट्टियों की एयर संबंधी आवश्यकता के लिए भी।	54.05	--	--	43.00	2.3 किग्रा./सेमी^{2} के दाब पर 1,63,000 एनएम^3/घंटे के डिस्चार्ज वोल्यूम की क्षमता	जन, 09	--
(vi)	न्यू कोक ओवन गैस होल्डर	गैस ग्रिड में पर्याप्त दाब बनाए रखने के लिए प्रतिस्थापन के रूप में न्यू कोक ओवन गैस होल्डर	123.22	--	--	51.00	100,000 मी^{3} क्षमता	जून, 09	--
(vii)	700टीपीडी ऑक्सीजन संयंत्र	ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व आर्गन की मांग में हुई बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए नया ऑक्सीजन संयंत्र	302.70	--	--	128.00	700 टन प्रतिदिन क्षमता	जून, 09	--
(viii)	एसएमएस-।। के बीओएफ कन्वर्टरों की सिमल्टानियस ब्लोइंग	एसएमएस-।। की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए	197.66	--	--	20.00	1.68 एमटीपीए से 1.85 एमटीपीए उत्पादन बढ़ाना	अक्तू, 09	--

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय 2008-09 (बजट अनुमान)			परिमाणयोग्य सुपुर्दगीयोग्य/अनुमानित निष्कर्ष	प्रोसेसेज/ टाईम लाईन्स	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				गैर-योजना बजट	योजना बजट	आई एंड ईबीआर			
1	2	3	4	5(i)	5(ii)	5(iii)	6	7	8
4.	**बोकारो इस्पात संयंत्र**								
(i)	हॉट स्ट्रिप मिल में मीवैस्ट ब्लॉक सिस्टम तथा हाऊसिंग मशीनिंग में संशोधन/मरम्मत कार्य ।	हॉट स्ट्रिप की समग्र गुणवत्ता के साथ-साथ उत्पादन में सुधार करना तथा हॉट स्ट्रिप मिल के सुचारू रूप से कार्य करने को सुनिश्चित करना ।	91.86	--	--	**15.00**	तप्त धातु के उत्पादन के साथ-साथ समग्र गुणवत्ता में सुधार करना तथा हॉट स्ट्रिप मिल के निर्बाध रूप से कार्य को सुनिश्चित करना ।	मई, 08	- गहरे समुद्र में कंटेनर के गिरने से मशीनिंग टूल्स की अनुपलब्धता के कारण सितं, 08 में निर्धारित शटडाऊन का मैसर्स वीएआई उपयोग नहीं कर सका। - चरण-। का कार्य जुलाई, 07 में शुरू हो गया। चरण-।। की आपूर्ति पूरी हो गई। अगले शट डाऊन के लिए उत्थापन की योजना बना ली।

(ii)	ऑक्सीजन संयंत्र में एयर टर्बो कम्प्रैशर (एटीसी) तथा ऑक्सीजन टर्बो कम्प्रैशर (ओटीसी)	उपस्कर को ठीक बनाए रखने तथा भविष्य में दीर्घ आधार पर ऑक्सीजन संयंत्र के उत्पादन के लिए तकनीकी आवश्यकता ।	81.76	--	--	**20.00**	एटीसी क्षमता 90,000 एमएम3/घंटा तथा ओटीसी क्षमता 15,000 एमएम3/घंटा	जुलाई, 08	प्रचालन जरूरत के कारण सिलैण्डर फिलिंग स्टेशन को पुनः स्थापित नहीं किया जा सका जिससे साईट के सौंपने में विलंब हुआ।
(iii)	बीएफ-2 व 3 में कोल डस्ट इंजेक्शन सिस्टम	कोक दर में कमी तथा फर्नेश उत्पादकता में सुधार के लिए तकनीकी आवश्यकता	133.92	--	--	**90.00**	1:1 अनुपात के आधार पर कोक का पुल्वेराईज्ड कोल में प्रतिस्थापना। 120 किग्रा/ टीएचएम की दर से ब्लास्ट फर्नेस में कोल इंजेक्शन दर ।	जुलाई, 08	विस्तार योजना के तहत एसएमएस-3 के लिए साईट को अंतिम रूप देने के कारण कोयला की हैंडलिंग एवं भंडारण साईट के पुनः स्थान निर्धारण में विलंब हुआ।
(iv)	कोल हैण्डलिंग प्लांट में कोककर कोयला भंडारण सुविधाएं	कोककर कोयला के लिए भंडारण सुविधाओं में वृद्धि	134.32	--	--	**70.00**	भंडारण क्षमता में 115,000 टन से 202,500 टन की वृद्धि	अक्तू, 08	- मैसर्स बीएचईएल द्वारा इंजीनियरिंग के डिजाइन और उपस्कर की आपूर्ति करने में विलंब हुआ। - मैसस बीएसबीके द्वारा सिविल कार्य में विलंब ।

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय 2008-09 (बजट अनुमान)			परिमाणयोग्य सुपुर्दगीयोग्य/अनुमानित निष्कर्ष	प्रोसेसेज/ टाईम लाईन्स	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				गैर-योजना बजट	योजना बजट	आई एंड ईबीआर			
1	2	3	4	5(i)	5(ii)	5(iii)	6	7	8
(v)	एसएमएस-।। में दूसरी लैडल फर्नेस की स्थापना।	प्रचालन में कास्टरों व व्यवहार्यता में लंबी सीक्वेंस के लिए बफर स्टेशन बनाने के बावजूद मूल्यवर्धित इस्पात के उत्पादन को सुविधा प्रदान करना, विशेष रूप से कम सल्फर वाले स्टील ग्रेड को, रिटर्न हीट में कमी, ऑक्सीजन खपत औश्र फैरो अलॉय की बचत।	96.96	--	--	**76.00**	मूल्यवर्धित इस्पात का उत्पादन, कन्वर्टरों की लाईनिंग लाईफ में सुधार।	सितं, 08	- मैसर्स वीएआई व मैसर्स सीमेंस द्वारा डिजाइन इंजीनियरिंग व उपस्कर का आदेश देने में विलंब। . - सिविल कार्य में विलंब से मैसर्स एचएससीएल व केसीसी द्वारा संसाधन संघटन में कमी।
(vi)	सिंटर संयंत्र में ईएसपी सहित बैटरी साईक्लोन्स का प्रतिस्थापन।	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदण्डों के अनुसार आऊटलेट डस्ट के उत्सर्जन स्तर की सांविधिक जरूरत को पूरा करने के लिए इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रीसीपीटेटर्स द्वारा बैटरी साईक्लोन का प्रतिस्थापन।	80.60	--	--	**30.00**	आऊटलेट डस्ट के उत्सर्जन स्तर में 150 एमजी/एनएम^3 पर नियंत्रण करने के लिए 900,000 एम^3/घंटा क्षमता के 6 ईएसपी।	अग.,10	--
(vii)	नए टर्बो ब्लोवर की स्थापना	बीएफ-2 की कोल्ड ब्लास्ट (सीबी) बढ़ी जरूरत को पूरा करना।	105.33	--	--	**40.00**	4000 एनएम^3/मिनट का ब्लोवर डिस्चार्ज वोल्यूम और ब्लोवर एंड में 3.9 किग्रा/सेमी^{3} का डिस्चार्ज प्रैशर।	अग.,09	--

(viii)	बीएफ-2 का उन्नयन	उपयोगी वर्किंग वौल्यूम और उत्पादकता में वृद्धि करना।	892.32	--	--	**100.00**	उपयोगी वोल्यूम में 1758 से 2259 एम3 और उत्पादकता में 2टी/एम3/दिन को बढ़ोतरी होगी।	अग,09	--
(ix)	सीओबी-1 व 2 का पुनर्निर्माण।	उत्पादन व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नवीनतम प्रदूषण मानदंडों को प्राप्त करना।	500.90	--	--	**15.00**	उत्पादन व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नवीनतम प्रदूषण मानदंडों में सुधार।	अप्रैल, 10	--
5.	**इस्को इस्पात संयंत्र**								
(i)	कोक ओवन बैटरी-10 का पुनर्निर्माण	उत्पादन व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नवीनतम प्रदूषण मानदंडों को प्राप्त करना।	416.50	--	--	**60.00**	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नवीनतम प्रदूषण मानदंडों के अनुसार पुनर्निर्माण।	सितं, 09	--
(ii)	आईएसपी का विस्तार	2.7एमटीपीए तप्त धातु, 2.5एमटीपीए अपरिष्कृत इस्पात और 2.37एमटीपीए विक्रेय इस्पात का उत्पादन करने के लिए नई सुविधाए स्थापित करना।	14195.51	--	--	**961.00**	2.7एमटीपीए तप्त धातु, 2.5एमटीपीए अपरिष्कृत इस्पात और 2.37एमटीपीए विक्रेय इस्पात	मई, 10	--

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय 2008-09 (बजट अनुमान)			परिमाणयोग्य सुपुर्दगीयोग्य/ अनुमानित निष्कर्ष	प्रोसेसेज/ टाईम लाईन्स	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				गैर-योजना बजट	योजना बजट	आई एंड ईबीआर			
1	2	3	4	5(i)	5(ii)	5(iii)	6	7	8
6.	**सेलम इस्पात संयंत्र**								
(i)	एसएसपी का विस्तार	सतत् ढलाई व नई सीआरएम के साथ् इस्पात निर्माण सुविधाएं विकसित करना।	2138.00	--	--	**200.00**	अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन में शून्य से 0.18 एमटी और विक्रेय इस्पात के उत्पादन में 0.18 से 0.34 एमटी की वृद्धि करना।	मार्च,10	--
7.	**वीआईएसएल**								
(i)	एसएमएस में ब्लूम कास्टर की स्थापना।	सतत् ढलाई प्रौद्योगिकी द्वारा पुरानी इन्गॉट प्रौद्योगिकी का प्रतिस्थापन।	87.64	--	--	**40.00**	1,25,000 टीपीए कास्ट ब्लूम्स का उत्पादन।	फर, 09	--
2.	**राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.**								

(i)	कोक ओवन बैटरी सं. 4, चरण-।	कोक की जरूरतों एवं शेष गैस को पूरा करने के लिए, अन्य तीन कोक ओवन बैटरियों की बड़े पैमाने पर मरम्मत के दौरान भी तप्त धातु व द्रव इस्पात के उत्पादन को इस स्तर पर बनाए रखने हेतु एक प्रतिस्थापन बैटरी की आवश्यकता होगी ।	303.00	--	--	**20.00**	0.75 एमटी कोक का उत्पादन करना	दिसंबर, 03 में प्राप्त भारत सरकार के आदेश के 36 माह बाद चिमनी हीटिंग की स्थापना हुई। अब सितंबर,08 में इसके चालू होने की संभावना है।	टिप्पणियां:- मैकेनिकल की आपूर्ति, रिफ्रैक्ट्री मदों में विलंब और विस्थापित लोगों के विरोध के कारण बैटरी के चालू होने में विलंब हुआ। जोखिम :- चरण-।। की इकाइयों के चालू न होने से संपूर्ण क्षमता अर्जित नहीं की गई।
(ii)	कोक ओवन बैटरी सं. 4, चरण-II	गैस का पूर्ण उपयोग करना तथा कोल हैंडलिंग में अतिरिक्त उप-उत्पाद सुविधाएं प्रदान करके उप-उत्पादों के बेहतर कार्यान्वयन में वृद्धि करना	118.89	--	--	**80.00**	उप-उत्पादों की प्राप्ति में वृद्धि	नवं, 09	टिप्पणियां:- (1) उप-उत्पाद संयंत्र के लिए परामर्शदाता को नियत करने में विलंब। हाल ही में परामर्शदात नियुक्त। (2) विशिष्टियां जारी की गईं तथा प्रमुख पैकेजों के लिए टेंडर प्रक्रिया में हैं। जोखिमः- लागत वृद्धि की संभावना। चालू करने में विलंब संभावित।

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय 2008-09 (बजट अनुमान)			परिमाणयोग्य सुपुर्दगीयोग्य/अनुमानित निष्कर्ष	प्रोसेसेज/ टाईम लाईन्स	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				गैर-योजना बजट	योजना बजट	आई एंड ईबीआर			
1	2	3	4	5(i)	5(ii)	5(iii)	6	7	8
(iii)	द्रव इस्पात का 6.3 एमटीपीए तक विस्तार।	संयंत्र की क्षमता में वृद्धि।	8692.00#	--	--	3000.00	उत्पादन में वृद्धि। द्रव इस्पात के उत्पादन को बढ़ाकर वर्तमान स्तर 3.0 एमटीपीए क्षमता से 6.5 एमटीपीए करना ।	मार्च,10 (सीमलैस ट्यूब मिल को छोड़कर)	टिप्पणियां:- विलंब के कारण निम्न हैं:- (1) ब्रिज एंड रूफ, कोलकाता व इंजी. वर्क्स, नई दिल्ली का निष्पादन संतोषजनक नहीं है। (2) क्वैरी आपूर्तिकर्ता की हड़ताल के कारण निर्माण कार्यकलापों के लिए माईनर मिनरल्स की कमी। (3) ऑर्डर देने और प्रमुख प्रक्रिया पैकेजों के ठेकों पर हस्ताक्षर होने में विलंब। (4) कुशल जनशक्ति तथा सुपरवाईजरी स्टॉफ की भारी कमी। (5) 19 जून, 07 से 25 जून, 07 तक तथा 15 सितं से 30 सितं तथा 22 अक्तू 07 तक चक्रवाती वर्षा। जोखिम:- संयंत्र और मशीनरी की मूल्य वृद्धि जिससे पूंजीगत लागत में वृद्धि होगी। अधिक समय लगने से लागत में वृद्धि। बाजार मूल्यों में उतार चढ़ाव। कच्चे माल का उपलब्ध न होना तथा आदान सामग्री के मूल्य में फेरबदल। अन्य देशों द्वारा इस्पात की डम्पिंग। रि-रोलिंग मिल तथा घरेलू उद्यमियों से प्रतिस्पर्धा।
(iv)	एयर सैपरेशन प्लांट	कंबाइंड ब्लोइंग प्रोसेस हेतु ऑर्गन की कमी होने पर अतिरिक्त सुविधा प्रदान करना । उत्पादित ऑक्सीजन बीएफ में प्रयुक्त की जाती है ।	96.00	--	--	50.00	600 टन/दिन की अतिरिक्त क्षमता	जुलाई 09	टिप्पणियां: शीघ्र ऑडर दिए जाने की संभावना है। निविदा के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा रहा है। पार्टियों ने लंबी अवधि की सुपुर्दगी अवधि उद्धरित की है। जोखिम: चालू करने में विलंब। बाजार घटकों के कारण लागत वृद्धि की संभावना।

परियोजना लागत संशोधन के तहत है।

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय 2008-09 (बजट अनुमान)			परिमाणयोग्य सुपुर्दगीयोग्य/अनुमानित निष्कर्ष	प्रोसेसेज/ टाईम लाईन्स	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				गैर-योजना बजट	योजना बजट	आई एंड ईबीआर			
1	2	3	4	5(i)	5(ii)	5(iii)	6	7	8
(v)	पुल्वेराईज्ड कोल इंजेक्शन	कम महंगे पुल्वेराईज्ड कोल की तुलना में महंगे बीएफ कोक की खपत में कमी के लिए इंजेक्शन सिस्टम ।	165.00	--	--	**60.00**	तप्त धातु का वर्धित उत्पादन। तप्त धातु की उत्पादन की लागत में कमी करना।	जुलाई, 09	टिप्पणियां: परियोजना संशोधित अनुसूची के अनुसार पूरा किए जाने की संभावना है। जोखिम: चालू होने में विलंब की संभावना।
(vi)	लौह अयस्क खान तथा कोककर कोयला खानों का अधिग्रहण	कच्चे माल के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और लागत में कमी करना।	600.00	--	--	**60.00**	आरआईएनएल/वीएसपी के पास कोककर कोयला/लौह अयस्क के लिए निजी स्रोत नहीं हैं और परिव्यय खानों के अधिग्रहण के लिए शामिल हैं।	--	टिप्पणियां: महल कोयला ब्लॉक आबंटित व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार परियोजना व्यवहार्य नहीं है। वैकल्पिक ब्लॉकों के आबंटन के लिए भारत सरकार के साथ उठाया गया है। जोखिम: प्रस्ताव को स्वीकार करना प्रौद्योगिक आर्थिक घटकों पर निर्भर करता है।
(vii)	वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सुविधाएं	शून्य जल बहिस्राव	93.28	--	--	**80.00**	तीन स्थानों से पानी प्राप्त किया गया/संरक्षित किया गया/पुन: उपयोग किया गया/प्लांट के आऊटलेट 1050 घन मी./घंटा होंगे।	जन, 10	--
(viii)	लौह अयस्क भ्ंडारण के लिए सुविधाएं	लौह अयस्क भण्डारण सुविधा बढ़ाना	480.84	--	--	**300.00**	लौह अयस्क भंडारण सुविधा 30 दिन के लिए बढ़ेगी।	सितं 09	टिप्पणियां: परामर्शदाता नियुक्त किया जा रहा है।
(ix)	अनुषंगी सुविधाओं सहित 330 टीपीएच (छठा) बॉयलर	स्टील आवश्यकता को बढ़ाना।	260.00	--	--	**145.00**	विस्तार के लिए प्रोसेस स्टीम का उत्पादन करना और विद्युत उत्पादन के लिए अतिरिक्त स्टीम।	दिसं 09	--
(x)	67.5 मेगावाट का टीजी-5 पावर इवेक्यूएशन सिस्टम	अतिरिक्त विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करना।	202.00	--	--	**145.00**	विस्तार इकाइयों की विद्युत आवश्यकता का आंशिक रूप से उत्पादन करना।	दिसं 09	--
(xi)	30 मेगावाट की विंड फार्म परियोजना	उपयुक्त स्थान पर 30 मेगावाट की ऊर्जा परियोजना स्थापित करना।	170.00	--	--	**85.00**	30 मेगावाट की रिन्यूऐबल इनर्जी का उत्पादन करना।	अग. 09	--

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय 2008-09 (बजट अनुमान)			परिमाणयोग्य सुपुर्दगीयोग्य/ अनुमानित निष्कर्ष	प्रोसेसेज/ टाईम लाईन्स	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				गैर-योजना बजट	योजना बजट	आई एंड ईबीआर			
1	2	3	4	5(i)	5(ii)	5(iii)	6	7	8
	कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि. (केआईओसीएल)								
(i)	मंगलौर में स्थाई रेलवे साइडिंग का विकास	मैग्नेटाईट लौह अयस्क सांद्रण देश में उपलब्ध नहीं होगा और पैलेट संयंत्र के प्रचालन के लिए कच्च माल के रूप में बेल्लारी/हॉस्पेट के उच्च ग्रेड के हैमेटाईट लौह अयस्क का प्रयोग करना दीर्घकाल के लिए एक वैकल्पिक स्रोत माना जाता है।	55.00	--	--	**5.00**	मंगलौर में 4 एमटीपीवाई लौह अयस्क की प्राप्ति को संभावना।	कॉलम 8 देखें	पहले कंपनी एक पाईपलाईन के जरिए कुद्रेमुख से मैग्नेटाईट लौह अयस्क सांद्रण प्राप्त करती थी जिसे पैलेट में परिवर्तित किया जाता था और आयात करने के साथ-साथ घरेलू ग्राहकों को बिक्री की जाती थी। 31.12.2005 से कुद्रेमुख में खनन कार्यकलाप बंद होने के परिणामस्वरूप बेल्लारी-हॉस्पेट क्षेत्र में पाए गए हैमेटाईट लौह अयस्क चूरे की खरीद की जाती थी और पैलेट के परिवर्तित किया जाता था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संयंत्र को रेल द्वारा पर्याप्त कच्ची सामग्री प्राप्त हो, एक अंतरिम उपाय के रूप में न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट से पट्टे पर एक प्लाट लिया गया और दिसंबर, 2005 तक रिकॉर्ड समय में 4 लाईन की एक रेलवे साईडिंग का निर्माण किया गया। तथापि, इसके लिए 500 ट्रक की आवाजाही की आवश्यकता थी और पारिस्थितिकी/पर्यावरण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्थाई रेलवे साईडिंग के लिए कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट बोर्ड (केआईएडीबी) से भूमि ली गई है।
(ii)	रेल द्वारा लौह अयस्क की प्राप्ति के लिए भारी माल संभाल की सुविधाओं का निर्माण	चूंकि अधिकांश कच्चा माल का परिवहन रेल के जरिए किया जाता है। केआईओसीएल को इसके पैलेट तथा कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए लौह अयस्क प्रेषण प्राप्त करने के लिए भारी माल संभाल सुविधाओं का निर्माण करने का प्रस्ताव है।	60.00	--	--	**5.00**	पैलेट के उत्पादन के लए 4 एमटीपीवाई लौह अयस्क की आपूर्ति	कॉलम 8 देखें	नई रेलवे साईडिंग का प्रस्ताव करने के बाद एक क्लोज्ड कन्वेयर सिस्टम के जरिए भारी माल संभाल प्रणाली की योजना बनाई थी। उपर्युक्त भूमि संबंधी विवाद के परिणामस्वरूप इस परियोजना में भी विलंब हुआ।

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय 2008-09 (बजट अनुमान)			परिमाणयोग्य सुपुर्दगीयोग्य/अनुमानित निष्कर्ष	प्रोसेसेज/ टाईम लाईन्स	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				गैर-योजना बजट	योजना बजट	आई एंड ईबीआर			
1	2	3	4	5(i)	5(ii)	5(iii)	6	7	8
(iii)	डक्टाईल आयरन स्पन पाईप	मूल्यवर्धित उत्पाद अर्थात डक्टाइल आयरन स्पन पाईप का उत्पादन करने के लिए एक योजना बनाना।	225.00	--	--	**30.00**	1,00,000 टीपीए डीआईएसपी का उत्पादन	कॉलम 8 देखें	दिनांक 1.4.2007 से गौण कंपनी किस्को का डीआईओसीएल में विलय कर दिया गया है। इसके लिए आदेश बीआईएफआर से जुलाई, 2007 के अंत तक प्राप्त हो गया था। वैश्विक निविदा निकालने से ऑर्डर नहीं दिया गया। अत: नए वैश्विक निविदा नोटिस जारी किए गए हैं।
(iv)	कुद्रेमुख में इको-टाऊन विकास	कुद्रेमुख इको-टयूरिज्म सुविधाएं विकसित करने का उद्देश्य समुदाय आधारित एवं वाणिज्यिक अभिकेन्द्रित इको टूरिस्ट परियोजना विकसित करना है।	95.00	--	--	**10.00**	इको-टूरिज्म का विकास	कॉलम 8 देखें	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने दिनांक 31.12.05 से कुद्रेमुख में खनन कार्य रोक दिया है। कंपनी के आवासीय घर, अस्पताल, गेस्ट हाऊस आदि के रूप में कुद्रेमुख में पहले ही स्थापित बुनियादी सुविधा है और यह इको टूरिज्म में उद्यम शुरू करने की योजना बना रही है। इस संबंध में वाईल्ड वेंचर्स प्रा. लि. ने एक अध्ययन किया है तथा इन्होंने राज्य सरकार के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम की सिफारिश की है।
(v)	कोक ओवन प्लांट	एक कोक ओवन संयंत्र की स्थापना करना। इससे कम मूल्य पर कोक की उपलब्धता में सुधार होगा।	100.00	--	--	**10.00**	कच्चा माल लागत में कमी करना।	कॉलम 8 देखें	धमन भट्टी में प्रयोग किए जा रहे कोक की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने मंगलौर में एक कोक ओवन संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य बनाया है। इससे कच्चे माल की लागत में काफी कमी आएगी।

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय 2008-09 (बजट अनुमान)			परिमाणयोग्य सुपुर्दगीयोग्य/अनुमानित निष्कर्ष	प्रोसेसेज/ टाईम लाईन्स	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				गैर-योजना बजट	योजना बजट	आई एंड ईबीआर			
1	2	3	4	5(i)	5(ii)	5(iii)	6	7	8
4.	**एन.एम.डी.सी. लि.**								
(i)	बैलाडिला निक्षेप-11बी	लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ाना।	295.89	--	--	**110.00**	3 एमटीपीए की चरण-। की क्षमता	अक्तूबर 2009	चार प्रमुख पैकेजों में से पैकेज-1 (क्रशिंग प्लांट एंड स्टॉक पाईल), पैकेज-2 (डाऊनस्ट्रीम कन्वेइंग सिस्टम), पैकेज-3 (अर्थ वर्क एंड साईट प्रीप्रेशन) पहले ही प्रदान कर दिए हैं। पैकेज-3 के संबंध में कुल 10.2 लाख मात्रा सहित उत्खनन तथा 3041 वर्ग मी. सोइल नेलिंग तथा 1976 वर्ग मी. शॉटक्रेटिंग पूरा हो चुका है। पैकेज-1 (इलैक्ट्रिकल सब-स्टेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) के लिए ऑफर प्राप्त हुए हैं तथा तकनीकी वाणिज्यिक सिफारिशें तैयार की जा रही हैं।
(ii)	कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना	लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ाना।	296.03	--	--	**3.00**	3 एमटीपीए की चरण-। की क्षमता	दिसं 09	एनएमडीसी के पक्ष में पट्टे का नवीकरण करने के संबंध में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश को अभी खरिज किया जाना है। वन विभाग से वृद्धि गिराने संबंधी आज्ञा भी प्राप्त करनी है तथापि मेकॉन को इंजीनियरी, ठेका अधिप्राप्ति, परियोजना प्रबंधन तथा निर्माण प्रबंधन सेवाओं के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। पैकेज-। के लिए निविदा निकाली गई है तथा अन्य पैकेजों के लिए निविदा दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय 2008-09 (बजट अनुमान)			परिमाणयोग्य सुपुर्दगीयोग्य/अनुमानित निष्कर्ष	प्रोसेसेज/ टाईम लाईन्स	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				गैर-योजना बजट	योजना बजट	आई एंड ईबीआर			
1	2	3	4	5(i)	5(ii)	5(iii)	6	7	8
(iii)	स्पंज लोहा एवं 10 मेगावाट विद्युत संयंत्र, नागरनार	स्पंज लोहा का उत्पादन करना तथा विद्युत सृजन करना	79.00	--	--	**15.00**	1 लाख टन प्रतिवर्ष स्पंज लोहा एवं 10 मेगावाट विद्युत का सृजन करना।	सितंबर 09	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त हो गई है तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी अभी प्राप्त होनी है। इसी बीच मैसर्स स्पंज आयरन इंडिया लि. को ईपीसीएम आधार पर परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। प्लांट ले-आऊट को अंतिम रूप दे दिया गया है। क्लिन-कूलर के संबंध में टेंडर को अंतिम रूप दिया गया है और ऑर्डर फरवरी, 08 में जारी किया जा रहा है। सिविल व स्ट्रक्चरल वर्क्स पैकेज तथा कच्ची सामग्री की तैयारी और उत्पाद संभाल पैकेज के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। अन्य पैकेजों के लिए टेंडर दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।
(iv)	कर्नाटक में विंड मिल	विद्युत ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हासिल करना।	110.00	--	--	**50.00**	10 मेगावाट विद्युत सृजन करना।	सितं. 08	टेंडर के लिए ऑफर प्राप्त हो गए हैं और जांच में हैं।
5.	**मैंगनीज ओर इंडिया लि. (मॉयल)**								
(i)	फैरो मैंगनीज/सिलिका मैंगनीज संयंत्र के लिए संयुक्त उद्यम	सेल के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में इस परियोजना को भिलाई में स्थापित किया जाएगा।	225.00	--	--	**74.00**	सेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह परियोजना फैरो मैंगनीज/ सिलिका मैंगनीज का उत्पादन करेगी।	इस परियोजना को वर्ष 2008-09 में शुरू किया जाएगा।	यह परियोजना संयुक्त उद्यम द्वारा शुरू की जाएगी जिसमें मॉयल और सेल प्रत्येक में 50% शेयर होंगे।
6.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. (एचएससीएल								
(i)	वीआरएस के लिए आवधिक ऋण पर ब्याज इमदाद	वीआरएस के जरिए जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाना।	--	**56.02**	--	--	जनशक्ति को 1660 से कम करने 1280 तक करना।	वर्ष 2008-09 के अंत तक	कर्मचारियों की संख्या, 11.2008 की स्थिति के अनुसार 1531 तक की हो गई है।
उप-योग - क			--	***56.02***	--	***6891.20***			

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय 2008-09 (बजट अनुमान)			परिमाणयोग्य सुपुर्दगीयोग्य/अनुमानित निष्कर्ष	प्रोसेसेज/ टाईम लाईन्स	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				गैर-योजना बजट	योजना बजट	आई एंड ईबीआर			
1	2	3	4	5(i)	5(ii)	5(iii)	6	7	8
ख.	**इस्पात मंत्रालय की योजना**								
	लोहा एवं इस्पात क्षेत्र में आर एंड डी में सुधार करने के लिए योजना।	पर्यावरण के अनुकूल उपायों से गुणवत्ता वाले इस्पात का लागत प्रभावी उत्पादन हेतु इनोवेटिव/पाथ ब्रेकिंग एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए आर एंड डी सुविधाओं में सुधार तथा इन्हें तीव्र करन के लिए एक नई योजना/तंत्र बनाना।	118.00	--	**18.50**	--	See col.8	कॉलम 8 देखें	यह योजना तैयार चरण में है।.
उप-योग ख				--	*18.50*	--			
ग.	**50 करोड़ रुपए से कम अनुमानित/स्वीकृत लागत की योजनाएं/कार्यक्रम**								
(i)	**सरकारी उपक्रमों के संबंध में**								
	एएमआर योजनाएं, आर एंड डी, बस्ती, तकनीकी उन्नयन, संभाव्यता अध्ययन, वीआरएस का कार्यान्वन तथा विभिन्न अन्य चल रही एवं नई योजनाएं।	संयंत्रों, उपस्करों एवं मशीनरी के नियमित अनुरक्षण एवं रख-रखाव, उत्पादन लागत को कम करने तथा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार तथा उत्पादकता में वृद्धि आदि के लिए।	--	**13.89**	**15.50**	**2617.80**	--	--	योजनाएं सरकारी उपक्रमों के दिन-प्रतिदिन के कार्य एवं प्रचालन से संबंधित है। इनकी प्रकृति भिन्न-भिन्न है तथा इसलिए प्रमुख योजनाओं को निष्पादन बजट में अलग से शामिल नहीं किया गया है।

(ii)	**इस्पात मंत्रालय से संबंधित (प्रत्यक्ष रूप से)**								
	मंत्रालय सचिवालय, पीएओ (इस्पात), डीसीआई एंड एस कार्यालय, कोलकाता तथा विशिष्ट मेटालजिस्ट को पुरस्कार	इस्पात मंत्रालय का प्रशासनिक व्यय को पूरा करना।	--	**15.61**	**--**	**--**	--	--	निष्पादन बजट में सम्मिलित नहीं किया गया है।
उप-योग - ग			--	***29.50***	***15.50***	***2617.80***			
सकल योग - क + ख + ग			--	85.52 #	34.00	9509.00			

सकल आधार पर । एचएससीएल, बीआरएल तथा मेकॉन लि. को प्रदानकी गई गारंटी फीस को माफ करने के संबंध में 8.29 करोड़ रुपए निवल प्राप्त होने के बाद वर्ष 2008-09 (बजट अनुमान) के लिए 77.23 करोड़ रुपए का गैर-योजना बजट है।

अध्याय-III

सुधार उपाय और नीतिगत पहल

1. भारतीय इस्पात क्षेत्र का उदारीकरण

भारतीय इस्पात क्षेत्र ऐसा प्रथम महत्वपूर्ण क्षेत्र था जिसे लाइसेंसिंग युग और मूल्य निर्धारण एवं वितरण नियंत्रण से पूर्णत: मुक्त किया गया है। इसे मुख्य रूप से भारतीय लोहा और इस्पात उद्योग द्वारा दर्शाई गई अन्तर्निहित शक्तियों और क्षमताओं के कारण इसे नियंत्रणमुक्त किया गया। आर्थिक सुधार और उसके परिणामस्वरूप लोहा और इस्पात क्षेत्र के उदारीकरण जो 1990 के आरंभ में शुरू हुआ था, से इस्पात उद्योग में काफी विकास हुआ है और निजी क्षेत्र में ग्रीन फील्ड इस्पात संयंत्र स्थापित हुए हैं। आज विश्व में इस्पात का उत्पादन करने में भारत 5वें स्थान पर है। इस क्षेत्र में लगभग 90,000 करोड़ रूपए से अधिक की पूंजी लगी हुई है और सीधे 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। 12.87% की वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2006-07 के दौरान 50.20 मिलियन टन परिसज्जित कार्बन इस्पात का उत्पादन हुआ। चालू वर्ष 2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान परिसज्जित कार्बन इस्पात का कुल उत्पादन 38.09 मिलियन टन (अनन्तिम) हुआ जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए उत्पादन से 5.6% अधिक है।

भारतीय लोहा और इस्पात क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए किए गए महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय नीचे दिए गए हैं:-

(i) जुलाई, 1991 में घोषित की गई नई औद्योगिक नीति में लोहा और इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से भी छूट दे दी गई है।

(ii) 24.5.92 से लोहा और इस्पात उद्योग को 51% तक विदेशी साम्या निवेश के लिए स्वत: मंजूरी हेतु उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है। इस सीमा को अब 100% तक बढ़ाया गया है।

(iii) जनवरी, 1992 से इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया था। इसके साथ-साथ यह सुनिश्चित किया गया था कि रक्षा और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अतिरिक्त लघु उद्योगों, इंजीनियरी माल के निर्यातकों और पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी जाती रहेगी।

(iv) आयात लाइसेंसिंग, विदेशी मुद्रा निर्मुक्ति, माध्यमीकरण और अधिक आयात टैरिफ से लोहे और इस्पात के आयात को पूर्णत: मुक्त करने के लिए आयात शुल्क स्तर को कम करके लोहा और इस्पात के लिए नियंत्रित आयात प्रणाली को धीरे-धीरे काफी

उदार बनाया गया है। लोहे और इस्पात मदों का स्वतंत्र रूप से निर्यात करने की भी अनुमति दी गयी है।

(v) इस्पात उत्पादन के लिए कच्चे माल पर शुल्क में भी कमी की गयी है। इन उपायों से इस्पात संयंत्रों की पूंजीगत लागत और उत्पादन लागत में कमी हुई है।

(vi) जनवरी, 1992 में मालभाड़ा समकरण योजना समाप्त कर दी गयी थी। देश के विभिन्न भागों में नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना से घरेलू बाजार में लोहा और इस्पात सामग्री निर्बाध रूप से उपलब्ध है।

(vii) बाजार शक्तियों का सामना करने के लिए प्रमुख उत्पादकों को और अधिक छूट देकर अप्रैल, 1994 से इस्पात विकास निधि संबंधी लेवी समाप्त कर दी गयी है।

(viii) खनिज उत्पादों और अयस्क एवं सांद्रण सहित इस्पात उत्पादन की महत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियों पर आयात शुल्क में पिछले कुछ वर्षों के बजट, विशेष रूप से पिछले बजट में काफी कमी की गई है।

(ix) माननीय इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 30.6.2006 को हुई इस्पात उपभोक्ता परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में इस्पात मंत्रालय ने एक इस्पात मूल्यन प्रबोधन समिति (एस पी एम सी) गठित की है। एस पी एम सी जिसमें सभी प्रमुख इस्पात उत्पादकों और इस्पात उपभोक्ताओं की भागीदारी है, का उद्देश्य मूल्य युक्तिकरण की मानिटरिंग, मूल्य के उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करना और इस्पात जिंसों के अयुक्तिसंगत मूल्य के बारे में सभी संबंधितों को सलाह देना है। एस पी एम सी तिमाही आधार पर बैठक करेगी और विभिन्न श्रेणियों के इस्पात उत्पादों के मूल्यों के उतार-चढ़ाव पर विचार-विमर्श करेगी, अन्तरों का विश्लेषण करेगी, भावी मूल्यों की नीति बनाएगी तथा इस्पात उत्पादन, खपत और व्यापार की नीतियों की सिफारिश करेगी।

2. राष्ट्रीय इस्पात नीति

इस्पात उद्योग की प्रगति भारत के विकास की गति को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है और इस प्रकार उस लागत और मूल्य पर, जिस पर भारतीय इस्पात अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी है, संभावित मांग के अनुसार क्षमता विस्तार काफी महत्व रखता है । देश में उदारीकरण के वर्तमान युग, नियंत्रणमुक्त और उद्योग के अविनियमन ने इस्पात उद्योग के विस्तार के लिए नए अवसर उपलब्ध करा दिए हैं । इस्पात क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने और 2020 तक भारत के विकसित अर्थव्यवस्था के विजन को हासिल करने के लिए इस्पात मंत्रालय ने

2005 में राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) तैयार की है । राष्ट्रीय इस्पात नीति की खास बातें नीचे दी गई हैं-

- राष्ट्रीयइस्पात नीति के तहत भारतीय इस्पात उद्योग के सुधार, पुनर्संरचना और वैश्वीकरण के संबंध में व्यापक योजना तैयार की गई है ।

- राष्ट्रीयइस्पात नीति का दीर्घकालिक लक्ष्य यह है कि भारत में विश्व स्तरीय आधुनिक और क्षमतावान इस्पात उद्योग हो जो विविधिकृत इस्पात मांग को पूरा कर सके । नीति का उद्देश्य न केवल लागत, गुणवत्ता और उत्पाद मिश्र के क्षेत्र में अपितु दक्षता और उत्पादकता के क्षेत्र में भी वैश्विक मानकों को प्राप्त करना है ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा हासिल की जा सके ।

- वर्ष 2019-20 तक 110 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति में मुक्त, वैश्विक स्तर पर एकीकृत और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में इस उद्योग के विकास में सामने आ रही आपूर्ति संबंधी अड़चनों को दूर करने की बात कही गई है।

- राष्ट्रीय इस्पात नीति में दीर्घकालिक नीतिगत लक्ष्य हासिल करने के लिए एक बहुपक्षीय रणनीति अपनाने की बात कही गई है । मांग के संबंध में रणनीति प्रोत्साहन जनक प्रयासों और जागरूकता पैदा करके तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिलीवरी चेन को सुद्रढ़ बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मांग सृजित करने की होगी । आपूर्ति के संबंध में अतिरिक्त क्षमता के सृजन को सुसाध्य बनाने, लौह अयस्क और कोयला जैसे आदानों की उपलब्धता में प्रक्रिया और नीति संबंधी बाधाओं को दूर करने, अनुसंधान और विकास में और अधिक निवेश करने तथा सड़कों, रेलवे और पत्तनों जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन को प्रोत्साहित करने की रणनीति होगी ।

- राष्ट्रीय इस्पात नीति में यह माना गया है कि देश में, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत कम है और जीवन स्तर में सुधार करने और जनता की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करने के लिए इस्पात की खपत बढ़ाने की जरूरत है ।

- वर्ष 2019-20 तक 110 मिलियन टन इस्पात उत्पादन के नीतिगत लक्ष्य को हासिल करने के लिए उद्योग को अतिरिक्त पूंजी की जरूरत होगी । इसके अलावा मौजूदा सुविधाओं के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए निधियों की जरूरत होगी । इतने बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित

करने की बात कही गई है । इसके अलावा, नीति में इस्पात उद्योग को प्राप्त होने वाले राजकोषीय प्रोत्साहन अवसंरचना परियोजनाओं को मुहैया करवाने की भी बात कही गई है ।

- राष्ट्रीय इस्पात नीति में इस्पात बाजार में कीमतों में अस्थिरता को रोकने के लिए फ्यूचर्स और डिरीवेटिव्ज जैसी जोखिम-रोधी व्यवस्थाएं करने में सहायता करने की बात कही गई है।

- राष्ट्रीय इस्पात नीति में घरेलू इस्पात उद्योग को उपलब्ध मौजूदा प्रशिक्षण अनुसंधान सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की बात कही गई है ताकि गौण लघु इकाइयों को उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करवाए जा सकें और उद्योग से संबंधित प्राचलों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जा सकें और उनका विश्लेषण किया जा सके ।

- राष्ट्रीय इस्पात नीति में विशेष श्रेणियों के इस्पात के लिए उत्पादन क्षमता सृजित करने, कोककर कोयले को प्रतिस्थापित करने, लौह अयस्क चूर्ण का उपयोग करने, ग्रामीण आवश्कताओं के अनुरूप नए उत्पाद विकसित करने, सामग्री और ऊर्जा, अपशिष्ट का उपयोग करने और पर्यावरण के संबंध में हो रही गिरावट को रोकने के लिए अनुसंधान और विकास संबंधी उद्यमशील प्रयास करने की बात कही गई है ।

- राष्ट्रीय इस्पात नीति में माना गया है कि गौण इस्पात क्षेत्र ने ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने, इस्पात की स्थानीय मांग पूरी करने और देश की कुछ विशेष उत्पादों की मांग पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है । इस नीति में राज्य लघु उद्योग निगमों के मौजूदा तंत्र के जरिए प्रमुख संयंत्रों से इन इकाइयों को उचित कीमतों पर आवश्यक फीडस्टॉक उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास करने की बात कही गई है ।

- राष्ट्रीय इस्पात नीति में माना गया है कि भारतीय इस्पात उद्योग का एकीकरण वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ करने के लिए आवश्यक है कि इस उद्योग को उन अनुचित व्यापार क्रिया-कलापों, जो विशेषकर मंदी की अवधि के दौरान आम हो जाते हैं, से बचाने की आवश्यकता है । इसलिए राष्ट्रीयइस्पात नीति में आयात को बनाए रखने के लिए तथा अन्य देशों में निर्यात इमदाद के प्रबोधन के लिए तंत्र स्थापित करने के बारे में भी कहा गया है ।

केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय के लिए एनएसपी की मानीटरिंग करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री की मंजूरी से एक अंतर मंत्रालय समूह (आईएमजी) गठित किया गया है। सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में आईएमजी देश में प्रमुख इस्पात निवेशों से संबंधित मुद्दों की

मानीटरिंग करेगा और समन्वय करेगा। खान मंत्रालय के सचिव, औद्योगगिक नीति एवं वन मंत्रालय के सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव पोत विभाग के सचिव, सदस्य (यातायात) रेलवे बोर्ड तथा संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य सचिव आईएमजी के अन्य सदस्य हैं।

आईएमजी के विचाराधीन प्रमुख विषय प्रमुख इस्पात क्षमताओं को शीघ्र पूरा करने के लिए उपायों की समीक्षा करना और समन्वय करना तथा अवसंरचना, कच्चे माल की उपलब्धता, पर्यावरण संबंधी मंजूरी शीघ्र प्राप्त करना, अन्य संसाधनों जैसे भूमि और पानी की उपलब्धता तथा पुनर्वास से संबंधित मुद्दे हैं।

जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है कि एन एस पी का एक उद्देश्य इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देकर देश में इस्पात की खपत और मांग को बढ़ाना है। इस्पात के उपयोग जागरूक संवर्धन के संबंध में लोगों को जागरूक करने संबंधी अभियान को ध्यान में रखते हुए सचिव, इस्पात मंत्रालय की अध्यक्षता में **इस्पात संवर्धन समन्वय समिति** गठित की गई है। प्रमुख इस्पात उत्पादक इस समिति में शामिल हैं। यह समिति इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (आई एन एस डी ए जी) के अधीन काम कर रही है। इस समिति का उद्देश्य जागरूकता अभियान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर बल देकर के जरिए देश में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देना है।

3. इस्पात मंत्रालय द्वारा की गई प्रमुख पहल

3.1 एनएसपी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित प्रमुख पहलें की गई हैं:-

(i) इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देना

राष्ट्रीय इस्पात नीति में इस्पात के उपयोग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र पर बल देकर, को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस समय देश में प्रति व्यक्ति इस्पात खपत केवल 46 कि.ग्रा. (2006) है जबकि विश्व औसत 150 कि.ग्रा. है और विकसित देशों मे यह 400 कि.ग्रा. है। इसलिए इस्पात मंत्रालय ने इस्पात के किफायती, अभिनव और व्यवहार्य सामान्य उपयोग के प्रति आम लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक राष्ट्रीय इस्पात संवर्धन अभियान शुरू करने की पहल की है। राष्ट्रीय इस्पात संवर्धन अभियान का शुभारंभ माननीय इस्पात मंत्री द्वारा 20 मार्च, 2007 को किया गया था। इस अभियान का टीवी और रेडियो पर प्रसारण किया जाता है और राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में इसे प्रकाशित किया जा रहा है। इस्पात अभियान का आगे और विस्तार किया जाएगा ताकि वास्तुविदों, डिजाइनर इंजीनियरों और बिल्डरों को फ्लाइओवरों, पुलो, विमानपत्तनों, रेलवे स्टेशन प्लेटफार्मों के साथ-साथ अन्य इंजीनियरी अनुप्रयोगों में इस्पात का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए शिक्षित किया जा सके। इस संवर्धन अभियान का सेल, आरआईएनएल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू लिमिटेड, जिंदल स्टील, एस्सार स्टील और इस्पात लिमिटेड ने समर्थन किया है।

(ii) सेल, आरआईएनएल और एनएमडीसी लि. की मेगा विस्तार योजनाएं

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सेल और आरआईएनएल ने अपनी महत्वाकंक्षी विस्तार योजनाएं शुरू की हैं। विस्तार योजनाओं से लगभग 53,000 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर 2010 तक सेल की क्षमता 14.6 मिलियन टन तप्त धातु वार्षिक से बढ़कर 26 मिलियन टन वार्षिक हो जाएगी। सेल की योजना 2020 तक क्षमता को और बढ़ाकर 60 मिलियन टन वार्षिक करने की है। आरआईएनएल के मामले में लगभग 9000 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर 2009-10 तक विस्तार योजना से तप्त धातु उत्पादन क्षमता 3 मिलियन टन वार्षिक के वर्तमान स्तर से बढ़कर 6.3 मिलियन टन वार्षिक हो जाएगी। आरआईएनएल की 2020 तक अपनी क्षमता को बढ़ाकर 16 मिलियन टन वार्षिक करने की योजना है। मौजूदा खानों के विस्तार, नई खानें खोलकर, स्पंज लोहे, पैलेट और इस्पात में मूल्यवर्धन के जरिए एनएमडीसी की 2014-15 तक अपनी मौजूदा 26 मिलियन टन वार्षिक लौह अयस्क उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 50 मिलियन टन वार्षिक करने की योजना है।

(iii) विलय एवं अधिग्रहण

विलय के जरिए सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों का पुनरूद्धार करने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा कई प्रस्ताव शुरू किए गए हैं। वर्ष के दौरान किस्को का केआईओसीएल में विलय पूरा कर लिया गया है। सेल द्वारा एनआईएनएल के अधिग्रहण और विलय, एमईएल और बीआरएल के सेल में विलय, एनएमडीसी लि. के सिल में विलय के मामले अंतिम चरण पर हैं और इनमें से अधिकांश के शीघ्र पूरा होने की संभावना है। कुल 100.72 करोड़ रूपए की लागत पर मेकॉन के पुनरूद्धार और पुनर्संरचना को सरकार द्वारा फरवरी, 2007 में मंजूरी दे दी गई। मेकॉन के एक ज्ञान आधारित कंपनी होने के कारण सरकार ने पुनरूद्धार को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड स्तर के कर्मचारियों सहित मेकॉन लिमिटेड के सभी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 66 वर्ष करने का निर्णय भी लिया है।

(iv) निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

2007-08 के लिए मंत्रालय के साथ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए गए समझौता ज्ञापनों में निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) को एक महत्वपूर्ण प्राचल के रूप में अभिज्ञात किया गया है तथा मंत्रालय द्वारा सीएसआर कार्यकलापों की कड़ाई से मॉनीटरिंग की जा रही है। लाभ कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात उपक्रमों ने सीएसआर के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है तथा सीएसआर कार्यों के लिए अपने वितरण योग्य अधिशेष की कम से कम 2 प्रतिशत राशि निर्धारित की है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में 2007-08 के लिए सीएसआर के लिए आबंटित कुल बजट लगभग 230 करोड़ रूपए है। सीएसआर कार्यों में पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सांस्कृतिम उत्थान, परिसरीय विकास, परिवार कल्याण, सामाजिक पहल पर ध्यान केंद्रित किया गया है तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अन्य उपाय किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में बाढ़ के कारण आई आपदा को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों ने इन प्रभावित

राज्यों में तत्काल राहत संबंधी उपाय किए। बाढ़ राहत उपायों के लिए सेल, एनएमडीसी और आरआईएनएल ने क्रमश: 5 करोड़ रूपए, 4 करोड़ रूपए और 2 करोड़ रूपए का अंशदान दिया। इस्पात मंत्रालय द्वारा सभी प्रमुख उत्पादकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने संयंत्रों के समीपवर्ती गांवो को अपनाएं और सीएसआर कार्यकलापों के एक भाग के रूप में उन्हें आदर्श इस्पात गांवों के रूप मे विकसित करने में सहायता करें। भंडारण टंकियों, बैल गाड़ियों, पानी के टैंकों, भवनों जैसे स्कूल भवनों पंचायत घरों, स्वास्थ्य केंद्र भवनों, प्रतीक्षा शेडों आदि में इस्पात के उपयोग पर बल दिया गया है। 129 गांवों को आदर्श इस्पात गांवो के रूप में विकसित किया जा रहा है।

(v) इस्पात का ग्रामीण वितरण नेटवर्क

आम आदमी को इस्पात की मदें उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिलें में कम से कम एक डीलर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। संपूर्ण देश में ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की आम उपयोग की मदों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सेल और आरआईएनएल देश के सभी जिलों में डीलर नियुक्त करने के उद्देश्य से तेजी से अपने वितरण नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं। जिला स्तरीय डीलरशिप आबंटित करते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़े वर्गों को तरजीह दी जाती है। इसके अलावा आम इस्पात मदें ग्रामीण क्षेत्रों में उसी मूल्य पर उपलब्ध करवाई गई हैं जो कि शहरों के स्टॉकयार्डों में है। स्टॉकयार्ड से डीलर के स्थान तक की ढुलाई की लागत सरकारी क्षेत्र के इस्पात उत्पादकों द्वारा वहन की जाती है। सेल और आरआईएनएल अपने वितरण नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। 2007 के अंत तक सेल देश के 603 जिलों में 1564 डीलर नियुक्त कर चुका है।

(vi) इस्पात मूल्य प्रबोधन समिति (एसपीएमसी) का गठन

इस्पात मंत्रालय में इस्पात मूल्य प्रबोधन समिति गठित की गई है। यह समिति इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के उत्पादों के मूल्यों के उतार-चढ़ाव को मॉनीटर करेगी, अंतर के संबंध में विचार-विमर्श करेगी और विश्लेषण करेगी, अडाप्टिव मॉडल के आधार पर भावी मूल्य के बारे में नीति बनाएगी और इस्पात उत्पादन, खपत और व्यापार के लिए नीतियों की सिफारिश करेगी।

(vii) लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना

भारतीय इस्पात संयंत्रों में अनुसंधान एवं विकास में निवेश का वर्तमान स्तर उनके कुल कारोबार के 0.2 प्रतिशत से भी कम है। लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए इस्पात मंत्रालय इस्पात विकास निधि (एसडीएफ) से विद्यमान अधिकार प्राप्त समिति तंत्र के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है। 499.53 करोड़ रूपए की लागत और 229.75 करोड़ रूपए की एसडीएफ राशि से 59 अनुसंधान परियोजनाएं सरकारी और निजी उपक्रमों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक और अन्य संवर्धनात्मक संस्थानों द्वारा शुरू की जा चुकी है। अनुसंधान क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ अयस्कों का सज्जीकरण, उत्पादकता में सुधार, नए/क्वॉलिटी उत्पादों का विकास, मानव संसाधनों का विकास, भारतीय लोहा और इस्पात संयंत्रों में

ऊर्जा खपत तथा प्रदूषण में कमी शामिल हैं। इनमें से पूरी हुई कुछ परियोजनाओं से लोहा और इस्पात उद्योग को पहले ही लाभ मिल रहा है।

(viii) चुनिंदा इस्पात मदों के संबंध में मेंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर

उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाला इस्पात उपलब्ध करवाने के लिए मंत्रालय ने घरेलू उपयोग में तथा निर्माण में उपयोग किए जाने वाले 17 इस्पात उत्पादों तथा भारतीय मानक ब्यूरा अधिनियम 1986 के अंतर्गत अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणन के लिए अन्य महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों की पहचान की है। इससे उपभोक्ताओं को ऐसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए गुणवत्ता वाले इस्पात पर बल देने तथा दोयम दर्जे के उत्पादों की आपूर्ति के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए अधिकार भी प्राप्त होंगे। इस संबंध में दिनांक 12.11.2007 को उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा एक औपचारिक गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी आदेश जारी किया गया है तथा इसे शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा।

(ix) क्लीन डवलपमेंट मैकेनिज्म (सीडीएम) के अंतर्गत किए गए प्रयास

सीडीएम दीर्घकाल तक चलने वाली तथा पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कनवेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के क्योटो प्रोटाकॉल के तहत की गई फ्लैग्जिबल व्यवस्थाओं में से एक है। केंद्रीय सरकार ने नेशनल सीडीएम अथॉरिटी (एनसीडीएमए) का गठन किया है जो उपयुक्त परियोजनओं को मेजबान देश का अनुमोदन (एचसीए) प्रदान करती है। अब तक लगभग 700 परियोजनाओं को एचसीए प्रदान किया गया है जिसमें भारत में लोहा एवं इस्पात संयंत्रों से 58 प्रस्ताव शामिल हैं। इन परियोजनाओं से ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) में 58.5 मिलियन टन कार्बनडाईऑक्साइड (सीओ 2) के बराबर कमी होगी जिससे (वर्ष 2012 तक) 66 मिलियन टन सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन का सृजन होगा। जिसका महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार किया जा सकता है। इस प्रकार कंपनियों के साथ-साथ देश को भी महत्वपूर्ण ढंग से लाभ होगा।

(x) लौह अयस्क चूरे के अधिकतर उपयोग के संबंध में

लौह अयस्क के उत्खनन से डला अयस्क के अतिरिक्त कम से कम 50 प्रतिशत चूरे का सृजन होता है जिसका उपयोग लोहे के उत्पादन में किया जाता है। जब तक इस चूरे को एकत्रित नहीं किया जाता तब तक या तो इसका निर्यात किया जाता है या फिर इसके ढेर लगने से पर्यावरण संबंधी खतरे होंगे। पर्याप्त सिंटरिंग पैलेटाइजेशन क्षमता नहीं होने के कारण इस्पात संयंत्र अधिकांशत: डला अयस्क पर निर्भर होते हैं तथा आमतौर पर चूरे का निर्यात किया जाता है। इसलिए वित्तीय रियायत/प्रोत्साहन के जरिए सिंटरिंग तथा पैलेटाइजेशन क्षमता विकसित करना चिंता का विषय है। इस संबंध में सरकार घरेलू पैलेटाइजेशन क्षमता की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही है। आर्थिक अनुसंधान इकाई (ईआरयू) के जरिए भारत मे लौह अयस्क चूरा उपयोगिता पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है तथा महत्वपूर्ण शेयरधारकों को परिचालित की गई है। यह रिपोर्ट लौह अयस्क (डले और चूरा दोनों) की खपत के साथ-साथ घरेलू उत्पादन, निर्यात तथा चूरे के घरेलू स्तर पर उपयोग

को बढ़ावा देने के लिए नीतिपरक सिफारिशों के साथ चूरे की उपयोगिता से संबंधित अड़चनों पर अभिकेंद्रित है। रिपोर्ट में सम्मिलित सिफारिशों पर मंत्रालय विचार कर रहा है। अध्ययन के अनुसार देश में इस्पात उत्पादन में चूरे का शेयर 2005-06 के दौरान 52.2% से ओर बढ़कर 2011-12 तक 69.5% और 2019-20 तक लगभग 72% होने की संभावना है। घरेलू लौह अयस्क चूरे के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इस्पात मंत्रालय ने भारत में लौह अयस्क के सज्जीकरण और समामेलन (सिंटरिंग एवं पैलेटाइजेशन) को बढ़ावा देने के लिए मौद्रिक और अन्य उपायों की सिफारिश की है।

(xi) <u>अवसंरचनात्मक अड़चनों को दूर करना</u>

इस्पात क्षेत्र को रेलवे संबंधी सुविधाएं देने में महत्वूपर्ण अड़चनों की पहचान करने के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसमें इस्पात उद्योग, इस्पात मंत्रालय तथा रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आर्थिक अनुसंधान इकाई (ईआरयू) के जरिए 11वीं योजना में इस्पात क्षमता के प्रस्तावित विस्तार हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं की पर्याप्तता पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में इस्पात क्षमता में प्रस्तावित विस्तार, विशेष तौर पर उड़ीसा, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, को पूरा करने के लिए परिवहन (रेलवे, सड़क तथा पत्तन), जल संसाधन तथा विद्युत संबंधी अवसंरचनात्मक आवश्यकता पर केंद्रित है। रिपोर्ट में शामिल सिफारिशें मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

(xii) <u>कच्चे माल की ढुलाई के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं</u>

रावघाट तथा दल्ली राजहरा लौह अयस्क खानों के बीच संपर्क के लिए दल्ली राजहरा से जगदलपुर वाया रावघाट तक 235 कि.मी. लंबी रेलवे लाइन के लिए भारतीय रेल, छत्तीसगढ़ सरकार, एनएमडीसी तथा सेल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस नई रेलवे लाइन से लौह अयस्क, खनिजों, इस्पात खाद्य सामग्री तथा वन उत्पादों के परिवहन में सुविधा मिलेगी।

3.2 स्त्री सशक्तिकरण हेतु वित्त मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निदेशानुसार मंत्रालय में एक जेंडर बजट सेल स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य मंत्रालय में जेंडर बजट की अवधारणा को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाना है। तथापि, वर्ष 2006-07 तक इस्पात मंत्रालय की कार्यान्वित की जाने वाली कोई योजना नहीं है। फिर भी लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की प्रोन्नति की नई योजनाओं में 11वीं योजना में अनुमोदित नई योजनाएं शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे जिससे प्रत्यक्ष रूप से एक लाभ भोगी समूह के रूप में महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सकता है।

4. लोहा और इस्पात उद्योग कार्यदल की सिफारिशें

11वीं योजना अवधि इस क्षेत्र के विकास को न केवल बनाए रखने अपितु विकास में सुधार करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मई, 2006 में योजना आयोग द्वारा सचिव, इस्पात मंत्रालय की अध्यक्षता में 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के लिए इस्पात उद्योग कार्यदल

गठित किया गया है। कार्यदल की प्रथम बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 11वीं योजना के लिए विकास नीति तैयार करने से पूर्व इस्पात उद्योग से संबंधित मुद्दों का विस्तार से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तदनुसार दो उप दल गठित किए गए। उप दल-।। लोहे और इस्पात की मांग और पूर्ति तथा उप दल-। प्रौद्योगिकीय मुद्दों के लिए था। कार्य दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट दिसम्बर, 2006 में योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी। कार्यदल की टिप्पणियों और निष्कर्षों के आधार पर तथा राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 की भावना और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारत को न केवल लागत, गुणवत्ता और उत्पाद-मिश्र की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु अपितु दक्षता और उत्पादकता के अन्तर्राष्ट्रीय बेन्चमार्कों की दृष्टि से भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र अभिज्ञात किए गए हैं जहां सरकार द्वारा समर्थन संबंधी उपाय उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

4.1 मांग संबंधी प्रबंधन

सभी शेयरधारकों के लिए एक प्रमुख चिन्ता का विषय भारत में इस्पात की वर्तमान प्रति व्यक्ति खपत कम होना है। आय स्तर बढ़ने, शहरीकरण और अवसंरचना के विकास से प्रतिव्यक्ति खपत में सुधार होने की आशा है जबकि घरेलू मांग में वृद्धि करने तथा खपत क्षमता सृजित करने के लिए काफी प्रयास करने की आवश्यकता है। इस्पात की मांग में वृद्धि की संभावनाओं को निम्नलिखित के जरिए वास्तविकता में बदला जा सकता है:

(i) वास्तुविदों, इंजीनियरों, विद्यार्थियों और अन्य प्रौद्योगिकी प्रैक्टिशनरों और इस्पात के प्रयोक्ताओं में इस्पात के उत्पादकों और इंस्टीट्यूट आफ स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (आई एन एस डी ए जी) द्वारा इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देना।

(ii) पुलों, क्रैश बैरियरों, सेतुओं, औद्योगिक और अन्य भवनों तथा सामान्य रूप से बड़े पैमाने पर निर्माण में इस्पात के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।

(iii) इस्पात प्रयोगों का विस्तार करने के लिए नए ग्रेड और उत्पाद विकसित करना।

(iv) इस्पात की उपलब्धता और वहनीयता में सुधार करना।

तथापि वास्तविक चुनौती विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भी इस्पात की खपत असमानताओं में है। विभिन्न पहलों जैसे भारत निर्माण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आदि के अन्तर्गत प्रयासों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ये कार्यक्रम खराब अवसंरचना और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान कम आय स्तरों की समस्याओं का समाधान करेंगे। वहन करने योग्य मूल्य पर गृह निर्माण और कृषि/कृषि उद्योग के लिए अपेक्षित इस्पात उपलब्ध कराने के लिए विशिष्ट नीतियों की आवश्यकता है। 11वीं योजना में देश के सभी भागों में इस्पात की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए नए ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण स्टॉक केन्द्र खोलने पर काफी बल दिए जाने की आवश्यकता है।

4.2 पूर्ति संबंधी प्रबंधन

(i) कच्चा माल

नियंत्रणमुक्त इस्पात उद्योग मूल्यों के उच्च संतुलन के जरिए कमी की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान करती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना बनाते समय डाउनस्ट्रीम आर्थिक कार्यकलापों के लिए इस्पात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरी तरह से ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यद्यपि घरेलू आवश्यकताओं को प्राथमिकता से पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे तथा उभरते निर्यात अवसरों का लाभ उठाना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए 11वीं योजना में इस्पात की बढ़ती हुई घरेलू मांग और निर्यात आवश्यकता को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण आदानों की उपलब्धता की योजना बनाई जानी चाहिए।

महत्वपूर्ण कच्चे माल जैसे लौह अयस्क, कोककर/अकोककर कोयला, फैरो मिश्र आदि की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए यह वांछनीय है कि कानूनी, नीति और संस्थागत ढ़ांचे में से प्राथमिकता देकर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सामग्री दक्षताओं में सुधार करके और स्वदेशी रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए इसे संभव बनाकर नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

(ii) अवसंरचना

इस्पात क्षेत्र के लिए अवसंरचना अर्थात् विद्युत, रेलवे, राजमार्ग, पत्तन और तटीय जहाजरानी सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की आवश्यकता है क्योंकि एक तरफ काफी बड़े स्तर पर निवेश के कारण इस्पात कंपनियों द्वारा अपेक्षित ढ़ांचा विकसित करना व्यवहार्य नहीं है और दूसरी तरफ कंपनियों द्वारा अनिवार्य नकद प्रवाह को बनाए रखने की आवश्यकता है। तथापि निजी विद्युत संयंत्रों, जैट, सड़कों और रेलवे के लिए कार्य करने वाली कई इस्पात कंपनियों द्वारा सरकारी संसाधनों की कमी दर्शाई गई है। बड़ी इस्पात कंपनियों द्वारा इस प्रकार का कुछ निवेश अपरिहार्य है। इसलिए ढ़ांचागत विकास का बोझ पूरी तरह से इस्पात कंपनियों पर नहीं डाला जाना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ कंपनियाँ अनिश्चितताओं से बचने और दीर्घकालीन लागत कम करने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष रूप से सरकारी-निजी भागीदारी की इच्छुक होंगी। शेयर-धारकों के लाभ के लिए सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपीएस) के विद्यमान नीतिगत ढ़ांचे का पूर्णत: उपयोग करने की आवश्यकता है।

(iii) नए निवेश

वर्ष 2011-12 तक अतिरिक्त इस्पात क्षमताओं को सृजित करने में देश को 1 लाख करोड़ रूपए से 1.2 लाख करोड़ रूपए के निवेश की आवश्यकता होगी। खनन और विद्युत जैसे संगत क्षेत्रों के लिए 25,000 से 30,000 करोड़ रूपए के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी। इस्पात परियोजनाओं के लिए वित्त की सप्लाई अलग-अलग परियोजनाओं के गुण-दोषों के आधार पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्धारित की जाएगी जबकि 11वीं योजना में इस्पात क्षेत्र में परिकल्पित क्षमता बढ़ाने को सुनिश्चित करने के लिए वृहत स्तर पर

वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त धन का निवेश करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अभिनव प्रयोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रणाली को बनाए रखने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी विकास और से अपनाने के काफी क्षेत्र हैं जो जोखिमपूर्ण हो सकते हैं परन्तु वे अच्छा रिकार्ड देने वाले भी हैं। उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को शीघ्र अपनाने के लिए उद्यम पूंजीकरण को तीव्र गति से बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

4.3 प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

तकनीकी दक्षता के प्राचलों में निरन्तर सुधार के जरिए ही इस्पात उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुनिश्चित किया जा सकता है तथा इसे बनाए रखा जा सकता है। ऐसे काफी क्षेत्र हैं जहां भारतीय इस्पात उद्योग पिछड़ रहा है। तथापि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां उद्योग अग्रणी भूमिका अदा करने में सक्षम है। ये समस्याएं मुख्य रूप से अपनाई गई प्रौद्योगिकियों के अप्रचलन तथा समय पर आधुनिकीकरण/पुनर्रुद्धार नहीं होने, कच्ची सामग्री और अन्य आदानों की गुणवत्ता, अपर्याप्त शॉप फ्लोर प्रक्रियाओं, आटोमेशन और आर एंड डी की कमी से संबंधित हैं। भारतीय इस्पात उद्योग उनके विदेशी सहयोगियों के स्तर पर लाने के लिए कार्रवाई के कार्यक्रमों पर काफी प्रयास करने की आवश्यकता है।

4.4 पर्यावरण प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण

कच्चे माल से लेकर परिसज्जित इस्पात चरण तक लोहा और इस्पात उत्पादन के लिए अपनाई गई प्रौद्योगिकी तथा अन्ततः सृजित उप-उत्पादों तथा अपशिष्ट के दक्षतापूर्ण निपटान/पुनः उपयोग को अनिवार्य रूप से लोहा और इस्पात संयंत्रों में पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए उत्पादन प्रक्रियाओं तथा संयंत्र के आस-पास के परिवेश को शामिल करते हुए एकीकृत दृष्टिकोण के लिए पर्यावरण के प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में उद्योग और सरकार का उद्देश्य शून्य अपशिष्ट/शून्य बहिस्राव होना चाहिए।

अपशिष्ट विशेष रूप से ढोस अपशिष्ट अपरिहार्य रूप से लाभपूर्ण मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। दूसरे शब्दों में सतत विकास प्रौद्योगिकी विकास और डिजाईन स्तर से ही शुरू किया जाना चाहिए। भविष्य में यह सुनिश्चित में यह सुनिश्चित किया जाए कि वे प्रौद्योगिकियाँ जो बने रहने योग्य नहीं हैं, न तो विद्यमान संयंत्रों के विस्तार और न ही नई क्षमताओं के सृजन के लिए अपनाई जानी चाहिएं। इन उद्देश्यों के लिए उद्यमियों और सरकार दोनों के स्तर पर उपयुक्त हस्तक्षेप के जरिए पहल करने के लिए आवश्यक है।

4.5 सुरक्षा उपाय

भारत में लोहा और इस्पात उद्योग में सुरक्षा की स्थिति में समग्र रूप से सुधार करने हेतु निम्नलिखित उपचारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है:-

(i) कानूनी सिस्टम को सुदृढ़ करना ताकि सुरक्षा नीति में उल्लंघन की कोई भी घटना चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो अथवा निजी क्षेत्र में हो, बिना दण्ड दिए नहीं रहनी चाहिए। तदनुसार फैक्टरी निरीक्षक, सुरक्षा अधिकारी और कानूनी ढ़ांचे की प्रणाली को सुधारना होगा। प्रौद्योगिकियों/कार्य परिवेश में हुए बदलावों को ध्यान रखने के लिए कानूनी प्रावधानों में उन्नयन किया जाना चाहिए ताकि जहां तक संभव हो सके, खामियों को दूर किया जा सके।

(ii) सभी संयंत्रों में आई एल ओ दिशा निर्देशों के अनुसार ओ एच एस प्रबंधन प्रणाली और ओ एच एस ए एस 18001 अपनाई जानी चाहिए।

(iii) भारत में कुछ इस्पात संयंत्रों में अब भी कई पुरानी प्रौद्योगिकियाँ अर्थात् ट्विन हर्थ फर्नेश, इंगाट मेकिंग आदि प्रचालनरत हैं। ये प्रक्रियाएं वहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खतरनाक हैं और इस प्रकार के संयंत्रों में सुरक्षा में सुधार करने हेतु इन प्रक्रियाओं को तत्काल बन्द किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त नई प्रौद्योगिकियों का विकास सुरक्षित कार्य परिवेश उपलब्ध कराने में सहायक होगा।

(iv) अन्तर्निहित जोखिम/खतरे का बेहतर ढंग से आंकन करने के लिए सभी संयंत्रों में अग्नि माडलिंग और जोखिम विश्लेषण का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

4.6 मूल्यों में स्थिरता

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एकीकरण के लिए समय के साथ इस्पात के मूल्यों में तेजी से वृद्धि और उतार-चढ़ाव आ सकता है। इस उतार-चढ़ाव का एक भाग अपरिहार्य है जबकि कारोबार की स्थिरता में वृद्धि करने के लिए ग्राहकों को हैजिंग मैकेनिजम उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंच (एम सी एक्स) और नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज (एन सी डी ई एक्स) जैसे विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में इस संबंध में पहले ही शुरूआत हो चुकी है। यह राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 में अपनाई गई सिफारिशों के अनुसार है। जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, मूल्य युक्तिसंगतिकरण की मानिटरिंग करने, मूल्यों में उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करने तथा इस्पात जिंस के अयुक्तिसंगत मूल्य के बारे में सभी संबंधित को सलाह देने के प्रयोजन से इस्पात मंत्रालय द्वारा पहले ही **च्इस्पात मूल्य प्रबोधन समितिछ** गठित की जा चुकी है।

4.7 आंकड़ों के संग्रहण और जानकारी के प्रचार-प्रसार करने के लिए संस्थागत ढ़ांचा

आंकड़ों/सूचना के संग्रहण, वैधता, विश्लेषण और प्रचार-प्रसार के लिए विद्यमान संस्थागत तंत्र में तत्काल सुधार करने की आवश्यकता है। इस्पात उद्योग के नियंत्रणमुक्त होने से आंकड़ों का संग्रहण विशेष रूप से क्षमता और उत्पादन से संबंधित सूचना संग्रहित करना अब काफी जटिल हो गया है। सभी शेयरधारकों, नीति निर्माताओं, फर्मों, वित्तीय संस्थानों और उपभोक्ताओं द्वारा संसूचित निर्णय लेने की सुविधा हेतु एक विश्वसनीय और प्रभावी आंकड़ा आधार तैयार करने को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कानूनी प्रावधान/संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है। विद्यमान संस्था नामतः संयुक्त

संयंत्र समिति (जेपीसी) तथा आर्थिक अनुसंधान इकाई (ईआरयू) को इस प्रयोजन के लिए सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, विद्यमान संस्थाओं नामतः संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) तथा आर्थिक अनुसंधान इकाई (ईआरयू), इंस्टिट्यूट फॉर स्टील डवलपमेंट एंड ग्रोथ (आईएनएसडीएजी), नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सैकेण्ड्री स्टील टैक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी) तथा बीजू पटनायक नेशनल स्टील इंस्टिट्यूट (बीपीएनएसआई) को सार्वभौमिकीकरण की बदली हुई वास्तविकताओं के अनुरूप रिओरियेंटिड करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में इस देश में इंटरनेशनल आयरन एंड स्टील इंस्टिट्यूट (आईआईएसआई) के अनुसार एक मल्टीडिसीपलीनरी ऑर्गेनाईजेशन स्थापित करने पर भी विचार किया जा सकता है।

5. <u>नीतिगत पहलों से निष्कर्ष बजट की संगतता</u>

इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में चालू योजनाओं/परियोजनाओं तथा 11वीं योजना के दौरान शुरू की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं/परियोजना जैसे क्षमता विस्तार, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, लौह अयस्क तथा कोककर कोयला खानों का अधिग्रहण/विकास अनुसंधान एवं विकास योजनाओं, नए स्लैब कास्टर की स्थापना, कोक ओवन बैटरी का पुनर्निर्माण, ए एम आर योजनाओं आदि से संयंत्रों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, गुणवत्ता तथा उत्पाद-मिश्र में सुधार होगा और उत्पादन की लागत में कमी होगी। अवधारणा पर बल देने सहित निष्कर्ष बजट की अवधारणा, रूपांकन, निष्कर्षोन्मुखी योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यक्रम और सुदृढ़ परियोजना/कार्यक्रम तैयार करने की अपेक्षा, क्षमताओं का मूल्यांकन तथा प्रभावी सुपुर्दगी प्रणाली से वास्तविक परिसम्पत्तियों और जनशक्ति के बेहतर उपयोग की संभावना है, परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन में सुधार होने, तथा प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने की आशा है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की योजनाओं/कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन से भारतीय इस्पात उद्योग के न केवल लागत, गुणवत्ता और उत्पाद मिश्र की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने अपितु दक्षता और उत्पादकता के अन्तर्राष्ट्रीय बेन्चमार्कों जो राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 में परिकल्पित उद्देश्य एवं लक्ष्य हैं, में भी योगदान देगी।

****

अध्याय IV

पिछले निष्पादन की समीक्षा-निष्कर्ष बजट 2007-08

निष्कर्ष बजट 2007-08 इस्पात मंत्रालय की योजना और गैर-योजनागत योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में तैयार किया गया था। 10वीं योजना (2002-07) तक इस्पात मंत्रालय को प्रत्यक्ष रूप से किसी योजना का कार्यान्वयन नहीं करना था। 11वीं योजना (2007-11) में "लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना" नामक एक नई योजना को 118.00 करोड़ रुपए के प्रावधान सहित घरेलू लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए शामिल किया गया है। फिलहाल यह योजना तैयार किए जाने के चरण में है। इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने-अपने प्रचालनों के क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम बनाते हैं और कार्यान्वित करते हैं। योजना के स्वरूप पर निर्भर करते हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की योजनागत योजनाएं उनकी वार्षिक योजना अथवा पंचवर्षीय योजनाओं अथवा दोनों की घटक होती हैं। प्रत्येक उपक्रम की अपनी-अपनी कई योजनाएं हैं। अधिकांश योजनाएं कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों और प्रचालनों से संबंधित हैं। इसलिए यह महसूस किया गया है कि इस्पात मंत्रालय के निष्कर्ष बजट में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सभी योजनाओं को शामिल करना न तो व्यवहारिक होगा और न ही निष्कर्ष बजट के उद्देश्य के अनुरूप होगा। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इस्पात मंत्रालय के निष्कर्ष बजट में केवल 50 करोड़ रूपए से अधिक लागत की मंजूर/अनुमानित लागत की प्रमुख योजना और गैर-योजनागत योजनाओं को ही शामिल किया जाए। इस मानदंण के आधार पर 31 योजनागत योजनाओं (सेल की 17 योजनाओं, आरआईएनएल की 7, केआईओसीएल की 3 और एनएमडीसी की 4 योजनाओं) तथा एक गैर-योजनागत योजना (एचएससीएल के संबंध में) को निष्कर्ष बजट 2007-08 में शामिल किया गया था। इन 32 योजनाओं के संबंध में निष्कर्ष बजट, 2007-08 में दर्शाए गए अभिप्रेत निष्कर्षों की तुलना में संयंत्र-वार वास्तविक उपलब्धियां (31 दिसंबर, 2007 तक) और 50.00 करोड़ रूपए से अधिक अनुमानित/मंजूर लागत वाली योजनाएं निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं। यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश प्रमुख योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं अत: इन योजनाओं की उपलब्धियों का अपेक्षाकृत अधिक सार्थक और वास्तविक मूल्यांकन इन योजनाओं के पूरा किए जाने के बाद ही संभव है।

अनुमानित निष्कर्षों/लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियां

3.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

(करोड रूपए)

सं	पीएसयू का नाम तथा योजना/ कार्यक्रम	लक्ष्य /निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	अनुमोदित परिव्यय* 2007-08		मात्रात्मक सुपुर्दगीयोग्य/ वास्तविक उत्पादन	प्रासेसिज/टाईमलाईन्स		वास्तविक व्यय		अनुमानित निष्कर्ष/ कॉलम 7 के संदर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां जोखिम घटक
				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान		मूल	वास्तविक/ अब निर्धारित किया गया	अप्रै-दिसं. 2007 के लिए	दिसं, 2007 तक संचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**भिलाई इस्पात संयंत्र**											
(i)	वायर रॉड मिल के बी-स्ट्रैण्ड की मरम्मत	सुधरी गुणवत्ता सहित टीएमटी ग्रेड तथा स्मालर सैक्शन के वायर रॉड के उत्पादन को सुसाध्य बनाना।	74.66	14.80	5.00	5.5 से 7.0 एमएम में टीएमटी ग्रेड तथा स्मॉलर सैक्शन के वायर रॉड के उत्पादन को सुसाध्य बनाना।	मई, 06	दिसं, 06	4.10	61.12	वर्ष 2007-08 (जन,08 तक) के दौरान तुलनात्मक लघु क्षेत्रों सहित टीएमटी ग्रेड के वायर रॉड का संचित उत्पादन 0.522 एमटी है।	पूरा कर लिया गया है।
(ii)	कोक ओवन बैटरी-5 का पुनर्निर्माण	सुधरी गुणवत्ता को बढ़ाना तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नवीनतम उत्सर्जन मानदंडों को प्राप्त करना।	219.04	116.48	77.60	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अद्यतन प्रदूषण अनुदेशों द्वारा पुनर्निर्माण	जन, 07	जुलाई,08	46.35	102.80	--	- मैसर्स सीयूआई/जिपरोकोज/केबीके द्वारा सिविल तथा व्यापक इंजी. ड्राइंगों में देरी के कारण कार्यक्षेत्र के कार्य में विलंब हुआ। - सीयूआई तथा संघ साझ ीदारों में समन्वय की कमी के कारण आपूर्ति तथा उन्नयन कार्य पर प्रभाव पड़ा।

(iii)	प्लेट मिल में हाईड्रोलिक गेज कंट्रोल तथा प्लान व्यू रोलिंग की स्थापना।	ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक क्लोजर थिकनैस टोलरैंस, लैस क्रोप कटिंग एंड साईंड ट्रिमिंग को हासिल करना तथा प्लेटों के उत्पादन में सुधार करना।	64.10	12.33	6.10	ग्राहकों की जरूरत के अनुसार गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आवश्यक।	जुलाई,06	मार्च, 07	0.01	43.66	स्टैबलाईजेशन के अंतर्गत।	नवंबर, 06 में सेमी ऑटो मोड पर पूर्ण। परीक्षण संचलन के दौरान आई समस्याएं चिन्हित की गई तथा उन्हें दूर किया गया।
(iv)	बीएफ-7 का प्रौद्योगिकीय उन्नयन	उपयोगी मात्रा एवं उत्पादकता को बढ़ाना।	170.41	26.63	16.86	उपयोगी मात्रा में 2000 एम3 से 2214 एम3 तक की वृद्धि होगी।	अग,06	फर, 07	12.90	155.47	उपयोगी मात्रा में 2365 एम3 तक वृद्धि पूरी कर ली गई।	पूरा कर लिया गया है।

(करोड रुपए)

सं	पीएसयू का नाम तथा योजना/ कार्यक्रम	लक्ष्य /निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	अनुमोदित परिव्यय* 2007-08		मात्रात्मक सुपुर्दगीयोग्य/ वास्तविक उत्पादन	प्रासेसिज/टाईमलाईन्स		वास्तविक व्यय		अनुमानित निष्कर्ष/ कॉलम 7 के संदर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां जोखिम घटक
				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान		मूल	वास्तविक/ अब निर्धारित किया गया	अप्रै-दिसं. 2007 के लिए	दिसं, 2007 तक संचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(v)	नई स्लैब कास्टर, आरएच डिगैसर तथा लैडल फर्नेस की स्थापना	भारतीय रेलवे के लिए निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली प्लेटों तथा पटरियों के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए मूल्यवर्धित/विशेष गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन करना।	520.76	299.19	239.22	अतिरिक्त कास्टिंग 0.165 एमटीपीए। एपीआई X65/X70 ग्रेड - 3,00,000टी	सितं., 07	जून,08	195.02	328.76	--	- 7.2.08 से एलएफ में हॉट ट्रायल्स किए जा रहे हैं। आरएच डिगैसर के लिए हॉट ट्रायल्स एवं प्रचालन मार्च, 08 में चालू किया जाएगा। - स्लैब कास्टर के लिए मैसर्स डिनियली एंड कं., इटली ने आपूर्ति एवं उन्नयन में विलंब किया। - ठेकेदारों द्वारा अपर्याप्त संसाधन संघटन ने भी कार्यस्थल पर कार्य पर प्रभावित किया।
(vi)	एसएमएस में तप्त धातु डिसल्फयूराईजेशन	विशेष रूप से ऑफ-शोर, परिवहन तथा अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में अनुप्रयोग हेतु, उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए कम सल्फर वाले इस्पात के उत्पादन की सुविधा प्रदान करना।	86.23	54.24	53.88	तप्त धातु में सल्फर के स्तर में 0.1% से 0.01% तक की कमी।	अग. 07	मार्च, 08	30.69	43.81	--	- फ्यूम एक्सट्रैक्शन (एफई) सिस्टम के संदर्भ में दिसं, 07 में प्रचालन शुरू। - एफई प्रणाली के लिए एकीकृत हॉट ट्रायल जन, 08 में शुरू हुए। यह इकाई संघटन के अंतर्गत है।

2.	**दुर्गापुर इस्पात संयंत्र**											
(i)	सम्बद्ध सुविधाओं सहित ब्लूम कास्टर की स्थापना	विशेष रूप से ऑफ-शोर, परिवहन तथा अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में अनुप्रयोग हेतु, उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात के उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करना।	271.41	45.84	50.00	कास्ट ब्लूम-0.85 एमटीपीए	मई, 06	अग, 07	29.63	234.28	अगस्त, 07 से नियमित आधार पर हीट्स की कास्टिंग शुरू हो गई है। फरवरी, 08 तक इसका उत्पादन किया गया। यह उत्पादन अभी भी संघटन के अंतर्गत है।	पूरा कर लिया गया है।

(करोड स्पए)

सं	पीएसयू का नाम तथा योजना/ कार्यक्रम	लक्ष्य /निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	अनुमोदित परिव्यय* 2007-08		मात्रात्मक सुपुर्दगीयोग्य/ वास्तविक उत्पादन	प्रासेसिज/टाईमलाईन्स		वास्तविक व्यय		अनुमानित निष्कर्ष/ कॉलम 7 के संदर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां जोखिम घटक
				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान		मूल	वास्तविक/ अब निर्धारित किया गया	अप्रै-दिसं. 2007 के लिए	दिसं, 2007 तक संचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(ii)	बीएफ-3 व 4 में कोल डस्ट इंजेक्शन	प्रौद्योगिकीय जरूरत के मुताबिक कोक दर में कमी तथा फर्नेस उत्पादकता में सुधार	74.22	44.30	46.00	1:1 के अनुपात के आधार पर कोक का पुल्वेराईज्ड कोल में प्रतिस्थापन। 120 किग्रा /टीएचएम की दर से ब्लास्ट फर्नेस में कोल इंजेक्शन दर।	अग. 07	अप्रैल, 08	31.95	43.20	--	- मैसर्स श्रीराम ईपीसी द्वारा उपस्कर उन्नयन में विलंब। - सीडीआई इकाई मार्च, 08 में तैयार होगी, अप्रैल,08 में प्रचालन चालू होगा ताकि बीएफ उत्पादन पर प्रभाव न पड़े।
3.	**बोकारो इस्पात संयंत्र**											
(i)	कोक ओवन बैटरी-5 का पुनर्निर्माण	उत्पादन में सुधार करना तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नवीनतम प्रदूषण मानदंडों को प्राप्त करना ।	198.84	62.54	46.00	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अद्यतन प्रदूषण अनुदेशों द्वारा पुनर्निर्माण	जन 07	सित 07	38.66	161.86	पुनर्निर्माण के बाद उत्सर्जन मापदंड प्राप्त किए गए।	पूरा कर लिया गया है।

(ii)	हॉट स्ट्रिप मिल में मीवैस्ट ब्लॉक सिस्टम तथा हाऊसिंग मशीनिंग में संशोधन/मरम्मत कार्य ।	हॉट स्ट्रिप की समग्र गुणवत्ता के साथ-साथ उत्पादन में सुधार करना तथा हॉट स्ट्रिप मिल के सुचारू रूप से कार्य करने को सुनिशिचित करना ।	91.86	36.50	25.00	बार-बार होने वो ब्रेकडाऊन से बचने के लिए तथा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तकनीकी आवश्यकता।	जून, 07	मई 08	24.80	69.08	--	- हाई सीज में कंटेनर की गिरावट के कारण मशीनी उपकरणों के उपलब्ध न होने के कारण सितं, 06 में मैसर्स वीएआई निर्धारित शटडाऊन का उपयोग नहीं कर सका। - चरण-। का कार्य जून, 07 में शुरू नहीं हुआ। - चरण-।। आपूर्ति पूरी कर ली गई। - अगले शट डाऊन के दौरान उत्थापन योजना बनाई गई।

(करोड स्पए)

सं	पीएसयू का नाम तथा योजना/ कार्यक्रम	लक्ष्य /निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	अनुमोदित परिव्यय* 2007-08		मात्रात्मक सुपुर्दगीयोग्य/ वास्तविक उत्पादन	प्रासेसिज/टाईमलाईन्स		वास्तविक व्यय		अनुमानित निष्कर्ष/ कॉलम 7 के संदर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां जोखिम घटक
				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान		मूल	वास्तविक/ अब निर्धारित किया गया	अप्रै-दिसं. 2007 के लिए	दिसं, 2007 तक संचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(iii)	ऑक्सीजन संयंत्रों में एयर टर्बो कम्प्रैसर (एटीसी) तथा ऑक्सीजन टर्बो कम्प्रैशर (ओटीसी)	भविष्य में नियमित आधार पर उपस्करों के अनुरक्षण तथा ऑक्सीजन संयंत्र के उत्पादन को बनाए रखने के लिए तकनीकी आवश्यकता।	81.76	61.71	25.00	एटीसी क्षमता 90,000 टनएम3/घंटा तथा ओटीसी क्षमता 15000 एनएम3/घंटा	नवं, 07	जुलाई, 08	5.40	12.61	--	प्रचालनात्मक अपेक्षाओं के चलते सिलेंडर फिलिंग को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका इसलिए संभाल में विलंब।

(iv)	बीएफ-3 व 4 में कोल डस्ट इंजेक्शन	प्रौद्योगिकीय जरूरत के मुताबिक कोक दर में कमी तथा फर्नेस उत्पादकता में सुधार	133.92	72.83	25.00	1:1 के अनुपात के आधार पर कोक का पुल्वेराईज्ड कोल में प्रतिस्थापन। 120 किग्रा /टीएचएम की दर से ब्लास्ट फर्नेस में कोल इंजेक्शन दर।	मई, 08	जुलाई,08	23.58	30.63	--	विस्तार योजना के अंतर्गत एसएमएस-3 के कार्यस्थल निर्धारित करने के चलते कोल संभाल एंड भंडारण स्थल के पुनः स्थापन में विलंब
(v)	कोयला संभाल संयंत्र में कोककर कोयला भंडारण सुविधाएं	कोयला संभाल में कोककर कोयले की भंडारण की सुविधाओं में वृद्धि।	134.00	50.00	18.00	भंडारण क्षमता में 115000 टन से 202500 टन की वृद्धि	मार्च 08	अक्तू 08	15.12	19.96	--	- डिजाइन इंजीनियरी तथा मैसर्स भेल द्वारा उपस्करों की आपूर्ति में विलंब - मैसर्स बीएसबीके द्वारा सिविल कार्य में विलंब।
4.	**राउरकेला इस्पात संयंत्र**											
(i)	कोक ओवन बैटरी-1 का पुनर्निर्माण	उत्पादन में सुधार करना तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नवीनतम प्रदूषण मानदंडों को प्राप्त करना ।	112.39	12.43	7.00	--	मार्च, 05	मई, 07	3.62	98.58	पुनर्निर्माण के पश्चात उत्सर्जन मानदंड प्राप्त किए गए।	पूरा कर लिया गया है। पीजी जांच कार्य चल रहा है।
(ii)	एसएमएस में तप्त धातु डिसल्फ्यूराईजेशन	विशेष रूप से तटीय, परिवहन और अवसंरचना क्षेत्रों में अनुप्रयोग हेतु उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए कम सल्फर वाले इस्पात के उत्पादन को सुविदाप्रद बनाना।	52.39	35.00	15.00	तप्त धातु में सल्फर के स्तर में 0.1% से 0.01% की कमी	मई, 08	मई 08	14.80	21.94	--	--

(करोड स्पए)

सं	पीएसयू का नाम तथा योजना/ कार्यक्रम	लक्ष्य /निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	अनुमोदित परिव्यय* 2007-08		मात्रात्मक सुपुर्दगीयोग्य/ वास्तविक उत्पादन	प्रासेसिज/टाईमलाईन्स		वास्तविक व्यय		अनुमानित निष्कर्ष/ कॉलम 7 के संदर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां जोखिम घटक
				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान		मूल	वास्तविक/ अब निर्धारित किया गया	अप्रै-दिसं. 2007 के लिए	दिसं, 2007 तक संचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(iii)	बीएफ-4 में कोल डस्ट इंजेक्शन सिस्टम	कोक दर में कमी तथा फर्नेश उत्पादकता में सुधार के लिए तकनीकी आवश्यकता	70.71	40.00	8.00	1:1 अनुपात के आधार पर कोक का पुल्वेराईज्ड कोल में प्रतिस्थापना। 120 किग्रा/ टीएचएम की दर से ब्लास्ट फर्नेस में कोल इंजेक्शन दर ।	अक्तू 08	अक्तू 08	6.21	6.21	--	उपस्कर आपूर्ति के लिए अनुमानित भुगतान में वृद्धि।
5.	**इस्को इस्पात संयंत्र**											
(i)	धमन भट्टी-2 का पुनर्निर्माण/ उन्नयन	उत्पादकता में वृद्धि तथा उपयोग मात्रा में वृद्धि होने से धमन भट्टी-2 का पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है।	103.93	60.00	63.00	530 एम3 उपयोगी मात्रा तथा 1.15 टी/एम3/दिन की उत्पादकता के साथ 213500 टीपीए तप्त धातु का उत्पादन	सितं 07	नवं 07	50.18	78.36	स्टैबलाईजेशन के अंतर्गत।	पूरा कर लिया गया है।

* आई एंड ईबीआर. सेल को कोई बजटीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है।

4.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल)

(करोड रुपए)

सं	पीएसयू का नाम तथा योजना/ कार्यक्रम	लक्ष्य /निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	अनुमोदित परिव्यय* 2007-08		मात्रात्मक सुपुर्दगीयोग्य/ वास्तविक उत्पादन	प्रासेसिज/टाईमलाईन्स		वास्तविक व्यय		अनुमानित निष्कर्ष/ कॉलम 7 के संदर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां जोखिम घटक
				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान		मूल	वास्तविक/ अब निर्धारित किया गया	अप्रै-दिसं. 2007 के लिए	दिसं, 2007 तक संचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(i)	कोक ओवन बैटरी सं. 4, चरण-I	कोक की जरूरतों एवं शेष गैस को पूरा करने के लिए, अन्य तीन कोक ओवन बैटरियों की बड़े पैमाने पर मरम्मत के दौरान भी तप्त धातु व द्रव इस्पात के उत्पादन को इस स्तर पर बनाए रखने हेतु एक प्रतिस्थापन बैटरी की आवश्यकता होगी ।	303.00	71.00	71.00	0.75 एमटी कोक का उत्पादन करना	दिसं, 06 (भारत सरकार से अनुमोदन जो दिसं, 03 में प्राप्त किया था, से 36 माह बाद)	सितं 08	22.98	274.62	--	टिप्पणियां:- मैकेनिकल की आपूर्ति, रिफ्रैक्ट्री मदों में विलंब और विस्थापित लोगों के विरोध के कारण बैटरी के चालू होने में विलंब हुआ। जोखिम :- चरण-II की इकाइयों के चालू न होने से संपूर्ण क्षमता अर्जित नहीं की गई।

(करोड स्पए)

सं	पीएसयू का नाम तथा योजना/ कार्यक्रम	लक्ष्य /निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	अनुमोदित परिव्यय* 2007-08		मात्रात्मक सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक उत्पादन	प्रासेसिज/टाईमलाईन्स		वास्तविक व्यय		अनुमानित निष्कर्ष/ कॉलम 7 के संदर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां जोखिम घटक
				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान		मूल	वास्तविक/ अब निर्धारित किया गया	अप्रै-दिसं. 2007 के लिए	दिसं, 2007 तक संचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(ii)	कोक ओवन बैटरी सं. 4, चरण-II	गैस का पूर्ण उपयोग करना तथा कोल हैंडलिंग में अतिरिक्त उप-उत्पाद सुविधाएं प्रदान करके उप-उत्पादों के बेहतर कार्यान्वयन में वृद्धि करना	118.89	60.20	5.00	उप-उत्पादों की प्राप्ति में वृद्धि	सितं 08	नवं 09	0.00	0.00	--	टिप्पणियां:- (1) उप-उत्पाद संयंत्र के लिए परामर्शदाता को नियत करने में विलंब। हाल ही में परामर्शदात नियुक्त। (2) विशिष्टियां जारी की गईं तथा प्रमुख पैकेजों के लिए टेंडर प्रक्रिया में हैं। जोख़िम:- लागत वृद्धि की संभावना। चालू करने में विलंब संभावित।

(iii)	3.0 एमटीपीए की मौजूदा क्षमता से 6.5 एमटीपीए करना	संयंत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए तप्त धातु की 3.0 एमटीपीए मौजूदा क्षमता को 6.5 एमटीपीए तक बढाना।	8692.00#	2500.00	1500.00	द्रव इस्पात के उत्पादन को बढ़ाकर वर्तमान स्तर 3.0 एमटीपीए क्षमता से 6.5 एमटीपीए करना	भारत सरकार के अनुमोदन, जो अक्तू 05 में प्राप्त किया गया था से चरणों में 36/48 माह	मार्च,10 (सीमलैस ट्यूब मिल को छोड़कर)	881.43	1152.92	--	टिप्पणियां:- विलंब के कारण निम्न हैं:- (1) ब्रिज एंड रूफ, कोलकाता व इंजी. वर्क्स, नई दिल्ली का निष्पादन संतोषजनक नहीं है। (2) क्वैरी आपूर्तिकर्ता की हड़ताल के कारण निर्माण कार्यकलापों के लिए माईनर मिनरल्स की कमी। (3) ऑर्डर देने और प्रमुख प्रक्रिया पैकेजों के ठेकों पर हस्ताक्षर होने में विलंब। (4) कुशल जनशक्ति तथा सुपरवाईजरी स्टॉफ की भारी कमी। (5) 19 जून, 07 से 25 जून, 07 तक तथा 15 सितं से 30 सितं तथा 22 अक्तू 07 तक चक्रवाती वर्षा। जोखिम:- संयंत्र और मशीनरी की मूल्य वृद्धि जिससे पूंजीगत लागत में वृद्धि होगी। अधिक समय लगने से लागत में वृद्धि। बाजार मूल्यों में उतार चढ़ाव। कच्चे माल का उपलब्ध न होना तथा आदान सामग्री के मूल्य में फेरबदल। अन्य देशों द्वारा इस्पात की डम्पिंग। रि-रोलिंग मिल तथा घरेलू उद्यमियों से प्रतिस्पर्धा।

परियोजना लागत संशोधन के तहत है।

(करोड स्पए)

सं	पीएसयू का नाम तथा योजना/ कार्यक्रम	लक्ष्य /निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	अनुमोदित परिव्यय* 2007-08		मात्रात्मक सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक उत्पादन	प्रासेसिज/टाईमलाईन्स		वास्तविक व्यय		अनुमानित निष्कर्ष/ कॉलम 7 के संदर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां जोखिम घटक
				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान		मूल	वास्तविक/ अब निर्धारित किया गया	अप्रै-दिसं. 2007 के लिए	दिसं, 2007 तक संचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(iv)	एयर सैपरेशन प्लांट	कंबाइंड ब्लोइंग प्रोसेस हेतु ऑर्गन की कमी होने पर अतिरिक्त सुविधा प्रदान करना । उत्पादित ऑक्सीजन बीएफ में प्रयुक्त की जाती है ।	96.00	70.00	5.00	600 टन/दिन की अतिरिक्त तमता	अक्त,07	जुलाई, 09	0.00	0.00	--	टिप्पणियां: जल्दी ही ऑर्डर देने की संभावना है। निविदाएं तैयार की जा रही हैं। पार्टियों ने लंबी सुपुर्दगी समयावधि के लिए कहा है। जोख़िम: प्रचालन चालू करने में विलंब। बाजार घटकों के कारण लागत वृद्धि की संभावना।
(v)	पुल्वेराईज्ड कोल इंजेक्शन	कम महंगे पुल्वेराईज्ड कोल की तुलना में महंगे बीएफ कोक की खपत में कमी के लिए इंजेक्शन सिस्टम ।	165.00	80.00	5.00	तप्त धातु की वर्तमान क्षमता को 0.5 एमटी तक बढ़ाना तथा तप्त धातु के उत्पादन की कीमत को कम करना ।	अक्त,07	जुलाई, 09	0.00	0.00	--	टिप्पणियां: संशोधित समयसूची के अनुसार परियोजना को पूरा किए जाने की संभावना। जोखिम: प्रचालन चालू करने में विलंब की संभावना।
(vi)	लौह अयस्क खान तथा कोककर कोयला खानों का अधिग्रहण	लौह अयस्क तथा कोककर कोयला खानों के अधिग्रहण से आरआईएनएल को कच्ची सामग्री हेतु आत्मनिर्भर होने के लिए आरआईएनएल/वीएसपी के पास कोककर कोयले व लौह अयस्क के निजी स्रोत नहीं हैं ।	600.00	65.00	0.15	लौह अयस्क/कोककर कोयले की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करना ।	--	--	0.10	0.26	--	टिप्पणियां: महल कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए। संभावना रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना व्यवहार्य नहीं है। वैकल्पिक ब्लॉक आबंटन के लिए भारत सरकार कार्रवाई कर रही है। जोखि: प्रस्ताव की स्वीकृति तकनीकी आर्थिक घटकों पर निर्भर करती है।

(vii)	धमन भट्टी-1 सीएटी-I मरम्मत	फर्नेस का जीवनकाल बढ़ाना	50.20 (बीएफ आई का समस्त बेस बदलने के लिए इसकी लागत में संशोधन करके इसे 472 करोड़ रु. किया गया है।)	50.00	0.00	उत्पादकता को बनाए रखना तथा इसमें सुधार करना।	2007-08	2010-11	0.00	0.00	--	टिप्पणियां: बीएफ-1 ने प्रचालन शुरू होने से 16 वर्ष के समय में 26 एमटी का थ्रु पुट पूरा किया है। सामान्यतया लगभग 25 एमटी थ्रु पुट के बाद 14-16 वर्ष बाद श्रेणी-। मरम्मत की आवश्यकता होती है। उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए इस परियोजना को नई इकाइयों के साथ-साथ ही चालू किया गया है।

4.3 कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि. (केआईओसीएल)

(करोड रुपए)

सं	पीएसयू का नाम तथा योजना/ कार्यक्रम	लक्ष्य /निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	अनुमोदित परिव्यय* 2007-08		मात्रात्मक सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक उत्पादन	प्रासेसिज/टाईमलाईन्स		वास्तविक व्यय		अनुमानित निष्कर्ष/ कॉलम 7 के संदर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां जोखिम घटक
				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान		मूल	वास्तविक/ अब निर्धारित किया गया	अप्रै-दिसं. 2007 के लिए	दिसं, 2007 तक संचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(i)	डक्टाईल आयरन स्पन पाईप (डीआईएसपी) संयंत्र	मूल्यवर्धित उत्पाद अर्थात डक्टाइल आयरन स्पन पाईप का उत्पादन करने के लिए एक योजना बनाना।	225.00	30.00	14.00	1,00,000 टन प्रति वर्ष डीआईएसपी का उत्पादन	कॉलम 13 देखें।		--	--	कॉलम 13 देखें।	दिनांक 1.4.2007 से गौण कंपनी किस्को का डीआईओसीएल में विलय कर दिया गया है। इसके लिए आदेश बीआईएफआर से जुलाई, 2007 के अंत तक प्राप्त हो गया था। वैश्विक निविदा निकालने से ऑर्डर नहीं दिया गया। अत: नए वैश्विक निविदा नोटिस जारी किए गए हैं।
(ii)	अन्य खान विकास	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खनन पर लगाए गए प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए नई खान स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाना इसका उद्देश्य है ।	145.00	5.00	0.00	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खनन पर लगाए गए प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए नई खान स्थापित करना।	कॉलम 13 देखें।		--	--	कॉलम 13 देखें।	कंपनी विभिन्न राज्यों में खनन पट्टों के लिए तलाश कर रही है। इस संबंध में कर्नाटक सरकार ने सिद्धांतत: 50% रमनदुर्ग निक्षेपों के आबंटन पर सहमति दे दी है। यह मामला राज्य सरकार तथा अन्य पार्टियों के बीच लंबी कानूनी कार्रवाई के अधीन भी है। हाल ही में उपर्युक्त कानूनी कार्रवाई से संबंधित तर्कों को कर्नाटक उच्च न्यायालय में भी उठाया गया था तथा निर्णय अभी सुरक्षित है। यह मुद्दा अभी भी न्यायाधीन है।

(iii)	मंगलौर में लौह अयस्क की प्राप्ति हेतु ब्लॉक सामग्री संभाल सुविधाओं का निर्माण	चूंकि अधिकतर कच्ची सामग्री का रेल के जरिए परिवहन किया जाता है इसलिए केआईओसीएल को इसके पैलेट तथा कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए लौह अयस्क कन्साईन्मेंट प्राप्त करने हेतु भारी सामग्री की संभाल सुविधाओं के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है।	150.00	10.00	5.00	पैलेटों के उत्पादन के लिए 4 एमटीपीए लौह अयस्क की आपूर्ति	कॉलम 13 देखें।	--	--	कॉलम 13 देखें।	नई रेलवे साइडिंग का प्रस्ताव करने के बाद एक क्लोज्ड क्नवेयर सिस्टम के जरिए भारी सामग्री संभाल प्रणाली की योजना बनाई है। हालांकि एक भूमि स्वामी तथा केआईएडीबी अधिग्रहण में विलंब हुआ तथा हाल ही में भूमि विवाद का निपटारा किया गया है।

* आई एंड ईबीआर। केआईओसीएल को कोई बजटीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है।

4.4 एनएमडीसी लि.

(करोड रुपए)

सं	पीएसयू का नाम तथा योजना/ कार्यक्रम	लक्ष्य /निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	अनुमोदित परिव्यय* 2007-08		मात्रात्मक सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक उत्पादन	प्रासेसिज/टाईमलाईन्स		वास्तविक व्यय		अनुमानित निष्कर्ष/ कॉलम 7 के संदर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां जोखिम घटक
				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान		मूल	वास्तविक/ अब निर्धारित किया गया	अप्रै-दिसं. 2007 के लिए	दिसं, 2007 तक संचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(i)	बैलाडिला निक्षेप-11बी	लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ाना।	295.89	55.00	50.00	3 एमटीपीए की चरण-। की क्षमता	अक्तूबर 2009	अक्तूबर 2009	21.07	24.30	कॉलम 13 देखें।	चार प्रमुख पैकेजों में से पैकेज-1 (क्रशिंग प्लांट एंड स्टॉक पाईल), पैकेज-2 (डाऊनस्ट्रीम कन्वेइंग सिस्टम), पैकेज-3 (अर्थ वर्क एंड साईट प्रीप्रेशन) पहले ही प्रदान कर दिए हैं। पैकेज-3 के संबंध में कुल 10.2 लाख मात्रा सहित उत्खनन तथा 3041 वर्ग मी. सोइल नेलिंग तथा 1976 वर्ग मी. शॉटक्रेटिंग पूरा हो चुका है। पैकेज-1 (इलैक्ट्रिकल सब-स्टेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) के लिए ऑफर प्राप्त हुए हैं तथा तकनीकी वाणिज्यिक सिफारिशें तैयार की जा रही हैं।
(ii)	कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना	लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ाना।	296.03	2.00	0.50	3 एमटीपीए की चरण-। की क्षमता	दिसं,09	दिसं,09	0.83	0.83	कॉलम 13 देखें।	एनएमडीसी के पक्ष में पट्टे का नवीकरण करने के संबंध में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश को अभी खरिज किया जाना है। वन विभाग से वृद्धि गिराने संबंधी आज्ञा भी प्राप्त करनी है तथापि मेकॉन को इंजीनियरी, ठेका अधिप्राप्ति, परियोजना प्रबंधन तथा निर्माण प्रबंधन सेवाओं के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। पैकेज-। के लिए निविदा निकाली गई है तथा अन्य पैकेजों के लिए निविदा दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।

* आई एंड ईबीआर। एनएमडीसी को कोई बजटीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है।

(करोड रूपए)

सं	पीएसयू का नाम तथा योजना/ कार्यक्रम	लक्ष्य /निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	अनुमोदित परिव्यय* 2007-08		मात्रात्मक सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक उत्पादन	प्रासेसिज/टाईमलाईन्स		वास्तविक व्यय		अनुमानित निष्कर्ष/ कॉलम 7 के संदर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां जोखिम घटक
				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान		मूल	वास्तविक/ अब निर्धारित किया गया	अप्रै-दिसं. 2007 के लिए	दिसं, 2007 तक संचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(iii)	स्पंज लोहा और 10 मेगावाट विद्युत संयंत्र- नागरनार	स्पंज लोहे का उत्पादन करना और विद्युत सृजित करना।	79.00	5.00	0.20	1 एलटी पीए स्पंज आयरन व 10 मेगावाट विद्युत	सितं 09	सितं 09	0.29	0.29	कॉलम 13 देखें।	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त हो गई है तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी अभी प्राप्त होनी है। इसी बीच मैसर्स स्पंज आयरन इंडिया लि. को ईपीसीएम आधार पर परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। प्लांट ले-आऊट को अंतिम रूप दे दिया गया है। क्लिन-कूलर के संबंध में टेंडर को अंतिम रूप दिया गया है और ऑर्डर फरवरी, 08 में जारी किया जा रहा है। सिविल व स्ट्रक्चरल वर्क्स पैकेज तथा कच्ची सामग्री की तैयारी और उत्पाद संभाल पैकेज के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। अन्य पैकेजों के लिए टेंडर दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।
(iv)	कर्नाटक में विंड मिल	इलैक्ट्रिकल एनर्जी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना	110.00	50.00	11.30	10 मेगावाट विद्युत सृजन, 20 मेगावाट तक विस्तारयोग्य	अप्रैल 08	सितं 08	--	--	कॉलम 13 देखें।	टेंडर के लिए ऑफर प्राप्त हो गए हैं और जांच में हैं।

4.5 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. (एचएससीएल)

(करोड रुपए)

सं	पीएसयू का नाम तथा योजना/ कार्यक्रम	लक्ष्य /निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	अनुमोदित परिव्यय* 2007-08		मात्रात्मक सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक उत्पादन	**प्रासेसिज/टाईमलाईन्स**		**वास्तविक व्यय**		**अनुमानित निष्कर्ष/ कॉलम 7 के संदर्भ में उपलब्धियां**	**टिप्पणियां जोखिम घटक**
				बजट अनुमान	**संशोधित अनुमान**		**मूल**	**वास्तविक/ अब निर्धारित किया गया**	**अप्रै-दिसं. 2007 के लिए**	दिसं, 2007 तक संचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(i)	वीआरएस को लागू करने के लिए आवधिक ऋण पर ब्याज सहायता।	वीआरएस के जरिए जनशक्ति युक्तिसंगत बनाना और जनशक्ति लागत में कटौती करना।	--	56.02	56.02	1500 तक कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना।	2007-08 के अंत तक	2007-08 के अंत तक	37.27	392.94	1.1.2008 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या को 1531 तक कम कर दिया गया।	--

@ बजटीय सहायता

अध्याय - V

वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2008-2009, के लिए मांग संख्या 91 बजट सत्र के दौरान इस्पात मंत्रालय की ओर से संसद में प्रस्तुत की जाएगी। इस मांग में मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के गैर-योजना व्ययों तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के गैर-योजना व्ययों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

1. वर्ष 2008-2009 के लिए निधि की कुल आवश्यकता

वर्ष 2007-2008 के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान सहित बजट अनुमान 2008-2009 के लिए मांग संख्या-91 में शामिल कुल वित्तीय आवश्यकता का सार निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

(करोड़ रुपए)

2008-2009क्के लिए मांग सं. 91	बजट अनुमान 2007-2008			संशोधित अनुमान 2007-2008			बजट अनुमान 2008-2009		
	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना	योग
राजस्व खंड	1.00	84.50	**85.50**	1.00	75.53	**76.53**	18.50	77.23	**95.73**
पूंजी खंड	65.00	0.00	**65.00**	65.00	0.00	**65.00**	15.50	0.00	**15.50**
योग	**66.00**	**84.50**	**150.50**	**66.00**	**75.53 ***	**141.53**	**34.00**	**77.23 #**	**111.23**

* गारंटी शुल्क माफ करने से संबंधित लेखा समायोजन के लिए 12.52 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल नहीं है।
# गारंटी शुल्क माफ करने से संबंधित लेखा समायोजन के लिए 8.29 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल नहीं है।

2. गैर-योजना व्यय

इस्पात मंत्रालय का 2007-08 (बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान) तथा बजट अनुमान 2008-09 में गैर-योजना व्यय, सचिवालय आर्थिक सेवाएं, विकास आयुक्त, लोहा तथा इस्पात (डी सी आई एंड एस), कोलकाता तथा इस मंत्रालय के तहत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

(करोड़ रूपए)

	मुख्य शीर्ष एवं व्यय की मदें	**बजट अनुमान 2007-08**	**संशोधित अनुमान 2007-08**	**बजट अनुमान 2008-09**
I.	**मुख्य शीर्ष - 3451**			
1.	सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	11.62	11.60	13.91
II.	**मुख्य शीर्ष - 2852**			
2.	विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात, कोलकाता	1.82	1.84	1.58
3.	प्रतिष्ठित धातुकर्मियों को पुरस्कार	0.12	0.12	0.12
4.	ब्याज इमदाद:			

(i)	वीआरएस के कार्यान्वसन के लिए के लिए बैंकों से जुटाए गए ऋणों पर ब्याज के भुगतान हेतु हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. को इमदाद	56.02	56.02	56.02
(ii)	वीआरएस के कार्यान्वसन के लिए के लिए बैंकों से जुटाए गए ऋणों/बांडों पर ब्याज के भुगतान हेतु मेकॉन लि. को इमदाद	6.03	5.95	5.60
	मुख्य शीर्ष एवं व्यय की मदें	**बजट अनुमान 2007-08**	**संशोधित अनुमान 2007-08**	**बजट अनुमान 2008-09**
5.	गारंटी शुल्क माफ करना (गैर-नकद संव्यवहार)			
(i)	एचएससीएल - नकद साख (सी सी) सीमा, बैंक गारंटी (बीजी) और वीआरएस ऋणों के लिए सरकारी गारंटी के संबंध में गारंटी शुल्क माफ करना।	6.60	6.10	6.10
(ii)	बीआरएल - कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं के लिए नकद साख सीमा, बैंक गारंटी और ऋणों के लिए सरकारी गारंटी के संबंध में गारंटी शुल्क माफ करना।	0.54	0.40	0.54
(iii)	मेकॉन लिमिटेड - वीआरएस ऋणों/बाँडों के लिए सरकारी गारंटी के संबंध में गारंटी शुल्क माफ करना।	1.75	1.75	1.65
(iv)	मेकॉन लिमिटेड - दंडात्मक गारंटी शुल्क माफ करना।	0.00	4.27	0.00
	घटाएं - निवल प्राप्तियां [(i) से (iv)] #	--	- 12.52	- 8.29
	योग: गैर-योजना व्यय (प्राप्तियों का निवल)	**84.50**	**75.53**	**77.23**
	योग: गैर-योजना व्यय (सकल)	**84.50**	**88.05**	**85.52**

वित्त मंत्रालय की सलाह पर गारंटी शुल्क को माफ करने से संबंधित प्रावधान संशोधित अनुमान 2007-08 से शुरू किए जाने हैं।

संशोधित अनुमान 2007-08 में मंत्रालय का गैर-योजना प्रावधान (सकल) बजट अनुमान 2007-08 के गैर-योजना प्रावधान से 3.55 करोड़ रूपए अधिक है। मेकॉन लिमिटेड से 2006-07 तक के लिए देय 4.27 करोड़ रूपए के दंडात्मक गारंटी शुल्क को माफ करने के लिए 2007-08 की अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच में प्राप्त किए गए 4.27 करोड़ रूपए के अतिरिक्त प्रावधान के कारण है। संशोधित अनुमान 2007-08 में गैर-योजना व्यय के अन्य शीर्षों के तहत 0.72 करोड़ रूपए की कमी को शामिल करते हुए संशोधित अनुमान 2007-08 में अतिरिक्त निवल 3.55 करोड़ रूपए बैठता है।

3. योजना व्यय

मंत्रालय के बजट में रखा गया योजना बजट प्रावधान निम्नलिखित के लिए है:

(i) इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के वित्तीय रूप से कमजोर और घाटे में चल रहे कुछ उपक्रमों को उनकी एएमआर तथा अन्य पूंजीगत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बजटीय सहायता उपलब्ध करवाना; और

(ii) मंत्रालय द्वारा 11वीं योजना के दौरान लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जाने वाली नई योजनाओं का निधियन।

11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस्पात उद्योग से संबंधित कार्य दल की सिफारिशों के अनुरूप इस्पात मंत्रालय ने पर्यावरण के अनुकूल गुणवत्ता वाले इस्पात के लागत प्रभावी उत्पादन हेतु अभिनव तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने तथा इसमें तेजी लाने के लिए एक नई योजना/तंत्र लाने का प्रस्ताव किया है। चूंकि इस अनुसंधान एवं विकास योजना के विशिष्ट ब्यौरों को इस क्षेत्र के विभिन्न स्टेक होल्डरों के परामर्श से अभी तय किया जाना है।

बजट अनुमान 2007-08 में 66.00 करोड़ रूपए की कुल योजनागत बजटीय सहायता संशोधित अनुमान 2007-08 में रखी गई है जबकि बजट अनुमान 2008-09 में 34.00 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है। योजनागत प्रावधानों का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

(करोड़ रूपए)

क्र. सं.	**संगठन/उपक्रम का नाम**	**योजना**	**योजना बजटीय सहायता बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान 2007-08**	**योजना बजटीय सहायता बजट अनुमान 2008-09**
1.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड	(i) एएमआर योजनाओं के लिए योजना ऋण	0.00	8.00
		(ii) बीआरएल की पुनर्संरचना हेतु प्रस्तावित योजना के मद्देनजर टोकन प्रावधान	1.00	0.00
2.	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	(i) निर्माण उपस्कर एवं मशीनरी की बड़े पैमाने पर मरम्मत और अधिप्राप्ति के लिए योजना ऋण	0.00	6.50
		(ii) एचएससीएल की पुनर्संरचना हेतु प्रस्तावित योजना के मद्देनजर टोकन प्रावधान	1.00	0.00
3.	मेकॉन लिमिटेड	5 प्रतिशत गैर-संचयी शोधनीय तरजीही शेयर पूंजी के जरिए निधियां लाना *	63.00	0.00
4.	बर्ड ग्रुप	एएमआर योजनाएं	0.00	1.00
5.	इस्पात मंत्रालय	लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु योजना के लिए सहायता अनुदान	**1.00**	18.50
	योग		***66.00***	***34.00***

* सरकार द्वारा मेकॉन के लिए अनुमोदित पुनरूद्धार/पुनर्संरचना पैकेज का भाग।

संशोधित अनुमान 2007-08 में 66.00 करोड़ रूपए के योजना प्रावधान के अलावा 2007-08 के अनुपूरक अनुमान मांग के तीसरे और अंतिम बैच में शामिल करने के लिए वित्त मंत्रालय ने बीआरएल में साम्या निवेश के तौर पर 7.00 करोड़ रूपए के अनुपूरक अनुदान का अनुमोदन किया है। यह 7.00 करोड़ रूपए की धनराशि 35.00 करोड़ रूपए के कुल साम्या निवेश की 5वीं और अंतिम किस्त है जिसे कंपनी के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित जून, 2002 के पुनरूद्धार पैकेज के तहत वर्ष 2003-04 से शुरू करते हुए पंचवर्षीय किस्तों में बीआरएल को दिया गया था।

4. वास्तविक व्यय - 2004-05 से 2007-08 (दिसंबर, 2007 तक)

संबंधित वर्षों के बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान की तुलना में पहले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के अनुदान के तहत वास्तविक योजना तथा गैर-योजना व्यय (सकल आधार) निम्नानुसार है:-

(करोड़ रूपए)

वर्ष	बजट अनुमान			संशोधित अनुमान			वास्तविक व्यय		
	गैर-योजना	योजना	योग	गैर-योजना	योजना	योग	गैर-योजना	योजना	योग
2007-08	84.50	66.00	**150.50**	88.05	66.00	**154.05**	53.22	63.00	**116.22 #**
2006-07	84.50	45.00	129.50	137.00	45.00	182.00	359.86 (1)	45.72 (2)	405.58
2005-06	74.53	15.00	**89.53**	84.50	15.00	**99.50**	77.15	15.00	**92.15**
2004-05	165.54	15.00	**180.54**	190.21	15.00	**205.21**	188.97	15.00	**203.97**

अप्रैल - दिसंबर, 2007 तक 9 माह की अवधि का वास्तविक व्यय

(1) इसमें (i) सेल से बकाया दंणात्मक गारंटी शुल्क को माफ करने के संबंध में 70.22 करोड़ रूपए का लेखा समायोजन और (ii) 2006-07 के अनुपूरक अनुदानों के तीसरे और अंतिम बैच में प्राप्त किए गए प्रावधानों, बकाया आयकर देयताओं के भुगतान के लिए एच एस सी एल को 164.03 करोड़ रू0 की अनुदान सहायता शामिल है।

(2) इसमें सरकारी ऋणों पर बकाया ब्याज को साम्या में परिवर्तित करने के लिए 1.72 करोड़ रू0 का प्रावधान तथा वर्ष 2006-07 के लिए अनुपूरक अनुदान में तीसरे और अंतिम बैच में प्राप्त प्रावधान शामिल हैं।

5. 2008-09 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक योजना 2008-09 प्रस्तावों तथा योजना आयोग के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर और 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने इस्पात मंत्रालय के लिए 2008-09 के बजट अनुमान हेतु निम्नलिखित परिव्यय मंजूर किया है:

(करोड़ रूपए)

(क)	सकल बजटीय सहायता	34.00
(ख)	आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आई एंड ईबीआर)	9509.00
(ग)	इस्पात मंत्रालय का कुल परिव्यय (क+ख)	9543.00

वार्षिक योजना 2007-08 (बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान) तथा वार्षिक योजना 2008-09 के लिए उपक्रम-वार योजना परिव्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए)

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/संगठन का नाम	बजट अनुमान 2007-08			संशोधित अनुमान 2007-08			बजट अनुमान 2008-09		
	परिव्यय	आईईबीआर	बजटीय सहायता	परिव्यय	आईईबीआर	बजटीय सहायता	परिव्यय	आईईबीआर	बजटीय सहायता
क. उपक्रमों की योजनाएं									
1. सेल	2641.00	2641.00	0.00	2007.00	2007.00	0.00	4674.00	4674.00	0.00

2. आरआईएनएल	3056.70	3056.70	0.00	1861.15	1861.15	0.00	4166.00	4166.00	0.00
3. सिल	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
4. एचएससीएल	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	6.50	0.00	6.50
5. मेकॉन	66.00	3.00	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
6. बीआरएल	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00	0.00	8.00
7. एमएसटीसी	5.00	5.00	0.00	13.60	13.60	0.00	5.00	5.00	0.00
8. एफएसएनएल	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	11.80	11.80	0.00
9. एनएमडीसी लि0	250.00	250.00	0.00	150.00	150.00	0.00	400.00	400.00	0.00
10. केआईओसीएल	75.00	75.00	0.00	45.00	45.00	0.00	100.00	100.00	0.00
11. मॉयल	65.00	65.00	0.00	140.06	140.06	0.00	117.20	117.20	0.00
12. बर्ड ग्रुप	25.00	25.00	0.00	26.00	26.00	0.00	31.00	30.00	1.00
योग - क	**6202.70**	**6137.70**	**65.00**	**4324.81**	**4259.81**	**65.00**	**9524.50**	**9509.00**	**15.50**
ख. इस्पात मंत्रालय की योजनाएं									
1. लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	18.50	0.00	18.50
योग - ख	**1.00**	**0.00**	**1.00**	1.00	0.00	1.00	**18.50**	**0.00**	**18.50**
कुल योग - क+ ख	**6203.70**	**6137.70**	**66.00**	**4325.81**	**4259.81**	**66.00**	**9543.00**	**9509.00**	**34.00**

नोट:- इस्पात मंत्रालय को सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए अपने बजट का 10 प्रतिशत चिन्हित करने की व्यवस्था से मुक्त कर दिया गया है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस्पात उद्योग से संबंधित कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार इस मंत्रालय ने 11वीं योजनावधि के दौरान 3 नई योजनाएँ नामतः लोहा एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना, इस्पात क्षेत्र में संस्थाओं और जनशक्ति विकास के लिए योजना तथा लघु एवं मध्यम उद्यमियों के लिए टी यू एफ एस योजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव किया था । तथापि आर एंड डी योजनाओं को छोड़कर शेष योजनाओं का योजना आयोग ने अनुमोदन नहीं किया है। वार्षिक योजना 2008-09 के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित 20 करोड़ रू0ककी तुलना में आर एंड डी योजना को बढ़ावा देने के लिए योजना आयोग द्वारा 18.50 करोड़ रू0 की मंजूरी दी गई है। इस क्षेत्र के विभिन्न शेयरधारकों के परामर्श से आर एंड डी योजनाओं के विशिष्ट ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के लिए 2008-09 के बजट अनुमान में परिव्यय हेतु किए गए प्रावधान का योजना/परियोजना-वार संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वार्षिक योजना 2008-2009 (बजट अनुमान) में कुल 9543.00 करोड़ रू0 के परिव्यय में से **4674.00 करोड़ रू0** की धनराशि का प्रावधान **स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)** के लिए किया गया है और इसकी व्यवस्था सेल के आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आई एंड ई बी आर) से की जाएगी। सेल की विभिन्न योजनाओं के लिए उपलब्ध करवाये गये परिव्यय का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) **भिलाई इस्पात संयंत्र** के लिए 1149.00 करोड़ रू0 के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। परिव्यय में कोक ओवन बैटरी सं0 5 का पुनर्निर्माण, स्लैब कास्टर की स्थापना, मेन स्टैप डाऊन स्टेशन-5 और

टीपीडी ऑक्सीजन संयंत्र जैसी चल रही योजनाओं तथा बीएसपी के आधुनिकीकरण एवं विस्तार जैसी नई योजना पर व्यय शामिल है।

(ii) **दुर्गापुर इस्पात संयंत्र** के लिए 336.00 करोड़ रू0 के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। परिव्यय में अन्य बातों के साथ-साथ संबद्ध सुविधाओं सहित ब्लूम कास्टर और बीएफ 3 और 4 में कोल डस्ट इंजेक्शन तथा डीएसपी के विस्तार और डीएसपी में ईआरपी जैसी नई योजनाओं से संबंधित व्यय शामिल है।

(iii) **राउरकेला इस्पात संयंत्र** के लिए 719.00 करोड़ रू0 के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। परिव्यय में बीएफ 4 में सीडीआई सिस्टम की स्थापना, सीओबी 4 की बड़े पैमाने पर मरम्मत, 700 टीपीडी ऑक्सीजन संयंत्र तथा कोक ओवन गैस होल्डर जैसी नई योजनाओं पर व्यय शामिल है।

(iv) **बोकारो इस्पात संयंत्र** के लिए 791.00 करोड़ रू0 के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। परिव्यय में कोककर कोयला स्टोरेज सुविधाओं को बढ़ाने पर होने वाला व्यय, बीएफ 2 और 3 में सीडीआई सिस्टम के प्रावधान, एसएमएस-।। में दूसरे लैडल फर्नेस की स्थापना, बीएफ-2 का उन्नयन और चल रही तथा नई योजनाओं के लिए व्यय शामिल है।

(v) **मिश्र इस्पात संयंत्र** के लिए 60.00 करोड़ रू0 का परिव्यय एओडी व ईएएफ की स्थापना, एएसपी के विस्तार तथा अन्य पूरी हो चुकी योजनाओं तथा 10 करोड़ रूपए से कम लागत की चल रही योजनाओं के लिए है।

(vi) **इस्को स्टील प्लांट** के लिए 1111.00 करोड़ रू0 के परिव्यय का प्रावधान किया गया है जिसमें आईएसपी के विस्तार (961 करोड़ रूपए), सीओबी - 10 (60 करोड़ रूपए) का पुनर्निर्माण और नई योजनाओं तथा चल रही योजनाओं के लिए शेष राशि शामिल है।

(vii) **सेलम इस्पात संयंत्र** के लिए 230.00 करोड़ रू0 के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। परिव्यय का अधिकांश हिस्सा एसएसपी के विस्तार (200 करोड़ रूपए) के लिए है। कम लागत की विविध योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है।

(viii) शेष 278.00 करोड़ रू0 के परिव्यय का प्रावधान विश्वैश्वरया आयरन एंड स्टील लि0 (58 करोड़ रू0), सेल की केन्द्रीय इकाईयों (60 करोड़ रू0), कच्चा माल प्रभाग (150 करोड़ रूपए) और विभिन्न चल रही परियोजनाओं तथा अनुसंधान कार्य के लिए महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मैल्ट लि0 (10 करोड़ रू0) के लिए किया गया है।

2. **राष्ट्रीय इस्पात निगम लि0** के लिए **4166.00 करोड़ रू0** के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इस परिव्यय में से अधिकांश हिस्सा, जिसकी धनराशि 3000.00 करोड़ रू0 है, को राष्ट्रीय इस्पात निगम लि0 की उत्पादन क्षमता को बढ़ा कर 6.5 मिलियन टन करने के लिए निर्धारित किया गया है। एएमआर योजनाओं, कोक ओवन बैटरी सं0 4 (चरण-1 तथा चरण-2), लौह अयस्क और कोककर कोयला खदानों के अधिग्रहण

तथा अनुषंगियों सहित 330 टीपीएच बॉयलर, लौह अयस्क भंडारण सुविधाएं, पावर इवेक्यूऐशन सिस्टम आदि के लिए भी प्रावधान किया गया है। परिव्यय की व्यवस्था कंपनी के आंतरिक संसाधनों से की जाएगी।

3. **स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड** के लिए **5.00 करोड़ रू0** के परिव्यय का प्रावधान एएमआर योजनाओं के लिए किया गया है जिसकी व्यवस्था कंपनी के आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से की जाएगी।

4. **हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि0** के लिए **6.50 करोड़ रूपए** का प्रावधान बड़े पैमाने पर मरम्मत और नये निर्माण उपस्करों व मशीनरी की अधिप्राप्ति के लिए किया गया है।

5. **भारत रिफैक्ट्रीज लि0** के लिए बजटीय सहायकता के लिए **8.00 करोड़ रूपए** का प्रावधान एएमआर योजनाओं हेतु किया गया है।

6. **एन एम डी सी लि0** के लिए **400.00 करोड़ रू0** के परिव्यय का प्रावधान किया गया है जिसकी व्यवस्था आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से की जाएगी। इसमें बैलाडिला निक्षेप-11बी, कर्नाटक में विंड मिल, अन्य वेंचरों में निवेश, स्पंज आयरन पावर प्लांट, चल रही ए एम आर योजनाओं, बस्ती तथा अनुसंधान एवं विकास जैसी योजनाएं/परियोजनाएं शामिल हैं जिसकी व्यवस्था आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से की जाएगी।

7. **कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि0** के लिए **100.00 करोड़ रू0** के परिव्यय का प्रावधान डक्टाईल आयरन स्पन पाईप प्लांट, मंगलौर में रेल द्वारा लौह अयस्क प्राप्त करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास, ए एम आर योजनाओं और अनुसंधान एवं विकास व्यवहार्यता अध्ययन तथा इको-टाऊन विकास की नई योजनाओं, कोल इंजेक्शन सिस्टम और कोक ओवन संयंत्र के लिए किया गया है। पूरे योजना परिव्यय की व्यवस्था कंपनी के आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से की जाएगी।

8. **मैंगनीज ओर इंडिया लि0** के लिए **117.20 करोड़ रू0** के परिव्यय का प्रावधान फैरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज के लिए संयुक्त उद्यम में निवेश, विंड पावर जेनरेशन योजना, बालाघाट में सिंटरिंग प्लांट, ए एम आर योजनाओं, टाऊनशिप और अनुसंधान एवं विकास/व्यवहार्यता अध्ययन जैसी योजनाओं के निष्पादन के लिए किया गया है। योजना परिव्यय की व्यवस्था कंपनी के आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से की जाएगी।

9. **बर्ड ग्रुप कंपनियों** के लिए **31.00 करोड़ रू0** के परिव्यय का प्रावधान वन रोपण और पट्टा मामलों, खनिज आधारित उद्योगों और एएमआर योजनाओं के लिए किया गया है और बजटीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई राशि के अतिरिक्त 1.00 करोड़ रूपए की राशि की व्यवस्था कंपनी के आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से की जाएगी।

10. वार्षिक योजना वर्ष 2008-09 में **मेकॉन लि.** के लिए परिव्यय का प्रावधान नहीं किया गया है।

11. **एम एस टी सी लि0** के लिए **5.00 करोड़ रू0** के परिव्यय का प्रावधान स्टॉकयार्ड/गोदाम सुविधाओं की स्थापना करने के लिए किया गया है और इसकी व्यवस्था कंपनी के आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से की जाएगी।

12. **फैरो स्क्रैप निगम लि0** के लिए **11.80 करोड़ रू0** के परिव्यय का प्रावधान ए एम आर योजनाओं के लिए किया गया है जिसकी व्यवस्था कंपनी के आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से की जाएगी।

6. 10वीं योजना (2002-2007) के दौरान योजना परिव्यय तथा वास्तविक व्यय

दसवीं योजना के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय की तुलना में वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए)

उपक्रम का नाम	2002-2003		2003-2004		2004-05		2005-06		2006-07	
	परिव्यय	वास्तविक	परिव्यय	वास्तविक	परिव्यय	वास्तविक	परिव्यय	वास्तविक	परिव्यय	वास्तविक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. सेल	500.00	224.33	600.00	454.32	650.00	531.63	1030.00	812.70	1275.00	1150.00
2. आरआईएनएल	55.00	27.05	227.00	25.00	300.00	70.90	896.00	160.94	1452.00	421.62
3. सिल	5.00	2.00	5.00	2.02	9.00	1.10	5.00	0.78	5.00	1.38
4 एचएससीएल	9.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	7.00	7.00
5. मेकॉन	4.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.28	12.28	30.00	43.58
6. बीआरएल	13.00	5.00	7.00	12.00	10.00	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00
7. एमएसटीसी	20.00	14.85	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	4.30	5.00	0.00
8. एफएसएनएल	12.00	14.91	11.50	5.33	11.50	12.93	10.00	19.35	11.80	16.81
9. एनएमडीसी लि0	527.05	113.05	481.55	65.12	321.90	46.76	220.25	121.28	150.00	112.75
10. केआईओसीएल	133.00	10.07	30.00	9.22	54.00	11.05	225.00	31.28	200.00	19.99
11. मॉयल	32.50	12.93	26.75	7.78	20.00	17.57	34.21	25.97	48.50	64.37
12. बर्ड ग्रुप	3.45	3.74	2.50	16.91	16.00	5.04	17.38	9.24	26.00	1.73
13. अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन *	95.00	0.41	60.00	13.93	60.00	7.63	0.00	0.00	--	--
योग	***1409.00***	***434.34***	***1461.30***	***616.63***	***1461.40***	***718.61***	***2466.12***	***1209.12***	***3217.30***	***1846.23***
इनमें से: **(i) आई एंड ईबीआर**	1397.00	422.34	1443.30	598.63	1446.40	703.61	2451.12	1194.12	3172.30	1800.51
(ii) बजटीय सहायता	12.00	12.00	18.00	18.00	15.00	15.00	15.00	15.00	45.00	45.72

* योजना आयोग द्वारा वर्ष 2006-07 से इसे योजनागत योजना में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि योजना पर होने वाले व्यय को इस्पात विकास निधि (एसडीएफ) से पूरा किया जाना है।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय की तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले 4 वर्षों के दौरान वास्तविक योजना व्यय संतोषजनक नहीं रहा है हांलाकि वास्तविक व्यय में प्रतिशतता तथा समग्रता की दृष्टि से, दोनों में बढ़ोत्तरी का रूख दिखाई दिया है। वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 में क्रमश: 31.40 प्रतिशत तथा 41.50 प्रतिशत के वास्तविक उपयोग की तुलना में वार्षिक योजना 2004-05 तथा 2005-06 में अनुमोदित परिव्यय का उपयोग लगभग 49 प्रतिशत था जो 2006-07 में

बढ़कर 57.38 प्रतिशत हो गया। जहां वार्षिक योजना 2002-03 से 2005-06 के दौरान प्रत्येक योजना में याजना बजटीय सहायता का शत-प्रतिशत उपयोग हुआ है वहीं संबंधित वार्षिक योजना परिव्ययों में पूरी गिरावट आई एंड ईबीआर के संबंध में है। 10वीं योजना के दौरान उपयोग में 5190.91 करोड़ रू0 की कुल गिरावट की लगभग 95 प्रतिशत गिरावट सरकारी क्षेत्र के 4 प्रमुख उपक्रमों अर्थात सेल, आर आई एन एल, एन एम डी सी लि0 तथा के आई ओ सी एल द्वारा कम उपयोग के कारण आई है। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में सेल द्वारा योजना परिव्यय के उपयोग में सुधार हुआ है और यह 2002-03 में 45 प्रतिशत से 2004-05 तथा 2005-06 में लगभग 80 प्रतिशत और 2006-07 में 90 प्रतिशत हो गई वहीं आर आई एन एल, एन एम डी सी लि0 तथा के आई ओ सी एल द्वारा 2002-06 के दौरान गिरावट बढ़ी है जिसके मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:

- **आर आई एन एल**: द्रव्य इस्पात की क्षमता के 6.3 एम टी पी ए तक विस्तार जैसी प्रमुख योजनाओं के अनुमोदन में विलंब और आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों आदि की तरफ से हुए विलंब के चलते योजनाओं का धीमा गति से कार्यान्वयन।
- **एन एम डी सी लि0**: कंपनी की योजनाओं/परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय/राज्य के प्राधिकारियों से वन संबंधी मंजूरी/पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त करने में विलंब और व्यवहार्य प्रौद्योगिकी के अभाव के चलते एन एम डी सी आयरन एंड स्टील प्लांट जैसी कतिपय योजनाओं की छंटनी।
- **के आई ओ सी एल**: कुद्रेमुख में लौह अयस्क के खनन कार्य को 31.12.2005 से बंद करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश ।

इस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि मंत्रालय के 10वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय को 2001 में अंतिम रूप दिया गया था और इस समय वर्ष 2003 से इस्पात क्षेत्र में सुधार के संकेत दिखाई देने लगे थे। 10वीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान योजना परिव्यय के कम उपयोग और बाद में योजना परिव्यय के उपयोग में सुधार के रूख और साथ ही वर्ष 2005-06 से योजना परिव्यय में बढ़ोत्तरी से इस तथ्य की पुष्टि होती है।

7. बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों की स्थिति

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के कुछ वित्तीय दृष्टि से कमजोर उपक्रमों को छोड़कर मंत्रालय द्वारा सरकारी अथवा निजी क्षेत्र के किसी अन्य संगठन अथवा संस्था को कोई बजटीय सहायता/अनुदान मांग उपलब्ध नहीं करवाई गई है। दिनांक 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जारी की गई बजटीय सहायता (योजना तथा गैर-योजना) के संबंध में कोई उपयोग प्रमाण-पत्र दिनांक 31.12.2006 तक लंबित नहीं है।

7. खर्च नहीं किये गये शेष की स्थिति

जैसा ऊपर बताया गया है इस्पात मंत्रालय अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के कुछ वित्तीय दृष्टि से कमजोर उपक्रमों को आवश्यकता के आधार पर बजटीय सहायता उपलब्ध करवाता है। दिनांक 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार उपक्रमों के पास खर्च नहीं किए गए शेष की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए)

वर्ष 2006-07 के अंत में अर्थात 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार खर्च नहीं किया गया शेष	अप्रैल-दिसम्बर, 2007-08 के दौरान जारी की गई धनराशि	अप्रैल-दिसम्बर, 2007-08 के दौरान उपयोग की गई धनराशि	31.12.2007 की स्थिति के अनुसार खर्च नहीं किया गया शेष
16.42	103.22	113.39	6.25

नोट- उपर्युक्त विवरण में गारंटी शुल्क को माफ करने/बट्टे खाते डालने से संबंधित व्यय को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह केवल लेखा समायोजन है और इनसे नकदी बाहर नहीं जाती है।

खर्च नहीं किया गया 6.25 करोड़ रू0 का पूरा शेष मेकॉन लि0 से संबंधित है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए मंजूर पुनरूद्धार पैकेज के तहत मार्च 2007 में 30.00 करोड़ रू0 की धनराशि साम्या निवेश के रूप में मेकॉन को निर्मुक्त की गई थी जबकि इसने दिनांक 31.12.2007 तक 23.75 करोड़ रू0 का उपयोग किया है।

****

अध्याय-VI

इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि0 (सेल)

(1) स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के समग्र नियंत्रणाधीन निम्नलिखित संयंत्र/इकाइयां हैं:-

1. भिलाई इस्पात संयंत्र(बी एस पी)
2. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र(डी एस पी)
3. राउरकेला इस्पात संयंत्र(आर एस पी)
4. बोकारो इस्पात संयंत्र(बी एस एल)
8. इस्को इस्पात संयंत्र(आई एस पी)
9. मिश्र इस्पात संयंत्र (ए एस पी)
10. सेलम इस्पात संयंत्र(एस एस पी)
11. विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात संयंत्र (वी आई एस एल)
9. कच्चा माल प्रभाग (आर एम डी)
10. केन्द्रीय विपणन संगठन (सी एम ओ)
11. लोहा और इस्पात के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आर डी सी आई एस)
12. इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी ई टी)
13. निगमित कार्यालय (सी ओ)

महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मैल्ट लिमिटेड (एमईएल) सेल की एक सहायक कंपनी है जिसमें सेल की 99.12 प्रतिशत शेयर पूंजी है। एमईएल का संयंत्र चंद्रपुर (महाराष्ट्र) में स्थित है और यह कंपनी फैरो मिश्र का उत्पादन करती है।

1.2 सेल की प्राधिकृत पूंजी 5000.00 करोड़ रू0 है। प्रदत्त पूंजी 4130.40 करोड़ रू0 है जिसमें से 3544.69 करोड़ रू0 (85.82 प्रतिशत) भारत सरकार के पास है तथा शेष वित्तीय संस्थानों, जी डी आर धारकों, बैंकों, कर्मचारियों आदि के पास है।

1.3 वित्तीय निष्पादन

(हजार टन)

सं0	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 बजट अनुमान
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसम्बर 07 तक)	
(i)	तप्त धातु	13202	14603	14606	14730	11311	16459
(ii)	अपरिष्कृत इस्पात	12460	13470	13506	13739	10379	15043
(iii)	विक्रेय इस्पात	11317	12051	12581	12530	9600	13692
(iv)	कच्चा लोहा	364	579	509	497	346	1060

1.4 वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रू0))

सं0	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 बजट अनुमान
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसम्बर 07 तक)	
(i)	आय	33235	34839	41419	40425	33108	40704
(ii)	प्रचालन लागत	22138	27458	30453	33421	24187	35299
(ii)	सकल मार्जिन	11097	7381	10966	7004	8921	5405
(iv)	कर पूर्व लाभ (हानि)	9365	5706	9423	5251	7804	3551
(v)	कर पश्चात लाभ (हानि)	6817	4013	6202	3442	5160	2336
(vi)	दिया गया लाभांश/ प्रस्तावित जिसमें से लाभांश का भुगतान किया गया/भारत सरकार को भुगतान करने के लिए प्रस्तावित	1363 1170	826 709	1280 1099	826 709	785 673	826 709

1.5 2002-03 में इस्पात क्षेत्र में मंदी के बाद के वर्षों में सेल के वित्तीय निष्पादन में काफी सुधार हुआ है। 2006-07 में कारोबार 62 प्रतिशत बढ़कर 39189 करोड़ रू0 हो गया जबकि 2003-04 में यह 24178 करोड़ रू0 था। 2006-07 में पी बी टी 258 प्रतिशत बढ़कर 9423 करोड़ रू0 हो गया जबकि 2003-04 में यह 2628 करोड़ रू0 था। 6 वर्ष के अंतर के बाद 2004-05 में लाभांश का भुगतान करना शुरू किया गया और 2004-05 से 2006-07 के दौरान सेल द्वारा 3469 करोड़ रू0 के लाभांश का भुगतान किया जा चुका है जिसमें से 2978 करोड़ रू0 का भुगतान भारत सरकार को किया गया। बाजार पूंजीकरण के जरिये पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा 1 लाख करोड़ रू0 से अधिक की संपत्ति सृजित की गई। ऋण जो 1.4.2004 की स्थिति के अनुसार 8690 करोड़ रू0 थे 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार घट कर 2792 करोड़ रू0 हो गई। सेल वास्तव में ऋण मुक्त कंपनी बन गई है। इसने 2003-04 के 1.87:1 के अनुपात की तुलना में ऋण साम्या अनुपात 0.13 : 1 अनुपात प्राप्त कर लिया है।

2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि0 (आर आई एन एल)

2.1 विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वी एस पी) विशाखापट्टणम में है। यह भारत में स्थापित प्रथम तटीय आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र है। 30 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के द्रव इस्पात के साथ इसे अगस्त, 1992 में चालू किया गया था। यह संयंत्र सघन उर्जा बचत तथा प्रदूषण नियंत्रण उपायों को शामिल करते हुए अद्यतन प्रौद्योगिकी से डिजायन और इंजीनियरी में अंतर्राष्ट्रीय मानको के अनुरूप बनाया गया है।

8692.00 करोड़ रू0 (आधार जून 2005 के मूल्य). की अनुमानित लागत पर कंपनी की क्षमता 3 मिलियन टन वार्षिक द्रव इस्पात से बढ़ाकर 6.3 मिलियन टन वार्षिक करने के लिए भारत सरकार ने 28 अक्टूबर 2005 को अपनी मंजूरी दे दी है। इसे पूरा करने की समय अनुसूचि स्टेज 1 के लिए 36 माह, स्पेशल बार मिल के लिए 45 माह तथा लाईट स्ट्रक्चरल मिल के लिए 48 माह है। परियोजना की संपूर्ण लागत आंतरिक स्रोतों से पूरी की जाएगी (ऋण साम्या अनुपात 1:1) तथा सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं दी जाएगी।

2.2 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार कंपनी की पूंजीगत संरचना में 4889.85 करोउ रू0 साम्या पूंजी तथा 2937.47 करोड़ रू0 की 7 प्रतिशत गैर संचयी शोधनीय तरजीही शेयर पूंजी शामिल है। सभी शेयर भारत सरकार के पास हैं।

2.3 वित्तीय निष्पादन

(हजार टन)

सं0	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 (बजट अनुमान)
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसम्बर 07 तक)	
(i)	तप्त धातु	3920	4153	4046	4100	2943	3950
(ii)	अपरिष्कृत इस्पात	3560	3603	3606	3620	2462	3450

(iii)	विक्रेय इस्पात	3173	3237	3290	3210	2289	3080
(iv)	कच्चा लोहा	273	439	352	416	405	403

2.4 वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रू0)

क्र. सं.	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 (बजट अनुमान)
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसम्बर 07 तक)	
(i)	आय	8778.06	8873.67	9787.78	9837.49	6770.11	11100.13
(ii)	प्रचालन लागत	5507.07	6504.81	7154.90	7787.31	4507.97	8810.13
(ii)	सकल मार्जिन	3270.99	2368.86	2632.88	2050.18	2262.13	2290.00
(iv)	कर पूर्व लाभ (हानि)	2253.76	1889.51	2222.34	1707.49	1992.07	1958.09
(v)	कर पश्चात लाभ (हानि)	2008.09	1252.37	1363.43	1091.63	1247.98	1285.14
(vi)	दिया गया लाभांश/ प्रस्तावित जिसमें से लाभांश का भुगतान किया गया/भारत सरकार को भुगतान करने के लिए प्रस्तावित	(नीचे दिया गया नोट देखें)					

नोट:- कंपनी के 7827.32 करोड़ रू0 के पूंजी आधार में 4889.85 करोड़ रू0 की साम्या तथा 2937.47 करोड़ रू0 के गैर संचयी शोधनीय तरजीही शेयर (एन सी आर पी एस सी) शामिल हैं। एन सी आर पी एस सी भारत सरकार द्वारा भारत सरकार के ऋणों को एन सी आर पी एस सी में परिवर्तित करने को दर्शाता है और ये वित्तीय वर्ष 2010-11 से चरणों में शोधनीय होंगे।कंपनी ने भारत सरकार को 2937.47 करोड़ रू0 की तरजीही शेयर पूंजी के शीघ्र शोधन हेतु अनुरोध किया है जो कंपनी द्वारा अर्जित/अर्जित किये जाने वाले संभावित लाभ में से साम्या पूंजी का लगभग 60 प्रतिशत है। यह प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है इसे ध्यान में रखते हुए लांभाश का भुगतान करने का प्रस्ताव नहीं है।

2.5 कंपनी अपनी निर्धारित क्षमताओं से अधिक पर प्रचालनरत है और समअनुरूपी समझौता ज्ञापन लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक अथवा वित्तीय निष्पादन में कोई कमी नहीं है। आर आई एन एल सितम्बर 2003 में एक ऋणमुक्त कंपनी बन गई है और जनवरी 2006 में इसने सभी संचित हानियाँ समाप्त कर दी हैं।

3. स्पंज आयरन इंडिया लि0 (सिल)

3.1 स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (सिल), प्रदर्शन स्पंज लौह संयंत्र के सफल प्रचालन के पश्चात् अस्तित्व में आया। यह भारत सरकार और आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार की भागीदारी तथा संयुक्त राष्ट्र विकास

कार्यक्रम/संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की सहायता से लोह/लौह अयस्क की ठोस अपचयन प्रक्रिया तथा 100 प्रतिशत गैर कोककर कोयले के आधार पर स्पंज लोहे का उत्पादन करने के लिए स्थापित किया गया है। स्थानीय कच्चे माल और प्रचालन परिस्थितियों के अनुरूप रोटेरी किल्न प्रोसेस के आधार पर स्पंज लोहा संयंत्र में कई सुधार और संशोधन किये गये। इससे प्रौद्योगिकी विकसित करने में सिल को कोई सहायता नहीं मिली परंतु देश में स्पंज लोहा उद्योग के विकास के लिए इससे रास्ता साफ हो गया।

प्रदर्शन संयंत्र के सकल प्रचालन को ध्यान में रखते हुए सिल ने उतनी ही क्षमता का एक दूसरा किल्न स्थापित करके अपनी क्षमता दोगुनी अर्थात 60 हजार टी पी ए कर दी। इस इकाई में अक्टूबर 1985 से नियमित प्रचालन शुरू हुआ।

हाईली मैटेलाईज स्पंज लोहे चूरे की ब्रीकवेटिंग के लिए एक ब्रीकवेटिंग संयंत्र (जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में इस्पात उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं था और बेकार जाता था) अक्टूबर 1987 के दौरान चालू किया गया था। यह इकाई उच्च घनता के ब्रीकवेट्स का उत्पादन करके सफलतापूर्वक प्रचालनरत है।

3.2 कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 66.00 करोड़ रू0 और प्रदत्त पूंजी 65.10 करोड़ रू0 है जिसमें से भारत सरकार के शेयर 98.78 प्रतिशत हैं और शेष शेयर आंध्रप्रदेश सरकार के पास हैं।

3.3 वास्तविकनिष्पादन

(उत्पादन)

क्र0 सं0	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 (बजट अनुमान
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसम्बर 07 तक	
(i)	स्पंज लोहे का उत्पादन	57,501	48,302	55,194	41,900	33,583 @	54,000
(ii)	स्पंज लोहे की बिक्री	58,174	48,215	54,670	41,900	33,082	54,000

@ 2007-08 के समझौता ज्ञापन विशिष्ट प्राचलों में अपेक्षितानुसार संयंत्र में किए गए प्रमुख रख-रखाव कार्यों के कारण 2007-08 की प्रथम छमाही के दौरान वास्तविक निष्पादन प्रभावित हुआ है।

3.4 वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रू0)

क्र. सं.	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 (बजट अनुमान)
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसम्बर 07 तक)	
(i)	आय	66.95	48.18	56.32	57.00	40.09	62.10
(ii)	प्रचालन लागत	52.71	42.52	50.31	50.67	33.44	57.56

(iii)	सकल मार्जिन	16.56	6.92	7.27	7.53	7.55	6.04
(iv)	कर पूर्व लाभ (हानि)	14.24	5.66	6.29	6.33	6.65	4.54
(v)	कर पश्चात लाभ (हानि)	3.93	3.18	4.02	4.20	4.71	1.54
(vi)	दिया गया लाभांश/ प्रस्तावित	1.79	0.65	0.81	0.84	0.75	0.61
	जिसमें से लाभांश का भुगतान किया गया/भारत सरकार को भुगतान करने के लिए प्रस्तावित	1.77	0.64	0.80	0.83	0.74	0.60

4. हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन्स लि0

4.1 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल), जिसका पंजीकृत कार्यालय कोलकत्ता में है, आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्रों के संपूर्ण निर्माण कार्य करनेमें एक सक्षम संगठन के रूप में सरकारी क्षेत्र में सृजित करने के उद्देश्य से निगमित किया गया था। कंपनी ने बोकारो, विजाग और सेलम जैसे इस्पात संयंत्रों की स्थापना से लेकर चालू करने तक के कार्य किए हैं और भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर (इस्को) तथा भद्रावती इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण/विस्तार से सम्बद्ध बड़े-बड़े निर्माण कार्य किए हैं। । इस्पात संयंत्रों में निर्माण संबंधी कार्यकलापों में कमी के चलते कंपनी ने अपने कार्यकलापों का विद्युत, कोयला, तेल एवं गैस जैसे अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया है। इसके अलावा, कंपनी ने सड़क/राजमार्गों, पुलों, बांधों, भूमिगत संचार और परिवहन प्रणाली और उच्च स्तर की आयोजना वाले औद्योगिक तथा बस्ती परिसरों, समन्वय और आधुनिक तकनीकों आदि जैसे अवसंरचना क्षेत्रों में अपने कार्यकलापों का विविधीकरण किया है।

4.2 कंपनी की प्राधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमश: 150 करोड़ रू0 तथा 117.10 करोड़ रू0 है। सभी शेयर भारत सरकार के पास हैं।

4.3 वास्तविक निष्पादन

(करोड़ रू0)

क्र.सं.	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 बजट अनुमान
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसम्बर 07 तक)	
(i)	आर्डर बुकिंग	521.00	430.00	781.00	500.00	695.00	600.00

4.4 वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रू0)

क्र.स.	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 बजट अनुमान
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसम्बर 07 तक)	
(i)	आय	322.31	349.80	433.33	475.00	356.52	550.00
(ii)	प्रचालन लागत	293.63	318.84	403.16	433.00	333.09	511.50
(iii)	सकल मार्जिन (पीबीआईडीटी)	28.68	30.96	30.17	42.00	23.43	38.50
(iv)	कर पूर्व लाभ (हानि)	(-) 94.21	(-) 85.97	(-) 83.50	(-) 69.96	(-) 61.22	(-) 80.70
(v)	कर पश्चात लाभ (हानि)	(-) 94.21	(-) 85.97	(-) 83.50	(-) 69.96	(-) 61.22	(-) 80.70
(vi)	दिया गया लाभांश/ प्रस्तावित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.5 एचएससीएल इस्पात मंत्रालय के अधीन घाटे वाले सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रमों में से एक है (दूसरा उपक्रम बी आर एल है)। कंपनी 1999 में कंपनी के लिए सरकार द्वारा मंजूर पुनरूद्धार/पुनर्संरचना पैकेज के तहत परिकल्पित लाभों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं रही है। भारत सरकार के ऋणों पर ब्याज देयता तथा वी आर एस व्यय कंपनी को हुई हानि का मुख्य घटक है। कंपनी द्वारा सामना की गई कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के फलस्वरूप मार्जिन में कमी होने से इनका वित्तीय निष्पादन भी प्रभावित हुआ है।

5. भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि0 (बीआरएल)

5.1 बी आर एल की स्थापना 22 जुलाई 1974 को की गई थी तथा इसका पंजीकृत कार्यालय बोकारों में है और इसकी निम्नलिखित 4 इकाईयाँ हैं :

(i) भंडारीदह रिफ्रैक्ट्रीज संयंत्र (बीएचआरपी), झारखंड
(ii) रांची रोड रिफ्रैक्ट्रीज संयंत्र (आरआरआरपी), झारखंड
(iii) भिलाई रिफ्रैक्ट्रीज संयंत्र (बी आर पी), छत्तीसगढ़
(iv) इफ्फको रिफ्रैक्ट्रीज संयंत्र (इफ्फको आर पी), झारखंड

यह कंपनी ब्रिक्स और मासेज का उत्पादन करती है और इनकी आपूर्ति मुख्यत: सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को करती है। इसने फ्रांस की पिलब्रिको की सिनागावा रिफ्रैक्ट्रीज कंपनी, जापान सहित विश्व के कई प्रतिष्ठित रिफ्रैक्ट्रीज उत्पादों/अनुसंधान संगठनों के साथ तकनीकी जानकारी करार कर रखा है।

5.2 कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 246.00 करोड़ रू0 है जबकि 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार प्रदत्त पूंजी 229.79 करोड़ रू0 है। सभी शेयर भारत सरकार के पास हैं।

5.3 वास्तविक निष्पादन

(मात्रा एम टी में)

क्र. सं.	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 बजट अनुमान
					बजट अनुमान	वास्तविक दिसम्बर 07 तक	
(i)	उत्पादन*	75107	81679	88793	95000	65004	95000
(ii)	प्रेषण*	73671	79316	87785	95000	61244	95000

* जॉब अंतरण सहित

5.4 <u>वित्तीय निष्पादन</u>

(करोड़ रू0)

क्र0 सं0	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 बजट अनुमान
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसम्बर 07 तक)	
(i)	आय	147.62	174.47	211.97	196.00	143.37	185.13
(ii)	प्रचालन लागत	132.73	159.03	204.43	170.99	132.18	173.13
(iii)	सकल मार्जिन	14.89	15.44	7.54	25.01	11.19	12.00
(iv)	कर पूर्व लाभ (हानि)	(-) 5.21	(-) 7.07	(-) 15.31	15.19	(-) 4.90	(-) 6.85
(v)	कर पश्चात लाभ (हानि)	(-) 5.21	(-) 7.07	(-) 15.31	15.19	(-) 5.08	(-) 6.85
(vi)	दिया गया लाभांश/ प्रस्तावित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

5.5 बी आर एल इस्पात मंत्रालय के अधीन घाटे वाले सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रमों में से एक है (दूसरा उपक्रम एच एस सी एल है)। आधुनिकीकरण की कमी, कम क्षमता उपयोगिता के कारण उत्पादन की उच्च लागत तथा भारत सरकार के ऋणों पर अधिक ब्याज बोझके कारण कंपनी का निष्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है।

बी आर एल का मामला 1992 में बी आई एफ आर को भेजा गया था। 1996-97 तथा 2002-03 में कंपनी के लिए पुनरूद्धार/पुनर्संरचना पैकेज मंजू र किए गए थे। 2006 में इसे पुन: बी आर पी एस ई को भेजा गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बी आर एल का सेल में विलय का प्रस्ताव भी शामिल था। इस समय यह सरकार के विचाराधीन है।

6. मेकॉन लि0

6.1 मेकॉन लिमिटेड, देश में पहला परामर्शी और इंजीनियरी संगठन है जिसे आई एस ओ: 9001 मान्यता प्राप्त है। पिछले कुछ वर्षों में इस्पात क्षेत्र में चक्रीय मांग/निवेश को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों विशेष रूप से तेल और गैस, विद्युत और अवसंरचना में अपने कार्यकलापों का विविधिकरण किया है। मेकॉन लोहा एवं इस्पात, रसायन, रिफाइनरीज तथा पैट्रो रसायनों, विद्युत, सड़क एवं राजमार्गों, रेलवे, जल प्रबंधन, पत्तन एवं बंदरगाह, गैस एवं तेल, पाइपलाइनों, अलौह खनन, सामान्य इंजीनियरिंग, पर्यावरण इंजीनियरिंग तथा संबद्ध/विविधीकृत क्षेत्रों में व्यापक विदेशी अनुभव सहित अग्रणी बहुविधिक डिजाइन, इंजीनियरिंग, परामर्शी और कांट्रैक्टिंग संगठन है। कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों में यू एस ए, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस आदि की प्रतिष्ठित फर्मों के साथ सहयोग करार किया है।

6.2 कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 104.00 करोड़ रू0 है जिसमें से 103.14 करोड़ रू0 प्रदत्त पूंजी है। प्रदत्त पूंजी में से 0.40 करोड़ रू0 के बोनस शेयर वर्ष 1996-97 के दौरान जारी किए गए थे। सभी शेयर भारत सरकार के पास हैं।

6.3 वास्तविक निष्पादन

चूंकि मेकॉन एक परामर्शी संगठन है इसलिए कंपनी का वास्तविक निष्पादन देना संभव नहीं है।.

6.4 वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रू0)

सं0	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 बजट अनुमान
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसम्बर 07 तक)	
(i)	आय	217.62	295.11	396.62	403.50	312.58	444.50
(ii)	प्रचालन लागत	176.13	246.13	345.82	351.40	273.01	389.91
(ii)	सकल मार्जिन	41.49	48.98	50.80	52.10	39.57	54.59
(iv)	कर पूर्व लाभ (हानि)	10.73	19.27	23.38	26.85	21.18	32.71
(v)	कर पश्चात लाभ (हानि)	10.73	16.12	20.38	23.85	18.93	26.71
(vi)	दिया गया लाभांश/ प्रस्तावित जिसमें से भारत सरकार को भुगतान करने के लिए प्रस्तावित लाभांश	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	3.15 3.15

6.5 मेकॉन ने 1997-98 तक लगातार लाभ अर्जित किया। इस्पात क्षेत्र में मंदी, अधिक जनशक्ति तथा कंपनी को प्राप्त होने वाले परामर्शी कार्यों के मूल्य में कमी के कारण इसे 1998-99 से 2003-04 तक हानि हुई। तथापि 2004-05 कंपनी ने 2003-04 के लिए (-) 10.72 करोड़ रू0 के टी पी ए की तुलना में

2004-05 के लिए 10.73 करोड़ रू0 के टी पी ए सहित समग्र परिवर्तन किया। इंजीनियरी और परामर्शी में कारोबार अधिप्राप्ति 2004-05 के दौरान 161.01 करोड़ रू0 से बढ़कर 2006-07 के दौरान 410.97 करोड़ रू0 हो गई जो कंपनी की स्थापना के बाद सबसे अधिक है। सप्लाई/टर्नकी क्षेत्रों में भी कारोबार अधिप्राप्ति में वृद्धि हुई है। पी ए टी 2004-05 में 10.73 करोड़ रू0 से बढ़कर 20.38 करोड़ रू0 हो गया। तथापि कंपनी का निवल मूल्य ऋणात्मक है फिर भी इसने 2003-04 में (-) 257.91 से 2006-07 में (-) 132.31 करोड़ रू0 का पर्याप्त सुधार किया है।

सरकार ने फरवरी, 2007 में 100.72 करोड़ रू0 की लागत पर मेकान के लिए पुनरूद्धार/पुनर्संरचना पैकेज मंजूर किया।

7.0 एम एस टी सी लि0

7.0.1 एम एस टी सी लिमिटेड **को 9 सितम्बर 1964 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित किया गया था और फरवरी 1992 तक यह कार्बन इस्पात, गलन स्क्रैप,स्पंज लोहे/हाट ब्रिकेवेटिड लोहे तथा रि-रोलेबल स्क्रैप** का आयात करने वाली माध्यम एजेंसी थी । यह भंजन के लिए पुराने पोतों के आयात के लिए भी माध्यम एजेंसी थी। जिनका आयात डि-केनेलाइज कर दिया गया और इसे अगस्त 1991 से ओ जी एल के तहत रख दिया गया। यह कंपनी फरवरी 1974 में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि0 (सेल) की सहायक कंपनी बन गई। वर्ष 1982-83 में एम एस टी सी सेल के शेयरों को भारत के राष्ट्रपति के नाम अंतरित करके भारत सरकार की कंपनी में बदल दी गई। अब यह कंपनी ट्रेडिंग कार्यकलाप, ई-कॉमर्स, लौह तथा अलौह स्क्रैप, अधिशेष भंडार जो मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकारी विभागों का है, के निपटान का कार्य कर रही है।

एम एस टी सी लि0 फैरो स्क्रैप निगम लि0 (एफ एस एन एल) जिसके 100 प्रतिशत प्रदत्त साम्या शेयर एम एस टी सी के पास हैं, की धारक कंपनी की भूमिका भी अदा करती है।

7.0.2 एम एस टी सी **की प्राधिकृत शेयर पूंजी 5.00 करोड़ रू0 और प्रदत्त पूंजी 2.20 करोड़ रू0 है जिसमें से लगभग 90 प्रतिशत भारत के राष्ट्रपति के पास है तथा शेष 10 प्रतिशत स्टील फर्नेस एसोसिएशन आफ इंडिया तथा आयरन एंड स्टील स्क्रैप एसोसिएशन आफ इंडिया के सदस्यों और अन्यों के पास हैं। 2.20 करोड़ रू0 की प्रदत्त पूंजी में 1:1 के अनुपात में वर्ष 1993-94 में जारी किए गए बोनस शेयर शामिल हैं।**

7.0.3 वास्तविक निष्पादन

(करोड़ रू0)

सं0	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 बजट अनुमान
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसम्बर 07 तक)	
(i)	विपणन (व्यापार कार्यकलाप)	4765	4552	4235	3300	3542	3700
(ii)	एजेंसी (ई-कॉमर्स सहित)	1077	3211	3495	3550	3042	4000

7.0.4 वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रू0)

सं0	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 बजट अनुमान
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसम्बर 07 तक	
(i)	आय	4960.03	4172.75	3100.06	3390.15	2567.08	3786.00
(ii)	प्रचालन लागत	4894.77	4086.60	3006.66	3324.15	2507.52	3726.00
(iii)	सकल मार्जिन	65.26	86.15	93.40	66.00	59.56	60.00
(iv)	कर पूर्व लाभ (हानि)	64.77	85.70	90.87	65.00	57.92	58.50
(v)	कर पश्चात लाभ (हानि)	38.30	54.68	59.00	42.90	38.45	38.61
(vi)	दिया गया लाभांश/ प्रस्तावित	7.68	10.96	11.88	8.58	--	7.72
	जिसमें से लाभांश का भुगतान किया गया/भारत सरकार को भुगतान करने के लिए प्रस्तावित	6.91	9.86	10.69	7.72	--	6.95

7.1 फैरो स्क्रैप निगम लि0 (एफ एस एन एल)

7.1.1 फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल) पहले एम एस टी सी और मै. हर्सको कारपोरेशन इंक, अमेरिका की एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी थी । जून 2002 में एम एस टी सी द्वारा एम एस हर्सको के धारित 40% साम्या शेयरों का अधिग्रहण करने के बाद यह एम एस टी सी की शत प्रतिशत सहायक कंपनी बन गई है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य सेल, आरआईएनएल और एनआईएनएल के सभी एकीकृत इस्पात संयंत्रों में स्लैग से स्क्रैप प्राप्त करना और आईआईएल इस्पात इंडस्ट्रीज तथा जिंदल स्टील जैसे निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में

प्रचालन करना भी है। कंपनी अग्रणी संगठनों में से एक है जो देश के धातुकर्मीय उद्योगों को विशेषज्ञतायुक्त सेवाएं उपलब्ध करवाती है। कंपनी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित अपनी 10 इकाईयों के जरिये मिल सर्विस सोल्यूशन डिलिवर करने के लिए डिजायन बिल्ट्स, आउन्स तथा मेन्टेन सुविधाएं और अवसरंचना उपलब्ध कराती है।

7.1.2 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी तथा अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी 2.00 करोड़ रू0 है।

7.1.3 वास्तविक निष्पादन

क्र. सं.	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 बजट अनुमान
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसम्बर 07 तक)	
(i)	स्क्रैप की प्राप्ति (लाख एम टी.)	21.74	22.46	22.04	21.00	17.44	21.50
(ii)	उत्पादन का बाजार मूल्य (करोड़ रू0)	956.56	988.24	969.68	924.00	767.52	946.00

7.1.4 वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रू0)

सं0	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 बजट अनुमान
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसम्बर 07 तक)	
(i)	आय	98.18	106.79	110.63	108.70	82.49	122.72
(ii)	प्रचालन लागत	81.39	88.27	95.20	93.09	70.84	103.80
(iii)	सकल मार्जिन	16.79	18.65	15.37	15.61	11.65	18.92
(iv)	कर पूर्व लाभ (हानि)	8.49	8.55	3.08	4.31	2.07	4.53
(v)	कर पश्चात लाभ (हानि)	5.41	5.68	1.26	2.82	1.35	2.94
(vi)	दिया गया लाभांश/ प्रस्तावित#(कर सहित)	1.23	1.29	2.95	0.90	0.00	0.69

सरकार को कोई लाभांश नहीं दिया गया क्योंकि एफ एस एन एल एम एस टी सी लि0 की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है।

7.1.5 एफ एस एन एल का उत्पादन विभिन्न रूपों में स्लैग और स्क्रैप के सृजन पर निर्भर करता है। वर्ष 2004-05 से 2006-07 की अवधि के लिए उत्पादन में वृद्धि विशेष रूप से स्लैग को संभालने के क्षेत्र में वृद्धि होने के कारण एफ एस एन एल की आय में वृद्धि हुई तथापि लाभप्रदत्ता में अनुपातिक रूप से वृद्धि नहीं हुई है। यह आदान लागतों जैसे डीजल, विद्युत, इस्पात, भारी मशीनों के पुर्जो आदि में वृद्धि के कारण हुआ। जबकि बढ़े हुए व्यय की क्षतिपूर्ति के लिए सेवा प्रभार दरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। आदान लागतों में वृद्धि के

बावजूद लागतों को सीमा के भीतर तर्कपूर्ण ढंग से कम करने के लिए कंपनी द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

8. एन एम डी सी लि.

8.1 15 नवम्बर, 1958 को स्थापित एन एम डी सी लि. देश में लौह अयस्क और हीरों का एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है और यह विभिन्न खनिजों जैसे डोलोमाइट, चूना पत्थर, मैंगनेसाईट, टंगस्टन, ग्रेफाईट,टीन आदि के गवेषण विकास और संदोहन में लगी हुई है। एन एम डी सी लि. में आर एंड डी प्रयोगशाला जिसे सैंटर आफ एक्सीलेंस घोषित किया गया है, में किये गये अपने सघन आर एंड डी कार्यो के जरिये फैरिक आक्साईड आयरन पाउडर आदि उच्च मूल्यों उत्पादों के उत्पादन के क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। कंपनी ने तंजानिया में स्वर्ण का गवेषण कार्य भी किया है। एन एम डी सी की बड़ी यंत्रीकृत लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में बेलाडिला 14/11 सी, बैलाडिला 5/10 तथा 11 ए और कर्नाटक में दोणइमल्ली में,पन्ना मध्यप्रदेश में भारत की यंत्रीकृत हीरा खान तथा लालापुर(इलाहाबाद) में सिलिकासेंड का प्रचालन करती है।

एन एम डी सी लि. का बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए प्रमुख विस्तार करने का प्रस्ताव है। बेलाडिला में निक्षेप 11 बी, दोणिमलई में कुमारस्वामी खान, नागरनार में स्पंज लोहा संयंत्र, कर्नाटक में विंडमिल परियोजनाएँ प्रगति पर हैं।

8.2 150.00 करोड़ रू0 की प्राधिकृत शेयरपूंजी की तुलना में अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी 132.16 करोड़ रू0 है जिसमें से 98.38 प्रतिशत शेयरपूंजी भारत सरकार के पास है।

8.3. वास्तविक निष्पादन

सं0	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 बजट अनुमान
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसम्बर 07 तक)	
(i)	**उत्पादन:**						
	लौह अयस्क (लाख एम टी)	207.43	229.23	262.31	250.00	201.04	280.00
	हीरे (कैरट)	78217	43878	1703	-	-	-
(II)	**बिक्री**						
	लौह अयस्क (लाख एम टी)	232.22	248.45	255.89	260.00	198.58	285.00
	हीरे (कैरट)	86257	48825	14588	-	2632	-

8.4 वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रू0

सं0	मद	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09

		वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक (दिसम्बर 07 तक)	बजट अनुमान
(i)	आय	2331.52	3915.27	4534.04	4583.15	4316.85	5521.23
(ii)	प्रचालन लागत	1040.23	1025.38	952.25	987.41	879.36	1354.48
(ii)	सकल मार्जिन (1-2)	1291.29	2889.89	3581.79	3595.74	3437.49	4166.75
(iv)	मूल्य ह्रास/डी आर ई	67.64	119.76	83.48	66.36	48.07	66.75
(v)	कर पूर्व लाभ (हानि)	1223.65	2770.13	3498.31	3529.38	3389.42	4100.00
(vi)	कर पश्चात लाभ (हानि)	755.44	1827.80	2320.21	2341.39	2234.01	2706.00
(vii)	दिया गया लाभांश/ प्रस्तावित जिसमें से लाभांश का भुगतान किया गया/भारत सरकार को भुगतान करने के लिए प्रस्तावित	151.32 148.88	365.57 359.66	465.19 457.67	-- --	437.45 430.38	-- --

8.5 एन एम डी सी लि. का वास्तविक और वित्तीय निष्पादन पिछले कई वर्षों में लगातार अच्छा रहा है जो कंपनी के विभिन्न वित्तीय प्राचलों जैसे पी बी टी, पी ए टी, लाभांश आदि में प्रगामी रूप से वृद्धि में दिखाई देता है। लौह अयस्क का बिक्री मूल्य 2003-04 में 1411.49 करोड़ रू0 से बढ़कर 2006-07 में 4170.92 करोड़ रू0 हो गया जो 196 प्रतिशत अधिक है। 2003-04 के लिए पी बी टी की तुलना में 2006-07 में 3498.31 करोड़ रू0 की पी बी टी हुई जो 468 प्रतिशत अधिक है। 2006-07 में घोषित 465.19 करोड़ रू0 का लाभांश साम्या का 352 प्रतिशत था । सरकार का शेयर 457.67 करोड़ रू0 था जबकि 2005-06 में यह 359.66 करोड़ रू0 था। वर्ष 2007-08 (31.12.2008 तक) कंपनी द्वारा 437.45 करोड़ रू0 लाभांश का भुगतान किया गया है जिसमें से भारत सरकार को 430.38 करोड़ रू0 का भुगतान किया गया है। सरकार

सरकार द्वारा 23.2.2008 को एन एम डी सी लि. को नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है।

9. <u>कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेउ (केआईओसीएल)</u>

9.1 लौह अयस्क सांद्रण के निर्यात हेतु कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड को अप्रैल, 1976 में बनाया गया। नेशनल नेशनल इरानियन स्टील इंडस्ट्रीज कंपनी के साथ हस्ताक्षरित एक करार के तहत 21 वर्षों की अवधि, जो 1 सितंबर, 1980 से आरंभ होती है, तक कुल 150 मिलियन टन सांद्रण की आपूर्ति ईरान को जानी थी। ईरान ने इसके कार्यान्वयन लागत, 630 मिलियन टन अमेरिकी डॉलर तक, को पूरा करने पर सहमति दी थी। इसमें से केवल 255 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए गए थे। तथापि, इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा दिए गए निधि से पूरा किया गया। इस परियोजना को पूर्ति की अंतिम लागत, 546.30 करोड़ रूपए की अनुमानित स्वीकृत लागत की तुलना में 516.89 करोड़ रूपए थी।

चूंकि करार के अनुसार ईरान लौह अयस्क सांद्रण उठाने में सक्षम नहीं था इसलिए सांद्रण के लिए नए बाजार तलाश करने के अलावा 3 मिलियन टन सांद्रण का उपयोग करने के लिए मई, 1981 में भारत सरकार ने एक पैलेट संयंत्र का नियंत्रण करने के लिए एक योजना अनुमोदन किया है। इस परियोजना को 116.65 करोड़ रूपए की लागत पर कार्यान्वित किया गया वाणिज्यिक उत्पादन अप्रैल, 1987 में शुरू हुआ था। लौह अयस्क पैलेट को इस्पात इंडस्ट्रीज तथा आरआईएनएल जैसी घरेलू इकाइयों को आपूति की जाती है तथा चीन को भी इसका निर्यात किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 31.12.2005 से कुद्रेमुख में खनन कार्य रोकने के निर्णय के परिणामस्वरूप पैलेट संयंत्र का प्रचालन बोट आउट हैमेटाइट अयस्क से किया जाता है।

9.2 केआईओसीएल की प्राधिकृत पूंजी 675.00 करोड़ रूपए है। जारी एवं प्रदत्त पूंजी 634.51 करोड़ रूपए है जिसका लगभग 99 प्रतिशत (628.14 करोड़ रूपए) भारत सरकार के पास है।

9.3 वास्तविक निष्पादन

(उत्पादन - मिलियन टन)

संख्या	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 (बजट अनुमान)
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसंबर, 07 तक)	
(i)	सांद्रण संयंत्र	4.350	2.922	--	--	--	--
(ii)	पैलेट संयंत्र	3.795	2.834	0.630	2.100	1.561	2.700
(iii)	धमन भट्टी इकाई	--	--	--	0.167	0.116	0.180

नोट: (i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31.12.2005 से खनन कार्य बंद कर दिया है।

(ii) दिनांक 1.4.2007 से किस्को का केआईओसलएल में विलय कर दिया है इसलिए वर्ष 2007-08 के आंकड़ों में धमन भट्टी इकाई भी शामिल है।

9.4 वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रूपए)

संख्या	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 (बजट अनुमान)
					बजट अनुमान *	वास्तविक (दिसंबर, 07 तक)	
(i)	आय	1866.70	1301.63	368.87	1191.54	1050.39	1973.24
(ii)	प्रचालन लागत	658.07	614.57	317.05	1112.36	952.35	1837.70
(iii)	सकल मार्जिन	1208.63	687.06	51.81	79.18	98.04	135.54
(iv)	कर पूर्व लाभ/हानि	1111.91	548.10	19.94	41.33	56.11	93.72
(v)	कर-पश्चात लाभ/हानि	649.84	356.30	13.77	27.39	37.63	61.87

(vi)	प्रदत्त/प्रस्तावित लाभांश जिसमें से	130.08	126.90	शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
	भारत सरकार को प्रदत्त/प्रस्तावित लाभांश	128.77	125.63	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

***** दिसंबर, 2007 तक

नोट : पर्याप्त लाभ न होने के कारण वर्ष 2006-07 के लिए किसी लाभांश का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

9.5 जैसाकि उल्लेख किया जा चुका है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केआईओसीएल को दिनांक 31.12.2005 से कुद्रेमुख में उत्खनन कार्य रोकने के लिए निदेश दिए हैं तदनुसार कुद्रेमुख में उत्खनन रोक दिया गया है जिससे कुद्रेमुख से मैग्नेटाइट अयस्क की आपूर्ति रूक गई तथा इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 के बाद बाद सांद्रण तथा पैलेट दोनों के उत्पादन में गिरावट औई। इससे कंपनी के वास्तविक एवं वित्तीय दोनों निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सांद्रण संयंत्र को बंद करना पड़ा इसलिए कंपनी हैमेटाइट अयस्क से पैलेट का उत्पादन करने के लिए पैजेट संयंत्र के प्रक्रमण आवश्यक संशोधन करने पड़े। पैलेट संयंत्र का प्रचालन स्टैबलीजेशन अधिक है।

10. मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

10.1 मॉयल जिसका गठन 1962 में कया गया था, उच्च ग्रेड के मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा घरेलू उत्पादक है जो फैरो मिश्र, इस्पात निर्माण में एक महत्वपूर्ण आदान है। डाई-ऑक्साइड का उत्पादन कंपनी की डोंगरी बुजुर्ग खान में किया जाता है। उच्च ग्रेड के मैंगनीज ओर डाई-ऑक्साइड अयस्क की घरेलू मांग में वृद्धि से कंपनी ने अपनी खानों को विसित करने तथा इनका आधुनिकीकरण करने के लिए विभिन्न पूंजीगत योजनाओं पर बल दिया है। इसके अलावा करोबार की मात्रा तथा लाभ प्रदता में सुधार करने के लिए मॉयल ने अपनी गतिविधियों को 90 के दशक के दौरान मूल्यवर्द्धित उत्पादों के निर्माण में वर्गीकृत किया है। वर्गीकरण के रूप में कंपनी ने वर्ष 1991 में इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाई-ऑक्साइड के निर्माण के लिए एक परियोजना स्थापित की है जिसकी प्रारंभिक प्रतिस्थापित क्षमता 600 एमटी प्रति वर्ष है तथा जिसे वर्ष 2006-07 में चरणबद्ध तरीके से 1500 एमटी प्रति वर्ष तक बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1098 के दौरान मध्य प्रदेश में बालाघाट में मॉयल ने 5 एमवीए क्षमता वाला एक फैरो मैंगनीज संयंत्र, जिसकी प्रारंभिक क्षमता 10000 एमटी प्रति वर्ष है, की स्थापना की है। कंपनी ने मध्य प्रदेश में 4.8 एमडब्ल्यू वाली एक विंड पावर यूनिट की भी स्थापना की है जिसका उपयोग मध्य प्रदेश में स्थित फैरो मैंगनीज संयंत्र और खानों की विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। 15.2 एमडब्ल्यू वाली विंड पावर यूनिट का दूसरा चरण प्रगति पर है तथा कार्य मार्च, 2008 के दौरान इसे चालू किए जाने का अनुमान है।

10.2 कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 30.00 करोड़ रूपए है तथा 31 मार्च, 2007 के अंत तक कंपनी की प्रदत्त एवं चुकता पूंजी 28.00 करोड़ रूपए है। भारत सरकार तथा महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकार कंपनी के शेयर धारक हैं जिसमें भारत सरकार के 81.57 प्रतिशत शेयर हैं।

10.3 वास्तविक निष्पादन

(उत्पादन एमटी)

क्र. संख्या	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 (बजट अनुमान)
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसंबर, 07 तक)	
(i)	मैंगनीज ओर	943169	864890	1047021	950000	940185	1106000
(ii)	इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाई-ऑक्साइड	1123	1301	1312	1300	774	1400
(iii)	फैरो मैंगनीज	10325	6170	10200	10000	8270	10000

10.4. वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रूपए)

क्र. संख्या	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 (बजट अनुमान)
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसंबर, 07 तक)	
(i)	आय	375.82	356.19	451.82	351.47	529.57	583.36
(ii)	प्रचालन लागत	205.44	193.92	221.59	246.02	211.13	303.45
(iii)	सकल मार्जिन	210.65	179.47	210.21	175.00	324.82	297.12
(iv)	कर-पूर्व लाभा/हानि	202.27	169.00	201.15	150.00	311.32	271.74
(v)	कर-पश्चात लाभ/हानि	126.90	114.52	134.21	99.51	205.50	179.38
(vi)	प्रदत्त/प्रस्तावित लाभांश	9.20	19.92	28.00	5.83	36.40 *	16.23
	जिसमें से:						
	भारत सरकार को प्रदत्त/प्रस्तावित लाभांश	7.50	16.25	22.84	--	29.69 *	--

* जून, 2008 के अंतिम माह के दौरान प्रदत्त वर्ष 2007-08 के लिए अंतरिम लाभांश

11. बर्ड ग्रुप कंपनियां

बर्ड ग्रुप की कंपनियां कोई सरकारी उपक्रम नहीं हैं वरन इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एवं सरकारी प्रबंधन वाली कंपनी है। इसमें निम्नलिखित पांच प्रचालनात्मक कंपनियां शामिल हैं :

(1) द उड़ीसा मिनरल डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी)
(2) द बिरसा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी)
(3) द कर्णपुरा डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (केडीसीएल)
(4) स्कॉट एंड सेक्सबी लिमिटेड (एसएएल),
(5) इस्टर्न इन्वेस्टमेंट कंपनी लि. (ईआईएल)

ओएमडीसी, बीएसएलसी तथा केडीसीएल उत्खनन कंपनियां हैं जबकि एसएसएल गहरे नलकूप खोदने तथा खनिज उत्खनन से संबंधित कार्यों में लगी है। ईआईएल एक निवेश कंपनी है और प्रमुख शेयरधारिता ओएमडीसी, बीएसएलसी और केडीसीएल के पास है।

11.1 द उड़ीसा मिनरल डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी)

वर्ष 1918 में एकीकृत ओएमडीसी लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के उत्खनन तथा विपणन के कार्य में लगी है। कंपनी की खानें उड़ीसा के कौझार जिले में बारबील के निकट स्थित है। वर्ष 2004 के दौरान ओएमडीसी ने 30,000 टीपीए क्षमता वाला स्पंज लोहा संयंत्र को स्थापित किया है। कंपनी की प्राधिकृत एवं चुकता पूंजी 0.60 करोड़ रूपए है।

11.1.1 वास्तविक निष्पादन

(लाख एमटी)

क्र. सं.	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 (बजट अनुमान)
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसंबर, 07 तक)	
1.	**उत्पादन**						
	आयरन ओर	31.75	23.62	22.30	26.52	12.47	18.24
	मैंगनीज अयस्क	0.42	0.35	0.27	1.00	0.60	0.88
	स्पंज लोहा	0.19	0.19	0.11	0.20	0.08	0.18
2.	**प्रेषण**						
	आयरन ओर	28.94	22.17	21.16	26.32	12.23	17.94
	मैंगनीज अयस्क	0.34	0.30	0.39	1.00	0.61	0.88
	स्पंज लोहा	0.14	0.18	0.05	0.20	0.12	0.18

11.1.2 वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रूपए)

क्र. सं.	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 (बजट अनुमान)
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसंबर,07 तक)	
(i)	आय	305.79	276.94	338.39	443.64	196.86	437.66
(ii)	प्रचालन लागत	72.37	84.08	75.48	93.65	46.17	85.62
(iii)	सकल मार्जिन	233.42	192.86	262.91	349.99	152.94	352.04
(iv)	कर-पूर्व लाभ/हानि	230.15	188.88	258.99	343.49	147.39	343.94
(v)	कर-पश्चात लाभ/हानि	145.55	129.93	173.47	226.74	97.85	226.79
(vi)	प्रदत्त/प्रस्तावित लाभांश	21.84	19.50	26.02	-	-	34.02
	जिसमें से:						
	भारत सरकार को प्रदत्त/प्रस्तावित लाभांश	3.10	2.77	3.70	-	-	4.83

बर्ड ग्रुप कंपनियों में ओएमडीसी एकमात्र लाभ कमाने वाली कंपनी है। वर्ष 2003-04 से कंपनी लगातार लाभ कमा रही है। तथा चालू वित्तीय वर्ष 2007.08 में भी बढ़िया लाभ कमाना जारी रखा है। वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ कंपनी ने समस्त बकाया सरकारी ऋण तथा ववर्ष 2003-04 के दौरान इस पर ब्याज का भुगतान कर दिया। अब कंपनी बिना किसी ऋण के कार्य कर रही है। तथापि, ओएमडीसी की वर्गीकृत

योजनाओं में उन तीन खनन पट्टों जो लौह अयस्क निक्षेपों के भंडार हैं, के नवीकरण की अनिश्चितता के कारण अड़चनें आ रही हैं।

11.2 द बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी)

बीएसएलसी का गठन वर्ष 1910 में किया गया था। कंपनी का प्रमुख कार्य चूना पत्थर और डोलोमाइट का उत्खनन तथा विपणन करना है। इसकी खानें उड़ीसा में सुन्दरगढ़ जिले में बिरमितरापुर में स्थित है। बीएसएल की प्राधिकृत एवं चुकता पूंजी 0.50 करोड़ रूपए है।

11.2.1 वास्तविक निष्पादन

(लाख एमटी)

क्र. सं.	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 (बजट अनुमान)
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसंबर, 07 तक)	
1	**उत्पादन**						
	लाइम स्टोन	1.87	2.14	2.58	4.08	2.04	4.49
	डोलोमाइट	6.09	7.41	7.04	6.72	6.28	7.39
2	**प्रेषण**						
	लाइम स्टोन	1.64	2.00	2.17	4.08	1.66	4.49
	डोलोमाइट	6.18	6.95	7.08	6.72	6.29	7.39

11.2.2 वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रूपए)

क्र.सं.	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 (बजट अनुमान)
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसंबर, 07 तक)	
(i)	आय	24.41	36.20	40.66	44.50	33.22	49.00
(ii)	प्रचालन लागत	25.78	38.58	35.98	41.00	31.24	44.50
(iii)	सकल मार्जिन	(-) 2.15	(-) 2.66	4.52	3.50	1.98	4.50
(iv)	कर-पूर्व लाभ/हानि	(-) 54.99	(-) 64.13	(-) 66.63	(-) 73.00	(-) 55.35	(-) 89.00
(v)	कर-पश्चात लाभ/हानि	(-) 54.95	(-) 64.12	(-) 66.65	(-) 73.00	(-) 55.35	(-) 89.00
(vi)	प्रदत्त/प्रस्तावित लाभांश	-	-	-	-	-	

पिछले कुछ वर्षों में से बीएसएलसी हानि में चल रही है। कंपनी के निष्पादन पर इस्पात निर्माण प्रौद्योगिकी फेरबदल, औद्योगिक संबंधी समस्याओं तथा विभिन्न मांग संबंधी अड़चनों ने प्रभाव डाला जिससे काफी नकदी हानि हुई चूंकि कंपनी का चुकता पूंजी केवल 0.50 करोड़ रूपए है इसलिए दिनांक 31.3.2007 के अनुसार कंपनी की संबंधित हानि 529 करोड़ रूपए है। बकाया सरकारी ऋण तथा इस पर ब्याज दोनो

मिलाकर 530 करोड़ रूपए से अधिक का ऋण साम्या दर में भी आश्चार्यजनक वृद्धि हुई है। जनशक्ति में काफी कमी से मौजूदा 1221 कर्मचारी अभी भी अधिशेष हैं और इसमें और कमी करने की आवश्यकता है।

11.3 कर्णपुरा डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (केडीसीएल)

केडीसीएल का गठन वर्ष 1920 में हुआ था प्रारंभ में कंपनी का काम रिफ्रैक्ट्री खनिजों के उत्पादन तथा विपणन के आस-पास केंद्रित था। भारी हानि के चलते कंपनी का रिफ्रैक्ट्री कार्य रोक दिया गया तथा सिमेंट ग्रेड के चूना पत्थर का उत्पादन तथा विपणन करके इसको खनन खंडों में प्रचालन शुरू किया। कंपनी की खानें बिहार में सिरका के निकट स्थित हैं। कंपनी की प्राधिकृत एवं चुकता पूंजी क्रमश: 0.40 करोड़ रूपए तथा 0.20 करोड़ रूपए रहा है।

11.3.1 वास्तविक निष्पादन

(लाख एमटी)

क्र.सं.	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 (बजट अनुमान)
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसंबर, 07 तक)	
1	**उत्पादन**						
	लाइम स्टोन	0.79	0.77	0.67	0.90	0.41	0.75
2	**प्रेषण**						
	लाइम स्टोन	0.78	0.78	0.65	0.90	0.44	0.75

11.3.2 वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रूपए)

क्र.सं.	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 (बजट अनुमान)
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसंबर, 07 तक)	
(i)	आय	1.93	1.99	1.87	2.57	1.21	2.15
(ii)	प्रचालन लागत	1.88	1.94	2.06	2.45	1.29	2.11
(iii)	सकल मार्जिन	0.04	0.04	(-) 0.19	0.12	(-) 0.09	0.04
(iv)	कर-पूर्व लाभ/हानि	(-) 1.35	(-) 1.63	(-) 2.21	(-) 2.17	(-) 1.88	(-) 2.92
(v)	कर-पश्चात लाभ/हानि	(-) 1.35	(-) 1.63	(-) 2.21	(-) 2.17	(-) 1.88	(-) 2.92
(vi)	प्रदत्त/प्रस्तावित लाभांश	-	-	-	-	-	

पिछले कुछ वर्षों से केडीसीएल भी हानि उठा रही है। दिनांक 31.3.2007 के अनुसार कंपनी की संचित हानि 12.35 करोड़ रूपए थी। दिनांक 31.3.2007 के अनुसार कंपनी का 1.35 करोड़ रूपए का सरकारी ऋण तथा 10.09 करोड़ रूपए का इस ऋण पर ब्याज केडीसीएल में बकाया है। उत्खनन में विभागीय कामगारों में अनुभव की कमी के चलते कंपनी का लीज होल्ड खानों को कोई अधिकार नहीं होगा तथा लघु

खान स्वामित्व के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण भूमि स्वामित्व की समस्या से केडीसीएल के उत्पादों की मांग में कमी आई है तथा इससे कंपनी के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

11.4 स्कॉट एंड सेक्सबी लिमिटेड (एसएसएल)

एसएसएल की स्थापना 1924 में की गई थी तथा यह पूर्ण रूप से केडीसीएल के स्वामित्व वाली गौण कंपनी है। कंपनी के प्रचालन का क्षेत्र गहरे नलकूप खोदना तथा खनिज उत्खनन है। एसएसएल की प्राधिकृत एवं प्रदत्त पूंजी 0.05 करोड़ रूपए है।

11.4.1 वास्तविक निष्पादन

एसएसएल के प्रचालन की प्रकृति के कारण कंपनी का वास्तविक निष्पादन देना संभव नहीं है।

11.4.2 वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रूपए)

क्र.सं.	मद	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08		2008-09 (बजट अनुमान)
					बजट अनुमान	वास्तविक (दिसंबर, 07 तक)	
(i)	आय	1.71	1.65	1.05	2.24	0.74	2.24
(ii)	प्रचालन लागत	1.75	2.73	4.16	2.16	1.35	2.20
(iii)	सकल मार्जिन	(-) 0.06	(-) 1.17	(-) 3.11	8.00	(-) 0.61	0.04
(iv)	कर-पूर्व लाभ/हानि	(-) 7.21	(-) 9.78	(-) 13.47	(-) 13.46	(-) 10.77	(-) 16.79
(v)	कर-पश्चात लाभ/हानि	(-) 7.21	(-) 9.78	(-) 13.47	(-) 13.46	(-) 10.77	(-) 16.79
(vi)	प्रदत्त/प्रस्तावित लाभांश	-	-	-	-	-	

पिछले कुछ वर्षों से एसएलसी भी लगातार हानि उठा रही है। कंपनी की यह कमजोरी इसके पुराने और जर्जर उपस्करों और स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के जरिए जनशक्ति को सही आकार देने के बाद भी अत्यधिक जनशक्ति होने के कारण है। एक अन्य अड़चन गहरे नलकूप खोदने के लिए आर्डरों की कमी इस शन्य निष्पादन के कारण एसएसएल गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है जिससे इसके वेतन एवं मजदूरी भी बकाया होने के साथ इसकी सांविधिक देयताओं में शामिल है। भविष्य में इसकी आर्डर बुक की स्थिति में सुधार करने की संभावना नहीं है। दिनांक 31.3.2007 के अनुसार कंपनी की संचित हानि 64.90 करोड़ रूपए थी तथा कंपनी 60.15 करोड़ रूपए के भारत सरकार के ऋण तथा इस पर ब्याज का भुगतान भी नहीं कर पाई है।

****